

## छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

[छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2005 के अंतर्गत स्थापित]

### राजपत्रों का संकलन निम्नानुसार :-

- ▶ छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2005
- ▶ छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम - 2005
- ▶ छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधित अधिनियम-2006
- ▶ छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधित अधिनियम-2006
- ▶ छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधित अधिनियम-2008
- ▶ छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधित अधिनियम-2008
- ▶ छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधित अधिनियम-2010
- ▶ छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधित अधिनियम-2011

## छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

मधु पिल्ले घौक, राम मंदिर के सामने, शांति नगर, रायपुर

दूरभाष : 0771-2446018, फैक्स : 0771-4070131

## छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

[छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2005 के अंतर्गत स्थापित]



### राजपत्रों का संकलन

#### छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

मधु पिल्ले चौक, राम मंदिर के सामने, शांति नगर, रायपुर

दूरभाष : 0771-2446018, फैक्स : 0771-4070131

"विजेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नाम भूगतन (विना डाक टिकट) के ऐवण हेतु अनुमति, क्रमांक नं. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. मिलाई, दिनांक 30-5-2001।"



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/  
सी. ओ./रायपुर/17/2002।"

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 193 ]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 25 अगस्त 2005—भाइ 3, शक 1927

विधि और विधायी कार्य विभाग  
मंत्रालय, दाक कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2005

क्रमांक 6886/21-अ/प्रारपण/04.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 17-8-2005 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विमल सिंह कपूर, उप-सचिव,

## छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 13 मई 2005)

## छत्तीसगढ़ निवी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005

## विषय सूची

खण्ड :

## अध्याय - 1

## प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ
2. परिभाषाएं

## अध्याय - 2

## निवी विश्वविद्यालय की स्थापना

3. निवी विश्वविद्यालय के उद्देश्य
4. निवी विश्वविद्यालय स्थापना के प्रस्ताव का प्रेषण
5. प्रस्ताव का मूल्यांकन
6. आशाव पत्र जारी करना
7. निवी विश्वविद्यालय की स्थापना की शर्तें
8. परिपालन प्रतिवेदन की प्रस्तुति, सत्यापन तथा निरीक्षण
9. स्थापना तथा निगमन

## अध्याय - 3

## निवी विश्वविद्यालय का संचालन एवं प्रबंधन

10. स्ववितीय निवी विश्वविद्यालय
11. विन्यास निधि
12. सामान्य निधि
13. सामान्य निधि का उपलब्धीकरण
14. विश्वविद्यालय के अधिकारी
15. कुलाध्यक्ष
16. कुलाधिपति
17. कुलपति
18. कुल सचिव
19. मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी
20. अन्य अधिकारी
21. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी
22. शासी निकाय
23. प्रबंध मंडल

24. सौक्षणिक परिषद्
25. अन्व प्राधिकरण
26. प्रथम परिनियम
27. अनुगमी परिनियम
28. प्रथम अध्यादेश
29. अनुगमी अध्यादेश
30. रिक्षायां, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी की कार्यवाही की अवैधता का कारण नहीं
31. आपात रिक्षायों की पूर्ति
32. समिति
33. विश्वविद्यालय अभिलेख, साक्ष वा उपकरण
34. विनियम
35. परिनियम, अध्यादेश और विनियम की प्रभावशीलता

#### अध्याय - 4

##### निजी विश्वविद्यालय का विनियम

36. विनियामक आयोग
37. वार्षिक प्रतिवेदन
38. नार्तिक लेखा एवं गांगीषा
39. नियतकालिक निरीक्षण

#### अध्याय - 5

##### निजी विश्वविद्यालय का परिसमाप्त

40. प्रायोजक रिक्षाय के विषट्टन होने पर विश्वविद्यालय का प्रबंधन
41. कालिपय परिच्छितियों में राज्य शासन की विशेष शक्तियाँ

#### अध्याय - 6

##### प्रक्षीण

42. नियम बनाने की शक्ति
43. कठिनाईयों के निराकरण की शक्तियाँ
44. निरसन एवं व्यावृति
- अनुसूची

छत्तीसगढ़ अधिनियम  
(क्रमांक 13 सं. 2005)

**छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005**

छत्तीसगढ़ राज्य में उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु स्वविरोध विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं नियमन के लिए तथा उनके क्रियाकलापों के नियमन एवं तत्संबंधी विधयों या आनुचांगिक विधयों के लिए अधिनियम,

भारत गणराज्य के छापनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विभानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

**अध्याय - एक : प्रारंभिक**

लैंपिक नाम, विस्तार एवं प्रारंभ.

1. (1) इस अधिनियम का संशिप्त नाम छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 है।
  - (2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा।
  - (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।
2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ द्वारा असेहित न हो, -
  - (1) “शैक्षणिक परिषद्” से अभिवेत है, निजी विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद्,
  - (2) “अधिकारी भारतीय लकड़ीकी शिक्षा परिषद्” से अभिवेत है, अधिकारी भारतीय लकड़ीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (केन्द्रीय अधिनियम 1987 की संख्या 52) के अधीन स्थापित अधिकारी भारतीय लकड़ीकी शिक्षा परिषद्,
  - (3) “भारतीय विधिक परिषद्” से अभिवेत है, इडलोकेट एवट 1961 (क्र. 25 सं. 1961) की धारा 4 के अधीन गठित भारतीय विधिक परिषद्,
  - (4) “प्रबंधन मञ्चल” से अभिवेत है, निजी विश्वविद्यालय का प्रबंधन मण्डल,
  - (5) “कुलाधिपति” से अभिवेत है, निजी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति,
  - (6) “मुख्य लेखा एवं वित्त अधिकारी” से अभिवेत है, निजी विश्वविद्यालय के मुख्य लेखा एवं वित्त अधिकारी,
  - (7) “दूसर्य शिक्षा परिषद्” से अभिवेत है - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम 1985 (क्र. 50 सं. 1985) की धारा 28 के अधीन स्थापित दूसर्य शिक्षा परिषद्,
  - (8) “विन्यास निधि” से अभिवेत है, निजी विश्वविद्यालय की विन्यास निधि,
  - (9) “मुक्त” से अभिवेत है, विद्यार्थियों से निजी विश्वविद्यालय द्वारा संकलित राशि, जहाँ उसे किसी भी नाम से मुकाबा जावे।
  - (10) “शासन” से अभिवेत है, छत्तीसगढ़ शासन।

- (11) "राज्यपाल" से अभिषेत है, छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल.
- (12) "शासी निकाय" से अभिषेत है, निजी विश्वविद्यालय का शासी निकाय.
- (13) "उच्च विद्या" से अभिषेत है, झाराबांव के लिए 10+2 स्तर से आगे निर्धारित पाद्यक्रम अध्ययन पाद्यसंरचना का अध्ययन.
- (14) "मेडिकल कौसिल ऑफ इंडिया" से अभिषेत है, इंडियन मेडिकल कौसिल एक्ट 1956 (क्र. 2, सद् 1956) के अधीन गठित मेडिकल कौसिल ऑफ इंडिया.
- (15) "मुख्य परिसर" से अभिषेत है, छत्तीसगढ़ राज्य की भीमा में स्थित निजी विश्वविद्यालयों के मुख्य परिसर, विनके कम से कम पांच अध्यायन विभाग अध्ययन शालाएं हों और वहाँ कुलपर्याप्त एवं कुलमात्रिक विभाग करते हों तथा निजी विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यालय भी स्थित हो.
- (16) "नेशनल कौसिल ऑफ एसेमेण्ट एण्ड एकेडेमेन्ट" से अभिषेत है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्वयंसमीकरण नेशनल कौसिल ऑफ एसेमेण्ट एण्ड एकेडेमेन्ट, मैगलौर.
- (17) "दूर परिसर केन्द्र" से अभिषेत है, निजी विश्वविद्यालय का ऐसा केन्द्र जो मुख्य परिसर से बहार बिन्दु राज्य के भीतर हो तथा विभिन्न संचालन एवं संभारण विश्वविद्यालय की इकाई ने एवं में होता हो।
- (18) "भाग्यारेषा" से अभिषेत है, निजी विश्वविद्यालय का आयोग.
- (19) "अन्य पिलड़ा वर्ग" से अभिषेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा घोषित अन्य पिलड़ा वर्ग।
- (20) "निजी विश्वविद्यालय" से अभिषेत है, इस अधिनियम के अधीन स्थापित एवं संचालित निजी विश्वविद्यालय.
- (21) "कार्म सी कौसिल ऑफ इंडिया" से अभिषेत है, कार्म सी अधिनियम 1948 (क्र. 8, सद् 1948) के अधीन गठित कार्म सी कौसिल ऑफ इंडिया.
- (22) "नियामक अधिकारी" से अभिषेत है, केन्द्र शासन अध्ययन प्राविधिक विनियम के अन्तर्गत नियामक अधिकारी जो उच्च विद्या के मानक स्तर को सुनिश्चितता के लिए नियम व शर्तें निर्धारित करे।
- (23) "विनियामक आयोग" से अभिषेत है, इस अधिनियम की धारा 36 के अधीन स्थापित विनियामक आयोग.
- (24) "विनियमन" से अभिषेत है, इस अधिनियम के प्राविधिकों के अधीन निर्दिष्ट विनियमन.
- (25) "कुल संघिव" से अभिषेत है, निजी विश्वविद्यालय का कुल संघिव.
- (26) "एन्व" से अभिषेत है, छत्तीसगढ़ राज्य.
- (27) "अध्ययन केन्द्र" से अभिषेत है, दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में विद्यार्थियों को परामर्श, बंत्रण या अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से निजी विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित, संघारित या मान्यता प्राप्त केन्द्र जो लोई दो या दो से अधिक संचार माध्यमों द्वारा रोडट्रो

प्रसारण, दूरदर्शन, पत्राचार पाद्यक्रम, सेपिनार, संफर्क कार्बक्रम और इसी प्रकार की कोई अन्य पद्धति से शिक्षा प्रदान करता है।

- (28) "परिनियम" से अभिषेत है, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन निर्वित निजी विश्वविद्यालय के परिनियम,
- (29) निजी विश्वविद्यालय से संबंधित "प्रायोगिक निकाय" से अभिषेत है—
  - (क) छत्तीसगढ़ सोसायटी (विस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्र. 44, सद् 1973) के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी,
  - (ख) पोई पंजीकृत सार्वजनिक न्याय,
  - (ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 (क्र. 1, सद् 1956) की पारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनी तथा,
  - (घ) अन्य कोई निकाय जो तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम के अधीन पंजीकृत हो,
- (30) "विद्यार्थी" से अभिषेत है, जिसी विश्वविद्यालय में जामानिका व्यक्ति जो उपाधि/पदोन्नायि/प्रमाणपत्र अवश्य विद्या संबंधी अन्य विशिष्टता प्राप्ति के लिए निजी वाद्यक्रम का अध्ययन करता है।
- (31) "अनुसूचित जाति" से अभिषेत है, इस अधिनियम से संलग्न व्यक्ति.
- (32) "अनुसूचित जाति" से अभिषेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संघर्ष में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जन-जातियाँ,
- (33) "अनुसूचित जनजाति" से अभिषेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संघर्ष में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जन-जातियाँ,
- (34) "अध्ययन शास्त्र" से अभिषेत है, उच्चतर विद्या तथा गवेषणा के स्थान के रूप में निजी विश्वविद्यालय द्वारा संचारित की गई संस्था,
- (35) "अध्यायक" से अभिषेत है, प्रात्यायक, प्रवाचक, व्याख्याता या किसी अन्य पद्धति का व्यक्ति जो शिक्षण कार्य को अवश्य शोधकर्त्ता का निर्देशन करे अवश्य विश्वविद्यालय के विज्ञी पाद्यक्रम के अध्ययन हेतु विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करे,
- (36) "विश्वविद्यालय अनुदान अस्थोग" से अभिषेत है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (क्र. 3, सद् 1956) के अधीन स्थापित आयोग,
- (37) "दू. नी.सी. विनियम 2003" से अभिषेत है, दू. नी.सी. (निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं याकृत स्तर का संधारण) का विनियम 2003,
- (38) "कुलाध्यक्ष" से अभिषेत है, जिसी विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष,
- (39) "कुलपति" से अभिषेत है, जिसी विश्वविद्यालय का कुलपति,
- (40) "गरीबी रेखा से नीचे के परिवार" से अभिषेत है, ऐसे परिवार जिनकी भाष्य शास्त्र द्वारा समय-समय पर निर्धारित गरीबी रेखा के नीचे हो,

## अध्याय - दो : निजी विश्वविद्यालय की स्थापना

3. निजी विश्वविद्यालय के नीचे दशाएं सामान्य उद्देश्य होंगे :- निजी विश्वविद्यालय के उद्देश्य,
- उच्च शिक्षा में अनुदेशन, अध्यापन तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करना एवं शोध तथा ज्ञान की अभिवृद्धि एवं विस्तार का प्रावधान करना।
  - उच्चतर औद्योगिक क्षमता का सुनन करना।
  - शिक्षा एवं प्रशिक्षण की उन्नत मुख्यालयों को मुलभ करना।
  - अध्यापन तथा शोध करना एवं विश्वाण कार्यक्रमों को विस्तृत उपलब्ध कराते रहना।
  - शोध एवं विकास तथा ज्ञान की सहभागिता एवं उसके अनुप्रयोग के लिए उत्कृष्टता के लिए कार्यक्रमों का सुनन करना।
  - उद्योग एवं सार्वजनिक संस्थाओं हेतु प्रार्थी सेवा उपलब्ध करना।
  - वह मुनिक्षित करना कि उपाधि, प्रोफेसर, प्रभाणपत्र तथा अन्य अकादमिक उपलब्धियों हेतु मापदण्ड यू.जी.सी., ए.आई.टी.टी.ई., बी.सी.आई., एम.सी.आई., डी.ई.सी. या अन्य विद्यापत्र अभियानों द्वारा विधायित मानक स्तर से विभिन्न स्तर का न हो।
  - निजी ऐसे अन्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करना, जो समय-समय पर विनियमक आदेश वी अनुरूप के आधार पर एवं शासन द्वारा अनुमति हो।
4. (1) प्रायोजनक निकाल द्वारा अधिनियम वी भारा 3 में दस्तीकृत देशों की गूर्ति हेतु विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए परियोजना प्रतिवेदन आवेदन के साथ विनियमक आदेश को, विधायित शुल्क तथा ऐसे प्रारूप में देखा कि विहित किया जाये, प्रस्तुत किया जावेगा। निजी विश्वविद्यालय स्थापना के प्रस्ताव का प्रेषण,
- (2) परियोजना प्रतिवेदन में विस्तृतित जानकारी दी जावे अर्थात् :-
- प्रायोजक निकाय के पंजीकरण प्रमाणपत्र, संविधान तथा उपविधियों के साथ अन्य विस्तृत विवरण,
  - विगत 03 वर्षों के अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ प्रायोजक निकाय के विस्तृत संसाधन की विस्तृत जानकारी,
  - प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय का नाम, स्थान तथा मुख्य परिसर,
  - निजी विश्वविद्यालय के उद्देश्य,
  - भूमि, भवन तथा अन्य अप्योसंरचनात्मक मुख्यालयों की उपलब्धता,
  - निजी विश्वविद्यालय प्राप्त होने के पहले परिसर विकास का विस्तृत व्यौदा यथा भवन निर्माण, अन्य संरचनात्मक मुख्यालयों एवं अप्योसंरचनात्मक मुख्यालयों तथा उपकरणों को प्राप्त करने अवधि हेतु योजना साथ ही आगामी पांच वर्षों हेतु जारीनदर कार्यक्रम की क्रम-रेखा,
  - पूँजीगत व्यय का आगामी पांच वर्ष के लिए संरणमद्द विवरण तथा वित्त व्यवस्था के द्वारा,
  - संकायों की प्रकृति एवं संस्था वधु विज्ञान, कला, वाणिज्य, तकनीकी शिक्षा आदि, पढ़े जाने वाले पाठ्यक्रमों के प्रकार जैसे- स्नातक, स्नातकोत्तर एवं निजी

विश्वविद्यालयों द्वारा प्रत्येक संकाय में विद्ये जाने वाले प्रस्तावित शोध कार्यक्रम एवं राज्य के विकासात्मक लक्ष्यों के संदर्भ में एवं उनकी प्राप्तिगिकता तथा आगामी 5 वर्षों

हेतु चरणबद्ध कार्यक्रम तथा पादयक्षमानुसार प्रवेश देने वाले छात्रों की लिखित संख्या,

- (अ) संबंधित विषयों में ग्रामोजक निकाय को उपलब्ध अनुभव तथा विशेषज्ञता,
- (ब) अध्यापन विद्ये जाने वाले पादयक्षमों तथा शोध कार्य हेतु आवश्यक अकादमिक सुविधायें यथा : अध्यापक, तकनीकी / गैर-तकनीकी कर्मचारी एवं उपकरणों की उपलब्धता,
- (ट) पादयक्षम अनुसार या कार्यक्रम अनुसार आवर्ती व्यय का अनुमान तथा उपलब्ध वित के स्रोत तथा अनुमानित प्रति विद्यार्थी व्यय,
- (इ) संसाधनों को गतिमान करने की योजना एवं इस हेतु पूँजी की लागत तथा उसके ऐसी प्रोतों की भुगतान की प्रक्रिया,
- (उ) अंतर्राज्यीय स्रोतों वैसे छात्रों से शुल्क की बसूली प्राप्ति-सेवा एवं विश्वविद्यालय के उद्देश्यों से संबंधित अन्य गतिविधियों से प्रत्याशित राजमद एवं अन्य प्रत्याशित आय से कोष-निर्माण की योजना,
- (ऋ) विभिन्न पादयक्षमों हेतु प्रस्तावित गुलक दांचा व्यय का विस्तृत विवरण, शुल्क में दी जाने वाली विवाह या छूट या परिहास तथा छावड़ुणि, यदि कोई हो, समाज के लाभिकारी वर्ग से कमज़ोर वर्ग, अनुसूचित आर्थि, अनुभूति जन-जाति या अन्य पिछड़े वर्ग को दी जाने वाली छूट का विवरण,
- (ए) निजी विश्वविद्यालय में पढ़ाये जाने वाले विभिन्न पादयक्षमों में प्रवेश की प्रस्तावित प्रक्रिया,
- (ओ) निजी विश्वविद्यालय में अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु प्रस्तावित प्रक्रिया,
- (एम) दूरवार्ता शिक्षा कार्यक्रम हेतु प्रस्तावित केन्द्र के नाम के साथ विस्तृत विवरण,
- (एम) स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यक्रम तथा विशिष्ट अध्यापन, प्रशिक्षण या शोध गतिविधियों का विवरण,
- (एम) कृषक, महिलाओं तथा विशेष रूप से इस राज्य में स्थित उद्योगों के लाभ हेतु चलाये जाने वाले कार्यक्रम,
- (एम) खेल वैदेय तथा अन्य उपलब्ध या प्रस्तावित सुविधाओं का विवरण यथा: राष्ट्रीय फैडेट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना, स्काउट एवं गाईड का विवरण,
- (एम) दूर वरितर एवं अध्ययन केन्द्र की स्थापना विशेषकर राज्य के अनुसूचित घोटों में,
- (फ) प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय की स्थापना करने की आवश्यकता एवं औचित्य का प्रतिपादन,

#### प्रस्ताव का मूल्यांकन.

5. (1) निजी विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव परियोजना प्रतिवेदन के साथ प्राप्त होने के पश्चात् विनियामक आयोग प्रस्ताव में उल्लिखित तथ्यों की जांच-पढ़ाल, जैसा कि आवश्यक समझेगा यथासंभव 07 दिनों में पूरी करेगा,
- (2) जांच पढ़ाल की अवधि में विनियामक आयोग किसी भी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी मांग सकता है और ऐसी जानकारी प्राप्त होने के उपरांत, यथासंभव विनियामक जायोग 45

दिनों के भीतर परियोजना प्रस्ताव के मूल्यांकन का कार्य पूरा करेगा, मूल्यांकन करते समय विनियोगक आवोग निम्नलिखित बातों विचार में रहेगा :-

- (क) विस शेत्र में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव है वहाँ उच्च शिक्षा तथा शोध के शेत्र में उपलब्ध सुविधाएं,
- (ख) प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय के यास यदि कोई विशिष्ट वैज्ञानिक या कोई इन्डस्ट्रीजल या कार्यक्रम हों जो कि राज्य में उपलब्ध अकादमिक संसाधनों की वृद्धि करे एवं मानव संसाधन के विकास में मदद करे,
- (ग) पिछले शेषों के उन्नवन अवधारणा शैक्षीय असंतुलन को समाप्त करने के लिए व राज्य के अधिकृत शेषों में दूसरे परिसर प्रारंभ करने हेतु निजी विश्वविद्यालयों का कार्यक्रम,
- (द) उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा सुलभ करते हुए समाज सेवा एवं युवकों का कल्याण निजी विश्वविद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है।

6. (1) घास 5 में उल्लिखित नांच व मूल्यांकन पूर्ण करने के पश्चात् एवं इस बात से संतुष्ट होने पर आठवट पर जारी करना, कि प्रायोगिक निकाय को निजी विश्वविद्यालय की स्थापना का अवसर दिया जा सकता है, विनियोगक आवोग राज्य सरकार को प्रायोगिक निकाय के हक में आशय पत्र जारी करने हेतु अनुरोध करेगा।

(2) विनियोगक आवोग की अनुरोध स्वाप्न होने पर, राज्य सरकार प्रायोगिक निकाय को आशय पत्र जारी करने पर विचार कर सकता है।

7. घास 6 (2) में उल्लिखित आवश्यक पत्र में निम्नलिखित गते सम्मिलित होगी जो प्रायोगिक निकाय को इस राज्य में एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये पूरी करवी होगी, अर्थात् :

(1) वह स्थापित करेगा :-

- (क) छत्तीसगढ़ राज्य में ही मुख्य परिसर, दूर परिसर एवं अध्यावन केन्द्र,
- (ख) इस अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों के अनुसार विनाश निधि,

(2) वह न्यूनतम निम्नलिखित प्राप्त करेगा -

- (क) 15 एकड़ भूमि यदि अन्यत्र मुख्य परिसर स्थापना प्रस्तावित है, तथा साथ ही वह इनके भू-स्वामित्व अधिलेख प्रस्तुत करेगा,
- (ख) 25 एकड़ भूमि यदि अन्यत्र मुख्य परिसर स्थापना प्रस्तावित है, तथा साथ ही वह इनके

(3) वह प्रशासकीय कार्यों तथा अकादमी कार्यों के सम्पादन के लिए कम से कम 25,000 वर्गफीट का निर्मित शेत्र, जलनों तथा अन्य सहायक निर्माणों के रूप में उपलब्ध करायेगा,

(4) वह परिवर्तन देगा कि -

- (क) यह कि निजी विश्वविद्यालय की भूमि तथा भवन का उपयोग केवल निजी विश्वविद्यालय के कार्यों हेतु ही किया जायेगा,
- (ख) निजी विश्वविद्यालय के विगम के तत्काल आद तथा कक्षायें प्रारंभ होने के पूर्व वर्षां प्रत्येक संस्था में अलगसक संकाय सदस्यों तथा अन्य सहायक कर्मचारीवृद्धों की नियुक्ति हर विभाग या विषय में कर ही जायेगी,

- (ग) पर्याप्त संख्या में उपकरण, कम्प्यूटर, फ़ॉनीचर तथा अन्य आवश्यक सामग्री सुलभ कारोबारी जावेगी, तथा प्रधम पांच वर्षों में रुपये बीस लाख रुपये प्रति वर्ष खर्च की जावेगी,
- (घ) प्रधम वर्ष में कम से कम दस लाख बी गुस्तके तथा परिकारे, ब्रह्म बी जावेगी तथा प्रधम तीन वर्ष में पचास लाख रुपये की रुपये उत्सवों, विविधकारों तथा कम्प्यूटर नेटवर्किंग तथा अन्य सुविधाओं पर व्यवहार की जावेगी जो कि विद्यालय में पर्याप्त समकालीन अध्यापन तथा धोध कार्य की ज़रूरतों के मुताबिक हो,
- (इ) नियमित पाद्यक्रम से जुड़ी ऐसी गतिविधियों को संचालित किया जावेगा जिससे कि ऐसे उचित अकादमी तथा स्वस्य वातावरण का निर्माण हो सके, उदाहरणार्थ संगोष्ठी, बाद-विदाद, प्रश्नमंच कार्यक्रम तथा अन्य पाद्यवेत्तर गतिविधियों जैसे कि एस.सी.सी., एन.एस.एस., खेल-कूद आदि, जो कि विद्यार्थियों के हित में हों तथा इस विषय की अधिकारिता रखने वाली संस्थाओं द्वारा समर्पित हों,
- (ज) (क) नियोजित विद्यविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा कार्यक्रम चलाये जायेंगे,
- (क) केन्द्रीय नियामक निकायों द्वारा समय-समय पर विहीन अन्य सभी शर्तों का अनुसालन किया जायेगा एवं उनके द्वारा जारी गई समस्त जानकारियों को प्रदान किया जायेगा,
- (क) समय-समय पर केन्द्रीय नियामक निकायों द्वारा निर्णित ऐसे न्यूनतम मापदण्डों का अनुसालन किया जायेगा, जो पाठ्यपत्र, संकारणी, अध्यारोपणात्मक सुविधाओं तथा विद्यों संसाधनों से संबंधित हैं,
- (क) नियोजित विद्यविद्यालय द्वारा संचालित पाद्यक्रमों के अंत में दिये जाने वाली स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधि वा प्रोफेशनल. बी.बी.सी. अध्यवा अन्य संबंधित निकायों के विनियमों/मापदण्डों के अनुरूप होंगी,
- (क) प्रवेश प्रक्रिया तथा शुल्क नियामक नियामक निकायों द्वारा विहित मापदण्डों/दिशानिर्देशों, यदि कोई है, के अनुरूप होंगे,
- (क) नियोजित विद्यविद्यालय के गैरक्षणिक कर्मचारीयुद के पास यू.बी.सी. व अन्य संबंधित निकायों द्वारा नियोजित न्यूनतम गैरक्षणिक अहंका रखते हों; तथा उन्हें उनित वेतन प्रदान किया जायेगा,
- (क) नियोजित विद्यविद्यालय सभी जाति, वर्ग, धर्म, बंश, लिंग के लिये खुला रहेगा एवं नियोजित विद्यविद्यालय के लिये यह वैधानिक नर्ती होगा कि वह किसी व्यवित को उक्ती प्रार्थिक आस्था या अवसास के कारण किसी भी प्रकार की पुरुषक परीक्षा से गुजारे, याहे वह घर्म संबंधी हो या अन्य हो, या किसी अवसास से संबंधित हो जिससे अध्यापक के रूप में उसकी नियुक्ति प्रभावित होती हो या अन्य किसी पद पर उसकी नियुक्ति प्रभावित होती हो, या विद्यार्थी के रूप में उसके प्रवेश को प्रभावित करती हो, या उसके किसी भी अधिकार से वंचित करती हो,
- (क) इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत परिविष्म, अध्यादेशों की स्वीकृति के दिन प्रवेश तथा काढ़ाओं के संचालन का कार्य प्रारंभ वर्ही किया जायेगा.

8. (1) प्रायोजक विकाय अनुपालन प्रतिवेदन वरिचन तथा अन्य आवश्यक अधिलेखों महित विनियामक आयोग को प्रस्तुत करेगा। विनियामक प्रतिवेदन की प्रस्तुति, सत्यापन तथा निरीक्षण,
- (2) अनुपालन प्रतिवेदन की प्राप्ति के बाद विनियामक आयोग उसकी तथा ऐसे तरीके में जैमा व उचित समझे, तथ्यात्मक आंकड़ों की जांच करेगा जिसमें स्वल निरीक्षण भी शामिल है।
- (3) उपचारा (2) में उल्लिखित अनुसार अनुपालन प्रतिवेदन की जांच करने पर यदि इसमें विनियामक आयोग की किसी गलत जांच जाये तो वह प्रायोजक विकाय को शीघ्रतापूर्वक इन विविचारी कमियों को दूर करने का निर्देश देगा।
- (4) विनियामक आयोग इस बात से संतुष्ट होने पर कि, उपर उल्लिखित उपचारा (3) के अनुसार पहिचानी कमियों को दूर कर दिया गया है, विविचारी कमियों को पूरा करने की जानकारी प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर, राज्य शासन को निवी विश्वविद्यालय की स्थापना की स्थिति के संबंध में प्रतिवेदन भेजेगा।
- (5) विनियामक आयोग से उक्त उपचारा (4) के अनुसार प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात, राज्य शासन यू.जी.सी. से प्रस्तावित निवी विश्वविद्यालय के निरीक्षण करने का अनुरोध करेगा। परंतु यह भी कि यू.जी.सी. अपने प्रतिवेदन अधिक से अधिक 3 माह के अंदर देगा अन्यथा राज्य शासन अपने विवेकानुसार आगामी कार्यवाही करेगा।
9. (1) विनियामक आयोग द्वारा धारा 8 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रतिवेदन तथा यू.जी.सी. का निरीक्षण प्रतिवेदन, यदि ऐसा कोई है, पर विचार उत्तरांत यदि राज्य शासन को संतुष्टि हो जाती है कि प्रायोजक विकाय ने धारा 7 के प्रावधानों को पूरा किया है तथा प्रस्ताव के आधार पर एक निवी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा सकता है तो, इस अधिनियम में संलग्न अनुसूची में संशोधन कर वह ऐसे नाम तथा विवरण जैसा इस संबंध में विविर्धि किया जाये निवी विश्वविद्यालय स्थापित करेगा। स्थापना तथा नियम,
- (2) इस प्रकार के निवी विश्वविद्यालय का निगमन उस तिथि से मात्रा जावेगा जिस तिथि से अनुसूची का संशोधन हुआ है। परंतु यह भी कि उक्त उपचारा (2) में दर्शायी निगमन की तिथि तथा धारा 4 की उपचारा (1) में उल्लिखित आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होगा।
- (3) निवी विश्वविद्यालय अनुसूची में संशोधित नाम का एक नियमित निकाय होगा, जिससे वापरत उत्तराधिकार एवं सामान्य विन्ह होगा, जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए सम्पूर्ण एवं उसका स्वामित्व प्राप्त कर सकेगा, जो अनुबंध कर सकेगा, बाद बहात सकेगा या उस नाम से उस पर बाद चलाया जा सकेगा।
- (4) ऐसे निवी विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विस्तर प्रस्तुत वाद या अन्य कानूनी कार्यवाही होने पर अधिवचन कुलसंचित द्वारा हस्ताक्षरित या सत्यापित किये जावेगे तथा इस तरह के वाद या कानूनी कार्यवाही की सभी प्रक्रिया निवी विश्वविद्यालय के कुलसंचित के नाम तामील होगी।
- (5) विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर ऐसे स्थान पर होगा जो अनुसूची के पांचवें कॉलम में दर्शाया गया है।

- अध्याय-तीन : निवी विश्वविद्यालय का संचालन एवं प्रबंधन**
- स्वरितीय निवी विश्वविद्यालय,** 10. निवी विश्वविद्यालय स्वरितीय होगा, तथापि लिखित कारण दर्शाएं हुए शासन इसे वित्तीय/भौतिक प्रोत्साहन देने पर विचार कर सकता है।
- विन्यास निधि.** 11. (1) उपर्युक्त पाठा 6 (2) के अंतर्गत राज्य शासन से इच्छा पत्र प्राप्त होने पर ऐसा प्रायोजक निकाय जो इच्छा पत्र में दी गई शर्तों एवं परिवर्धनों को पूर्ण करने तत्पर है, निवी विश्वविद्यालय के लिए विन्यास निधि की स्थापना, विनियामक आयोग के कोष में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार नीचे दर्शाई गयी राशि जमा करेगा।  
 (क) राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में निवी विश्वविद्यालय की स्थापना होने पर एक कठोड़ स्पष्ट  
 (ख) अन्य प्रकारों में तीन कठोड़ स्पष्ट।
- परंतु, प्रायोजक निकाय द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व विन्यास निधि में जमा राशि समायोजित कर ली जावेगी।
- (2) यह सुनिश्चित करने के लिए कि निवी विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम तथा असारेश के उपर्युक्त कार्य कर रहा है, यह विन्यास निधि सुनिश्चित के रूप में प्रयुक्त होगी। प्रायोजक निकाय द्वारा अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश तथा विनियोग के किसी भी उपर्युक्त के उल्लंघन या भंग करने पर विनियामक आयोग की अद्वारा पा, राज्य शासन संपूर्ण विन्यास निधि या उसके किसी अंश को समरप्त कर सकेगा।
- (3) विन्यास निधि के स्थापना की विधि, उसके विनियोगन की विधि, इससे प्राप्त आय को प्रायोजक निकाय को भुक्तान, उसके राजसात करने और प्रायोजक निकाय को बापस करने की विधि इस प्रकार होगी जैसी कि विहित की जावे।
- साक्षन् निधि.** 12. प्रत्येक निवी विश्वविद्यालय एक सामान्य कोष की स्थापना करेगा, जो सामान्य कोष के नाम से जाना जावेगा एवं जिसमें निम्न प्रकार की राशि जमा की जावेगी :-
- (क) निवी विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त शुल्क तथा अन्य प्रभार,
  - (ख) प्रायोजक निकाय द्वारा किया गया कोई अंदाशन,
  - (ग) निवी विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों के परिपालन में किये जाने वाले किसी प्रापार्श या अन्य कार्य के द्वारा प्राप्त आय,
  - (घ) व्याप्त, वसीयत, दाव, विन्यास तथा अन्य प्रकार का अनुदान, तथा
  - (ङ) निवी विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अन्य सभी प्रकार की राशि।

पांतु विद्यार्थियों से खंड (क) के अंतर्गत प्राप्त शुल्क का एक प्रतिशत बैंक ड्राफ्ट/बैंक चेक के साथम से नियामक आयोग के पास शुल्क प्राप्ति के माह के अगले माह के 15 दिनों के अंदर जमा किया जाना होगा। यदि कोई निवी विश्वविद्यालय उपरोक्त शुल्क विनियामक आयोग के पास नियत समय में जमा करने में असफल होता है तो प्रति 30 दिन पर 1.5 प्रतिशत शास्त्रीय व्याप्ति की दर से साथ संपूर्ण राशि जमा करेगा। यदि इस राशि को जमा करने में 90 दिन से अधिक का व्यतिक्रम होता है तो इस कार्य को अधिनियम का उल्लंघन माना जावेगा एवं विनियामक आयोग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

परंतु आगे यह भी कि विनियोगक आयोग इस राशि को यथोचित समय में राज्य के संचित निधि में जमा करेगा।

13. सामान्य निधि का उपयोग निम्न उद्देश्यों हेतु होगा, यथा :-
- (1) इस अधिनियम, परीनियम, अध्यादेश, विधान के उद्देश्य हेतु लिये गये उभार विस्तरे व्याप भी शामिल हैं, के भुगतान हेतु।
  - (2) निवी विश्वविद्यालय की सम्पत्ति के राज-राजव लेतु।
  - (3) कोष की धारा (11) एवं (12) के अंतर्गत निर्मित निधियों के अकेशण पर व्यय का भुगतान।
  - (4) न्यायालय में ऐसे वाद या वैधानिक कार्यवाही संबंधी व्यय, जिसमें विश्वविद्यालय एक पक्ष हो।
  - (5) विश्वविद्यालय के अधिकारीयों एवं कर्मचारियों, शैक्षणिक एवं शोध कार्य में संलग्न स्टाफ के बेतन तथा भर्ते का भुगतान तथा भविष्य निधि, अंशदान, उपचान तथा अन्य लाभ का भुगतान।
  - (6) शासी निकाय, प्रबंधन मंडल, अकादमिक परिषद् तथा विश्वविद्यालय के परीनियम द्वारा प्रीर्णित अन्य प्राधिकारी के सदस्यों तथा इस अधिनियम, परीनियम, अध्यादेश एवं विनियोगन के निवी भी ग्रान्थारा के ग्रान्थारा हेतु प्रबोजक वित्तान के किसी प्राप्तिकारी या अध्याय या कुलपति द्वारा नियुक्त किये गये सदस्यों के बाजा-भर्तों या अन्य भर्तों के भुगतान हेतु।
  - (7) गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के विद्यार्थियों को अयोतावृति, छात्रवृति, शुल्कमुक्ति, सहायमानवृति तथा अन्य पुस्तकार या शोध सहायुक्त, प्रशिक्षा या अन्य ऐसे विद्यार्थी जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन निर्मित निवी विश्वविद्यालय के संविधि, अध्यादेशों एवं विनियमों या नियमों के अंतर्गत इस प्रकार की स्वीकृति की गयता रखते हैं।
  - (8) इस अधिनियम तथा इसके अंतर्गत निर्मित संविधियों, अध्यादेशों या विनियमों के क्रियान्वयन में विश्वविद्यालय द्वारा किये गये किसी भी प्रकार के व्यय का भुगतान।
  - (9) प्रशोधक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना एवं निवेश में पूँजीगत व्यय का भुगतान जो व्याज की प्राचालित बैंक दर से अधिक न हो।
  - (10) विश्वविद्यालय द्वारा इस अधिनियम तथा इसके अंतर्गत निर्मित संविधियों, अध्यादेशों तथा विनियमों के अंतर्गत वापरम् संबंधी किये जाने वाले कारबौं से संबंधित व्यय एवं प्रधार का भुगतान।
  - (11) प्रबंध मंडल द्वारा निवी विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के लिये अनुमोदित होने पर प्रायोजन निकाय की ओर से विश्वविद्यालय की व्यवस्था का दायित्व बहन करने वाली किसी संस्था को किया जाने वाला व्यवस्था गुन्क महित व्यय का भुगतान।

परंतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रबंध मंडल के पूर्वानुग्रहन बिना जैसा भी विश्वव दिया गया हो, कोई व्यय नहीं किया जावेगा औ प्रबंध मंडल द्वारा वर्ष हेतु कुल आवार्ती तथा कुल अनावार्ती व्यय हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो।

परंतु यह भी कि सामान्य निधि की राशि का उपयोग जैसा कि उपभारा (1) में वर्णित उद्देश्य के लिये उचित है, निवी विश्वविद्यालय के शासी निकाय के अनुमोदन से किया जा सकेगा।

- विश्वविद्यालय के अधिकारी.** 14. निचो विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे यथा :-
- (1) कुलाध्यक्ष
  - (2) कुलाधिपति
  - (3) कुलपति
  - (4) कुलसचिव
  - (5) मुख्य वित्त एवं सेक्रेटारियाई
  - (6) अन्य ऐसे अधिकारी, जिसकी घोषणा विश्वविद्यालय के संविधि के अंतर्गत अधिकारी के रूप में की जावे।
- कुलाध्यक्ष.** 15. (1) छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, निचो विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे।
- (2) कुलाध्यक्ष, जब ये उपस्थित होंगे, निचो विश्वविद्यालय की उपाधि, प्रोफेसर प्रदान करने हेतु आयोजित दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।
  - (3) कुलाध्यक्ष की निम्न शक्तियाँ होंगी, यथा :-
- (क) कुलपति की नियुक्ति करना,
  - (ख) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से संबंधित किसी अभिलेख अध्यवा मूल्यना पांगना,
  - (ग) कुलाध्यक्ष को भेजी गयी बानकारी के आधार पर, यदि वह संतुष्ट है कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश, प्रक्रिया अथवा निर्णय इस अधिनियम, नियमों एवं नियमों के अनुरूप नहीं है, तो कुलाध्यक्ष विविधानक आयोग से अभिमत प्राप्त कर सकेंगा, ऐसा समाधान होने पर कि वोई अनियमिता हुई है तो यह इस प्रकार के निर्देश प्रसारित कर सकेंगा जैसा कि यह निचो विश्वविद्यालय के लिए में उचित समझे तथा इस प्रकार बारी किए गए निर्देश निचो विश्वविद्यालयों द्वारा पालन किये जावेंगे।
  - (घ) कुलाधिपति अथवा अन्य वित्ती से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कुलपति के विस्त जांच कराना।
- कुलाधिपति.** 16. (1) प्रायोजक निकाय द्वारा कुलाधिपति की नियुक्ति, कुलाध्यक्ष के पूर्वनुगोदन से 3 वर्षों के लिए की जावेंगी।
- पांतु, किसी निचो विश्वविद्यालय को स्थापित करने तथा उसे कार्यान्वयन बनाने के लिये, प्रायोजक निकाय, राज्य शासन से मताह लेकर कम से कम 1 वर्ष के लिये कुलाधिपति की नियुक्ति करेंगा पांतु यह 3 वर्षों से अधिक के लिये नहीं होगी।
- (2) कुलाधिपति निचो विश्वविद्यालय का संस्था प्रभुत्व होगा।
  - (3) कुलाधिपति विश्वविद्यालय की शासी निकाय की बैठकों की अध्यक्षता करेंगा तथा कुलाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाधि तथा प्रोफेसर प्रदान करने हेतु आयोजित दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगा।

- (4) कुलपति की नियुक्ति समिति द्वारा अनुशंसित नहीं होगी यदा :-
- किसी भी सूचना अथवा अधिकार को मंगा सकना,
  - शिकायतों के आधार पर बह बहुत होता है कि कुलपति के कार्य से नियोजित विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिवेश अथवा अध्यादेशों का उल्लंघन हुआ है अथवा कोई वित्तीय अविवादिता की गई है तो कुलपति को पदब्रूत करने के लिए कुलाध्यक्ष को रिपोर्ट (प्रतिवेदन) देना,
17. (1) कुलपति की नियुक्ति, इस कार्य के लिए गठित छोजनीय समिति द्वारा अनुशंसित नाम- कुलपति,  
सूची में से कुलाध्यक्ष द्वारा की जावेगी।
- (2) उपरां (1) में अङ्गित सर्व कमेटी नियन्त्रणरात्र होगी :-
- प्रायोजक निकाय द्वारा नामांकित 2 छात्रतिप्राप्त शिक्षाविद्,
  - उच्च शिक्षा विभाग से एच्यू ग्रामन द्वारा नामांकित एक छात्रतिप्राप्त व्यक्ति,  
छोजनीय समिति से सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को कुलाध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष नियुक्त जिया जावेगा,
- (3) छोजनीय समिति न्यूनतम् 3 छात्रतिप्राप्त शिक्षाविदों की नाम-सूची कुलपति की नियुक्ति हेतु  
प्रस्तुत करेगी।
- परंतु, यदि छोजनीय समिति द्वारा अनुशंसित नाम-सूची को कुलाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित  
नहीं जिया जाता है तो वे समिति से न्यू अनुशंसा मंगा सकता है।
- परंतु आगे यह भी कि, न्यू-स्थानित नियोजित विश्वविद्यालय के कार्य को करने के लिए  
कुलाध्यक्ष द्वारा कुलपति के गारांर हो वही को लिए कुलपति की नियुक्ति की जा  
सकेगी,
- (4) कुलपति की नियुक्ति, उपरां (10) में दिये गये प्रावधानों के अनुकूल 4 मार्गों के लिए  
होगी।
- परंतु सभी सीमा समाजि के परचात् भी नये कुलपति के कार्यभार प्रहण करते तक  
वे अपने एट पर बने रहेंगे, किन्तु किसी भी स्थिति में यह सभी सीमा 6 माह से अधिक  
नहीं होगी।
- (5) कुलपति नियोजित विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी एवं अकादमिक अधिकारी होगा तथा  
विश्वविद्यालय के क्रिया-कलाओं पर सामाज्य पर्यवेक्षण एवं निर्यंत्रण बनाए रखेगा तथा  
नियोजित विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राविकाणों के नियंत्रण का क्रियान्वयन करवायेगा।
- (6) कुलाध्यक्ष एवं कुलपति दोनों की अनुस्थिति में, कुलपति नियोजित विश्वविद्यालय के  
वीचांत समारोह की अध्यक्षता करेगा।
- (7) यदि कुलपति की रात में किसी ऐसे विषय में खटित कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत होती  
है जिसकी शक्तियाँ किसी अन्य प्राधिकारी को इस अधिनियम के द्वारा अनुकूल के अंतर्गत  
प्रदत की गई है, तो वह ऐसी कार्यवाही करेगा जैसा वह उन्हें समझता हो तथा की गई  
कार्यवाही से यक्षमता प्रदत ऐसे अधिकारी अथवा प्राधिकारी को अवगत करवायेगा, जो कि  
सामान्यतः उस ग्रामपाल में कार्यवाही करता है :

परंतु, यदि संबंधित प्राधिकारी के अभियात में इस प्रकार की कार्यवाही कुलपति के द्वारा नहीं नीचे जावेगी तो, तो इस प्रकार वा प्रकारण, निर्णय हेतु कुलपति को भेजा जायेगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

परंतु, वह भी कि यदि कुलपति के द्वारा कोई कार्यवाही निची विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को प्रभावित करती है तो वह व्यक्ति देसी कार्यवाही की सूचना प्राप्ति की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर शासी निकात के समय अंतीम करने हेतु अधिकार होगा। शासी निकात वा निर्णय संबंधित व्यक्ति को अंतीम करने की तिथि से अधिकतम 3 माह के भीतर सूचित कर दिया जावेगा।

- (8) परंतु कुलपति की तथा में निची विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का कोई निर्णय इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों अथवा नियमों द्वारा प्रत्यन शक्तियों से बाहर है अथवा निची विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल हो सकता है तो वह इस निर्णय को संशोधित करने हेतु संबंधित प्राधिकारी को अनुरोध करेगा एवं उस स्थिति में वर्षानि प्राधिकारी 15 दिन के भीतर उस निर्णय को पूर्णतः या अंतात संशोधित करने से अस्वीकार करता है, तो ऐसा प्रकार कुलपति को प्रस्तुत किया जावेगा और उनका निर्णय अंतिम होगा जो शासी निकाय को तुष्टि के लिए भेजा जावेगा।
  - (9) कुलपति द्वारा ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया जावेगा तथा ऐसे कार्रवाओं का निर्वहन किया जावेगा जैसा कि परिनियम और अध्यादेशों में विविध हो।
  - (10) परंतु किसी धारण अध्यादेश प्राप्त होने पर या अन्यथा भी कुलाध्यक्ष ने यह प्रतीत होता है कि कुलपति ने-
    - (क) इस अधिनियम द्वारा या इसके अंतीम अधिनोदित किसी कार्रवाओं के निर्वहन में गलती की है भ्रष्टवा,
    - (ख) उसमें निची विश्वविद्यालय की नीतिविधियों के सम्बद्ध में अलग मिल तुए हैं तो कुलाध्यक्ष, इस तथ्य को जानते हुए भी कि उनके कुलपति पद की समय-सीमा पूरी नहीं हुई है, तथापि कार्रवाओं का उद्देश्य करते हुए, लिखित आदेश द्वारा, कुलपति के पद को उस तिथि से रिक्त करने के लिए कह सकता है जैसा कि आदेश में विविध किया गया हो।
  - (11) उपराह (10) के अंतर्गत ऐसा आदेश तब तक पारित नहीं होगा जब तक कुलपति को, समुचित आधार दर्शाते हुए इस प्रकार की कार्यवाही की सूचना न दे ती जाये और प्रस्तावित आदेश के विवर कारण बतावे के लिए समुचित अवसर प्रदान न कर दिया जाये।
  - (12) उपराह (10) के अंतर्गत आदेश में उद्दिष्टित दिनांक से, कुलपति अपने पद से पदमुक्त माने जा सकेंगे और कुलपति का पद रिक्त माना जावेगा।
18. (1) कुलसचिव की विद्युक्ति शासी निकाय द्वारा इस कार्य के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की अनुसंधान पर परिनियम में दर्शाये अनुसार की जावेगी, परंतु प्रथम कुलसचिव की विद्युक्ति प्रायोजक निकाय के द्वारा 2 वर्षों के लिए की जावेगी।
- (2) कुल सचिव द्वारा निची विश्वविद्यालय की ओर से सभी अनुबंध हस्ताक्षीर किये जावेगे तथा सभी दस्तावेज एवं अधिसेष अधिकारीक जिन्हे जायेगे।

- (3) कुल संविव ल्यवासी निकाय, प्रबंध मंडल और अकादमिक परिषद् के सदस्य संचिव होंगे किन्तु उन्हें प्राप्तिकार नहीं होगा।
- (4) कुल संविव द्वारा ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन किया जायेगा जैसा कि संविधियों द्वारा निर्धारित किया जा सके।
- (5) निरी समय यह ज्ञापित कराये जाने पर या अन्यथा भी, जांच उपरांत लिखियों सचेत करती हों कि कुलसंविव का पद पर बने रहा निजी विश्वविद्यालय के लिए में वहीं है; तो कुलपति, उन कारणों का लिखित उल्लेख करते हुए कुलसंविव को वदमुक्त करने के लिए कुलाधिकारि को कह सकता है।

परंतु, इस उच्चारा के अंतर्गत कार्यवाही करने के पूर्ण कुलसंविव को सुनाने का अवसर दिया जावेगा।

19. (1) मुख्य वित्त एवं सेक्यायिकारी की नियुक्ति कुलपति द्वारा इस प्रकार की जानेगी जैसा कि मुख्य वित्त एवं सेक्यायिकारी,
- (2) मुख्य वित्त एवं सेक्यायिकारी, ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वाह करेगा, जैसा कि परिनियमों द्वारा निर्धारित किया जावे।
20. (1) निजी विश्वविद्यालय ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है जो कि उसके संचालन के लिए आवश्यक हो।
- (2) निजी विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति और उनकी शक्तियाँ व वार्ष उप्रकार के होंगी, जैसा कि परिनियमों द्वारा निर्धारित होये जावे।
21. (1) निजी विश्वविद्यालय के विनियोजित प्राधिकारी होंगे, यथा-
- (क) शासी निकाय
  - (ख) प्रबंध मंडल
  - (ग) सैक्यायिक परिषद् तथा
  - (घ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा सूचित किया जाकर निजी विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किया जावे।
- (2) शासी निकाय एवं प्रबंध मंडल में नामांकित सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होगा, कोई भी नामांकित सदस्य तापातार 2 कार्यकाल से अधिक के लिए नामांकित नहीं किया जावेगा।
22. (1) विश्वविद्यालय के शासी निकाय का गठन विनानुसार होगा, यथा-
- (क) कुलाधिकारि,
  - (ख) कुलपति,
  - (ग) प्रायोगिक निकाय द्वारा नामांकित 3 ल्यातिप्राप्त व्यक्ति, जिनमें कम से कम 01 व्यक्ति विक्षायिक होगा।
  - (घ) राज्य शासन द्वारा स्वातिप्राप्त के नामों की सूची में से कुलाध्यक्ष द्वारा तीन व्यक्तियों को नामांकित किया जावेगा।

- (१) राज्य शासन का एक प्रतिनिधि, और उप-सचिव के स्तर से गोपे का न हो.
- (२) कुलाधिपति शासी निकाय का पदेव अध्यक्ष होगा.
- (३) शासी निकाय विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकारी होगा, विश्वविद्यालय की समस्त भूमि एवं अवल संपत्ति पर शासी निकाय का अधिकार होगा।  
उसे निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी, यथा-
- (क) इस अधिनियम या परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के अलावत दो गई ऐसी सभी शक्तियों का उपयोग करते हुए निजी विश्वविद्यालय के सचालन का नियंत्रण करना, सामान्य देखभाल करना एवं निर्देशित करना,
- (ख) निजी विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के विर्तियों पर पुनर्विनाश करना यदि वे इस अधिनियम, वियामों, परिनियमों अथवा अध्यादेशों से सुखात न हों,
- (ग) निजी विश्वविद्यालय के बजट तथा वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन करना,
- (घ) निजी विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली विस्तृत शक्तियों का नियांत्रण करना,
- (ङ) यदि ऐसी शक्तियां उत्पन्न हो जाये कि निजी विश्वविद्यालय का सुधार सुप्रेर्ण कार्य करना संभव नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में प्रायोजक निकाय को स्वेच्छया भंग करने की अनुशंसा करना,
- (च) ऐसी अन्य शक्तियों जो संविधियों द्वारा निर्धारित की जाये,
- (४) शासी निकाय की बैठक प्रायोक फैलोप्टर वर्ड में कम से कम तीन बार होंगी,
- (५) शासी निकाय की बैठकों के लिये गणपूर्ति नम से कम गांव की होगी.
- प्रबंध मंडल:**
23. (१) प्रबंध मंडल का गठन निम्नानुसार होगा, यथा-
- (क) कुलपति,
- (ख) प्रायोजक निकाय द्वारा नामांकित हो प्रतिनिधि,
- (ग) राज्य सरकार द्वारा नामांकित हो प्रतिनिधि,
- (घ) निजी विश्वविद्यालय के दो ऋग्मानुसार बरिष्ठतम प्राध्यापक,
- (ङ) निजी विश्वविद्यालय के दो बरिष्ठतम शिक्षक जो उपचारा (१) (घ) के अंतिरिक्त चक्रीय जग्न में लिये जायेंगे,
- (२) कुलपति विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल का अध्यक्ष होगा,
- (३) प्रबंध मंडल की शक्तियां एवं दायित्व ऐसे होंगे जैसा कि संविधि द्वारा निर्धारित किये जायेंगे,
- (४) प्रति दो माह में प्रबंध मंडल की कम से कम एक बैठक होगी,
- (५) प्रबंध मंडल की बैठकों में गणपूर्ति गांव का होगा.
- शैक्षणिक विभाग:**
24. (१) शैक्षणिक विभाग में कुलपति तथा ऐसी संस्था में अन्य सदस्य होंगे जैसा कि संविधि द्वारा निर्धारित की जायेंगे :

- (2) कुलपति शैक्षणिक परिषद् ना अध्यक्ष होगा।
- (3) शैक्षणिक परिषद् निवी विश्वविद्यालय की प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगी तथा इस अधिनियम, नियमों, परिनियमों एवं अधिकारियों के प्रावधानों के अनुरूप विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नियिकाओं का समन्वय करेगी तथा उन पर समावेश बनाये रखेगी।
- (4) शैक्षणिक परिषद् की बैठकों में गजबूर्जी परिवेश के प्रावधानों के अनुकूल होगी।
25. निवी विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, संविधान, शक्तियाँ एवं कार्यव्य ऐसे होंगे जैसा अन्य प्राधिकारी, कि संविधियों द्वारा निर्धारित किये जावेंगे।
26. (1) इस अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों के अधीन होते हुए निवी विश्वविद्यालय प्रधम प्रधम परिनियम, परिनियम द्वारा निर्माणित विषयों में से सभी या निवी विषय का प्रावधान कर सकेगा, तथा-
- (क) समय-समय पर गठित निवी विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों तथा अन्य निकायों के गठन, शक्तियाँ एवं कार्यव्य,
- (ख) कुलसचिव, मुख्य विचार एवं लेखाधिकारी की नियुक्ति की शर्तें तथा उनकी शक्तियाँ एवं कार्यव्य,
- (ग) अन्य अधिकारियों एवं संचार के माध्यमों की नियुक्ति की शर्तें तथा उनकी शक्तियाँ एवं कार्यव्य,
- (घ) निवी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा की जरूरत,
- (च) अधिकारियों, संचार के माध्यमों, कर्मचारियों एवं छात्रों के बीच विवाद की स्थिति में मध्यस्थिता हेतु त्राईकाला,
- (इ) मानव उपायियों प्रदान करना,
- (ज) निकाय शुल्क से मुक्ति तथा छात्रवृत्ति प्रदान करने संबंधी प्रावधान,
- (झ) प्रवेश संबंधी नीति, विद्यार्थी रोका के नीति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, विकासांग एवं लड़कियों की श्रेणियों के छात्र-संघों के आरक्षण का नियन्त्रण भी समाहित हो,
- (ঃ) छात्रों से लिये जाने वाले शुल्क तथा ऊपर (ঃ) में उल्लेखित श्रेणियों की रियायत का प्रावधान,
- (ঁ) विधिग्राम पाद्यकार्यों हेतु छात्र-संघों का प्रावधान,
- परंतु, यह कि निवी विश्वविद्यालय विनियामक आदेश के पूर्वानुमोदन विना, छात्रों से शान अध्यक्ष कैपिटेनशिप शुल्क लेने संबंधी कोई परिवेश नहीं बनायेगा।
- (2) निवी विश्वविद्यालय का प्रधम परिनियम, शासी निकाय द्वारा विनियामक आदेश के अनुमोदन उपरांत बनाया जायेगा।
- (3) विनियामक आदेश, विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रधम परिनियमों पर उनकी प्राप्ति की तिथि से 2 माह के भीतर विचार करेगा एवं ऐसे संशोधनों सहित, जैसा कि वह उचित समझे, अपना अनुमोदन प्रदान करेगा।

- (4) विश्वविद्यालय, प्रथम परीक्षियों पर, जैसा कि वे विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित की गई है, अपनी सहायति संशोधित करेगा तबा यदि विश्वविद्यालय, विनियामक आयोग द्वारा उपचारा (3) के अंतर्गत किये गये संशोधनों के विषयात्मक हेतु सहमत न हो, तो वह उनका कारण बता सकेगा, विश्वविद्यालय द्वारा किये गये सुझावों को विनियामक आयोग स्वीकार अथवा अस्वीकार का सकता है।
- (5) अन्य सरकार, प्रथम परीक्षियों को, जैसा कि विनियामक आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाता है, राजपत्र में प्रकाशित करेगा एवं तत्पश्चात् ऐसे परीक्षयम् प्रभावशील होगे।
- अद्यापी परीक्षियम् 27. (1) इस अधिकायम् एवं नियमों के प्रावधानों के अधीन नियोजी विश्वविद्यालय के परीक्षियम् में निम्नलिखित में से समस्त अथवा किन्हीं विषयों का प्रावधान हो सकेगा-
- (क) नियोजी विश्वविद्यालय के वये प्राप्तिकारी का सूचन,
  - (ख) लेखा नीति एवं वित्तीय प्रक्रिया,
  - (ग) नियोजी विश्वविद्यालय के प्राप्तिकारीयों में शिक्षकों का प्रतिनिधित्व,
  - (घ) वये विभागों का विवरण तथा विद्यमान विभागों का विवरण या तुरंतः,
  - (ङ) पदक एवं पुरस्कारों का सूचन,
  - (च) पदों का सूचन एवं विवरण,
  - (ङ्घ) शुल्क का तुरंतिपात्रण,
  - (ज) नियमित पाठ्यग्रन्थों में निर्धारित तात्त्व गोद्या में परीक्षान,
  - (झ) अन्य ऐसे विषय को अधिकायम् के प्रावधानों द्वारा निर्धारित होने हैं,
- (2) प्रथम परीक्षियों के अंतिरिक्त नियोजी विश्वविद्यालय के अन्य परीक्षियम्, प्रबंध मंडल द्वारा, शासी निकाय के अनुसूचन से बनायी जाएंगी।
- (3) उपचारा (2) के अंतर्गत निर्वित परीक्षियम् विनियामक आयोग को भेजी जायेंगी तथा विनियामक आयोग, यदि आवश्यक समझे तो, उनकी प्राप्ति की तिथि से 2 माह के भीतर उनमें संशोधन के सुझाव दे सकेगा।
- (4) शासी निकाय, विनियामक आयोग द्वारा सुझाये गये संशोधनों पर विचार करेगा एवं परीक्षियों को अपनी टिप्पणी सहित विनियामक आयोग को वापसू भेजेगा।
- (5) विनियामक आयोग, शासी निकाय द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार करेगा एवं राज्य शासन, विनियामक आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित परीक्षियों को राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा एवं ऐसे प्रकाशन के पश्चात् वे प्रभावशील होंगे।
- प्रथम अध्यादेश 28. (1) इस अधिकायम्, नियम तथा परीक्षियों द्वारा निर्वित प्रावधानों के अधीन प्रथम अध्यादेश, निम्नलिखित समस्त नियुक्तों में से किसी नियुक्त पर विचार का सकता है अपार्द-
- (क) नियोजी विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और उनका नामांकन, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-बाति, विकलांग एवं तद्रूपियों पर विशेष विचार रखा जावेगा।

- (ख) निवी विश्वविद्यालय की सभी उपाधिकारी, पदोपाधिकारी व प्रमाण-पत्रों के लिए अध्ययन के पाद्यक्रमों का निर्धारण,
- (ग) निवी विश्वविद्यालय की उपाधिकारी, पदोपाधिकारी, प्रमाण-पत्रों तथा अन्य अकादमिक वैशिष्ट्य का प्रदान किया जाना, उनके लिए युलाम अहंताएँ एवं उन्हें प्रदान करने एवं प्राप्त करने संबंधी अपार्याये जाने वाली प्रणाली,
- (घ) फैलोशिप, छात्रवृत्ति, विष्ववृत्ति, पदक एवं पुस्कार प्रदान करने संबंधी शर्तें,
- (ङ) परीक्षा समिक्षियों, परीक्षकों एवं मार्डिरेटों की नियुक्ति की प्रक्रिया एवं उनकी सेवावाधि व शर्तों महित परीक्षाओं का संचालन,
- (च) निवी विश्वविद्यालय के विभिन्न पाद्यक्रमों, परीक्षाओं, उपाधिकारी एवं पदोपाधिकारी के शुल्क का निर्धारण,
- (छ) निवी विश्वविद्यालय के छात्रों के आवास की शर्तें,
- (ज) छात्रों के विश्व अद्याधारानामक कार्यवाही संबंधी प्रावधान,
- (झ) निवी विश्वविद्यालय के अकादमिक वातावरण में सुधार हेतु अवश्यक होने गए नियम अन्य विकास का सूचन, गठन एवं कार्यकलाप,
- (ञ) अन्य विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा के संस्थाओं से सहयोग एवं सहभागिता की प्रणाली,
- (ट) अन्य सभी प्रकारण, जो इस अधिनियम या परीक्षेमों के अंतर्गत हैं, अन्यान्यों द्वारा प्रस्तुत होने हैं।
- (2) निवी विश्वविद्यालय का प्रथम अध्यादेश कुलपति द्वारा बनाया जायेगा जो विविधानक अध्योग को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जावेगा।
- (3) उपाधान (2) के अंतर्गत कुलपति द्वारा बनाये गये अध्यादेशों पर विनियामक आधोग उनकी प्राप्ति की लिये से 2 माह के भीतर विचार करेगा एवं उसे या तो अनुमोदित करेगा या संशोधन के सुझाव देगा।
- (4) कुलपति, विनियामक आधोग द्वारा दिये गये सुझावों पर अपनी टिप्पणी देगा एवं “प्रथम अध्यादेश” को विनियामक आधोग को बास करेगा एवं उसकी प्राप्ति पर विनियामक आधोग या तो उसे अनुमोदित करेगा या उसे अस्वीकार कर देगा, एवं उसके अंतिम निर्णय के आधार पर अध्यादेश, जैसा कि विनियामक आधोग द्वारा अनुमोदित होगा, राजपत्र में राज्य शासन द्वारा प्रकाशित किया जायेगा एवं ऐसे प्रकाशन के पश्चात् अध्यादेश प्रभावशील हो जायेगा।
29. (1) प्रथम अध्यादेश के अंतिरिक शेष सभी अध्यादेश अकादमिक परिषद् द्वारा प्रबंध मंडल के अनुमोदन से निर्भर किये जायेंगे,
- (2) विनियामक आधोग उपाधान 1 अंतर्गत निर्भर अध्यादेशों का अनुमोदन करेगा तथा ऐसा अनुमोदित सभी अध्यादेश राज्य शासन, राजपत्र में प्रकाशित करेगा तथा ऐसे प्रकाशन के पश्चात् अध्यादेश प्रभावशील हो जायेंगे।
30. निवी विश्वविद्यालय के प्राधिकारी द्वारा की गई कोई कार्यवाही केवल कोई रिक्त होने के कारण अध्यवा गठन की त्रुटि होने के कारण अवैध नहीं होगी।

निवी विश्वविद्यालय के  
किसी अधिक तरी की  
कार्यवाही की अवैधता का  
कारण नहीं।

- आपात रिक्तियों की दृष्टि.
31. निजी विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों अथवा निकायों के सदस्यों की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा सदस्य को मुक्त करने अथवा विस या पर नियुक्ति या नामांकन हुआ था उसमें परीक्षण होने के कारण उर्पत रिक्तियों को ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा यथार्थीप्र॒ दृष्टि किया जावेगा, जिसके द्वारा पहले ऐसा किया गया था।
- परंतु निजी विश्वविद्यालय के प्राधिकारी अथवा निकाय की आपात रिक्तियों में सदस्य के रूप में नियुक्त अथवा नामांकित होने पर वह सदस्य उस रोप समाचारधि के लिये नियुक्ति या नामांकित होना जिसके स्वाम पर उसकी नियुक्ति या नामांकन हुआ है।
- समिति.
32. निजी विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या अधिकारी ऐसी समितियों का गठन कर सकते हैं जिनके अभ्युदयेय की शर्तें वैसी होंगी जैसी कि इस प्रकार के समिति के विशेष कार्यों के निर्वहन के लिये आवश्यक हो। इस प्रकार की समितियों का गठन एवं उनके कार्यालय वैसे ही होंगी जैसे कि परिनियम में विहित हो।
- निकायिकालय अधिनेत्र यात्रा का उपकार.
33. निजी विश्वविद्यालय द्वारा संचारित अथवा विश्वविद्यालय के काब्दे की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यालयी किसी प्राधिकारी या समिति के प्रस्ताव अथवा अन्य दस्तावेज अथवा किसी वंशी की प्रविहि कुत्तलाचित द्वारा प्रगमित किये जाने पर प्रथम दृष्टा ऐसी रसीद, नोटिस, आवेदन, प्रोसिडिंग प्रस्ताव अथवा इस प्रकार के विषय तथा व्यवहार के रूप में उसी प्रकार ग्राह्य होंगी जैसा कि मूल दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने की दशा में होगी।
- विविध.
34. (1) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अलावा गठित निजी विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, इस अधिनियम के अंतर्गत, परिनियम एवं विश्वविद्यालय के ग्राह्यादेश के ग्राह्यादेशों के अंतर्गत नियिग का नियांन कर राखेंगे।
- (2) प्रबंध संकाल द्वारा इस शाम के संतर्गत किसी प्राधिकारी द्वारा निर्भूत नियिग को संतोषित अथवा निरत कर राखेगा।
- वार्तिक अध्यादेश और विविधम की प्रकारीतियां।
35. सभी वार्तिक अध्यादेश एवं विविधम यात्रा के उल्लेख में प्रकारीत होने के गहनाद् प्राप्तवतीत होंगे।

#### अध्याय-चार : निजी विश्वविद्यालय का विनियम

- विनियमक आयोग.
36. (1) निजी विश्वविद्यालयों के विनियम के लिये एज्य स्तर पर एक विनियामक आयोग स्थापित किया जावेगा जो एज्य शासन एवं केन्द्रीय नियामक अधिकारण के बीच अध्याय, परीक्षा, शोध एवं अन्य कार्यक्रम में व्योग्यत मानक स्तर सुनिश्चित करने, विद्यार्थियों के द्वित संरक्षण तथा कर्तव्यार्थों को तर्कसंगत सेवा शर्तें सुनिश्चित करने के लिये होगा, साथ ही विश्वविद्यालय को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता बनाए रखेगा।
- (2) विनियामक आयोग कुलाध्यक्ष के सामान्य नियंत्रण में कार्य करेगा।
- (3) विनियामक आयोग के गठन में;
- (क) एक अध्यक्ष तथा दो पूर्णकालिक सदस्य जिनमें से एक सदस्य "सदस्य अकादमिक" और दूसरा "सदस्य प्रशासनिक" होगा तथा दो से अधिक अंशकालिक सदस्य होंगे जो कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।
- (ख) एक पूर्णकालिक या अंशकालिक सचिव होगे।

- (4) अध्ययन की नियुक्ति कुलाखण्ड द्वारा ऐसे पेनल से भी जारीगी जिसकी अनुशंसा राज्य शासन के द्वारा की गई हो और जिसमें ऐसे ल्यातिप्राप शिक्षाविदों को शामिल किया गया हो, जिन्हें उन शिक्षा की संस्थाओं के कार्य का समर्पित अनुभव हो।
- (5) सदस्यों की नियुक्ति कुलाखण्ड द्वारा ऐसे पेनल में से भी जारीगी जिसे राज्य शासन द्वारा अनुरोधित फैलाया हो और जिसमें शिक्षा, वित्त, विधि, प्रशासनिक/प्रबंधन आदि में प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्तियों के नाम शामिल हो।
- (6) अध्यक्ष द्वारा सदस्य ऐसे होंगे जो कि इस अधिनियम के तहत स्थापित विश्वविद्यालयों से किसी तरह से संबंधित न हों।
- (7) अध्यक्ष द्वारा सदस्यों की सेवा के विवरण तथा शर्तें, वैदिकों की विधि, आदोग के कर्मचारीरुद्ध की नियुक्तियों और उनकी सेवा शर्तें, विशिष्ट प्रयोजनों के लिये अस्थायी सहायता, आदोग की विधि, आर्थिक प्रतिवेदन, लेखा, अंकेशण और इस प्रकार के अन्य मामले जो कि आदोग के सही संचालन के लिये आवश्यक हों, राज्य सरकार द्वारा इस संघर्ष में बढ़ावे निकालों द्वारा उत्कीर्णित होंगे।
- (8) विनियामक आदोग का यह सामान्य कार्यव्य होगा कि :-
- (a) नियंत्री विश्वविद्यालयों में अध्यापन, परीक्षा और शोध के लिये मानक स्तर बनाए रखने के लिये ऐसे आवश्यक कदम उठाया जो वह उचित समझें,
- (b) यह मुनिविचित करना कि नियंत्री विश्वविद्यालय को कितना शुल्क और अन्य राशि प्रकटित करने का अधिकार हो ताकि वे उनके द्वारा दी जाने वाली भौतिक की लागत को बहुल कर सके और साथ में उनके पास कुछ तरफ़सारत राखि वन्द मी सके जिसका उपयोग वे संविधि के संधारण और ज्ञान के विस्तार के लिये कर सकें,
- (c) यह मुनिविचित करना कि नियंत्री विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य हेतु नियुक्त विद्यार्थियों में विश्वविद्यालय अनुदान आदोग या अन्य नियामक अधिकरण द्वारा निपारित न्यूनतम अद्दाएँ हों,
- (d) मुनिविचित करना कि नियंत्री विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आदोग या अन्य नियामक संस्थाओं द्वारा निपारित न्यूनतम मानवरक्षों के अनुसार हुई है तथा विश्वविद्यालय की परिविधियों, अध्यादेशों के सुधारना है,
- (e) मुनिविचित करना कि नियंत्री विश्वविद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों के साथ शोधण न हो और उनसे शुल्क बहुल करने के लिये गलत तरीके न अपनाए जाये,
- (f) नियंत्री विश्वविद्यालय के विषट्टन संबंधी सभी मामलों में कार्यवाही करें, जिसमें विद्यार्थियों के पादयुक्त पूरा करने, परीक्षा संचालन करने एवं उपायि देने का कार्यक्रम शामिल है, इस कार्य को किसी अन्य विश्वविद्यालय को इस प्रकार सौंपने ताकि विद्यार्थियों के लिये प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो, विद्यार्थियों के लिये नियंत्रण वाले इन सब कार्यों पर तथा साथ में विश्वविद्यालयों के विषट्टन पर होने वाले व्यय को विवाद नियंत्रण एवं सामान्य नियंत्रण से पूरा किया जाएगा,
- (g) नियंत्री विश्वविद्यालय के पाठ्यर्थ से राज्य के विभिन्न स्थानों पर स्थापित अध्ययन केन्द्रों का नियन्त्रण करना,

वार्षिक प्रतिवेदन.	<p>(9) नीति विषयक प्रश्नों पर राज्य रासान विविधामक आयोग को निर्देश दे सकेगा।</p> <p>37. (1) प्रबंध मंडल द्वारा निजी विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जावेगा, जिसमें अन्य विषयों के जीवीरित विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उदाहरण गये कदमों का समावेश होगा तथा विस्तार ग्रन्थालय द्वारा निकाय द्वारा किया जावेगा, एवं इसकी एक प्रति प्राप्योगिक निकाय को भेजी जायेगी।</p> <p>(2) उपरांत (1) के अंतर्गत तैयार की गई वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति कुलाध्यक्ष एवं विविधामक आयोग को भी प्रस्तुत की जावेगी।</p>
वार्षिक लेखा एवं प्रधानमन्त्री.	<p>38. (1) निजी विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा तथा डैलेन्सीट प्रबंध मंडल के विदेशों के अधीन तैयार की जावेगी तथा वार्षिक लेखा का परीक्षण वर्ष में कम से कम एक बार विश्वविद्यालय द्वारा इस कार्य हेतु नियुक्त लेखा परीक्षक द्वारा किया जावेगा।</p> <p>(2) वार्षिक लेखा सहित, लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन रासान निकाय को प्रस्तुत किया जावेगा।</p> <p>(3) वार्षिक लेखा लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन तथा रासान निकाय की टीप सहित एक प्रति कुलाध्यक्ष को तथा एक प्रति विविधामक आयोग को प्रस्तुत की जावेगी।</p> <p>(4) लेखा तथा डैलेन्सीट से उत्पन्न विषय पर विविधामक आयोग द्वारा विए गए निर्देश, विश्वविद्यालय के लिए बंधनकारी होंगे।</p>
विवरकालिक निरीक्षण.	<p>39. (1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, निजी विश्वविद्यालय या उसके किसी केन्द्र का विषयाकालिक निरीक्षण कर सकता है। इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, संबंधित निजी विश्वविद्यालय से अवश्यक जानकारियों मांग सकता है (विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे गए विवरण या विवर 1979 में सभव-सभव पर सिये गये संशोधनों महिल दिये गये हों)।</p> <p>(2) निजी विश्वविद्यालय जो प्रथम उपाधि और/स्नातकोत्तर उपाधि/पदोपाधि पाठ्यक्रम प्रदान करती है, के निरीक्षण एवं मूल्यांकन के पश्चात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निजी विश्वविद्यालय की कोई न्यूनता एवं असमानता पाती है तो ढीप करने के लिए उचित अवसर प्रदान करेंगी। ददि आयोग इस बात से मनुष्टुह होता है कि निजी विश्वविद्यालय ने ऐसा अवसर प्राप्त होने के उपरान्त भी किसी विषयमें दिये गये प्रावधानों की पूर्ति करने में असफल है तो आयोग ऐसे आदेश प्रसारित कर सकता है जो निजी विश्वविद्यालय को प्रथम उपाधि और/स्नातकोत्तर उपाधि/पदोपाधि पाठ्यक्रम जैसी भी सियति हो, को प्रतिबंधित करने का आवेदा तब तक के लिए प्रसारित कर सकता है जब तक न्यूनताओं की प्रतिष्ठृति न कर ली गई हो।</p> <p>(3) निजी विश्वविद्यालय जो प्रथम उपाधि और/स्नातकोत्तर उपाधि/पदोपाधि प्रदान करता है किन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिसूचित नहीं है, उसके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कर्तव्यही कर सकता है तथा जन-सामान्य को लोक अधिसूचना द्वारा सूचित करेंगा, ऐसा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम की पारा 24 के अधीन ऐसे निजी विश्वविद्यालय जो ओ इस प्रकार के कार्यक्रम चलाता है तथा ऐसी गैर विधारित उपाधियां देता है को दंडित किया जा सकता है।</p>

## अध्याय-पाँच : निझी विश्वविद्यालय का परिसमापन

40. (1) यदि प्रायोजक निकाय अपने को विधायित करता चाहे या अधिनियम के तहत स्थापित निझी विश्वविद्यालय को नहाना बंद करता चाहे, तो वह इस संबंध में अपनी योजना की सूचना विनियामक आयोग को देगा जिसमें पाठ्यक्रम व परीक्षा भूमि करने की व्यवस्था सुनिश्चित करता तथा भवित्व की उम तिथि की भी सार्वजनिक पोषण की जाएगी जिसके बाद फिर ये विद्यार्थियों को भर्ती नहीं किया जाएगा।  
 प्रशोधक निकाय के विषय होने पर विश्वविद्यालय का प्रबंधन,
- (2) इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर विनियामक आयोग जो यह अधिकार होगा कि वह प्रायोजक निकाय को ऐसा निर्देश दे जो उपचारा । के अंतर्गत निर्भारित योग्यियों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो, यदि प्रायोजक निकाय उपचारा । के तहत निर्भारित प्रायोजकों का उल्लंघन करता है तो विनियामक आयोग विचार निधि को समरप्त कर लेगा और पाठ्यक्रम पूरा करने, परीक्षा संचालन, उपाधि देने जादि के संबंध में या ही स्वयं कार्य करने या यह कार्य किसी अन्य विश्वविद्यालय को सौंधने संबंधी व्यवस्था इस प्रकार नहीं जाएगा कि विद्यार्थियों के लिए निसी तरह प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हों विद्यार्थियों के लिए की गई इन व्यवस्थाओं पर जो व्यव होगा, उसे विचार निधि एवं/या विश्वविद्यालय की समाज निधि से पूरा किया जाएगा।
41. (1) यदि विनियामक आयोग के प्रतिवेदन पर वा अन्यथा राज्य शासन को यह प्रतीत हो कि इस अधिनियम के अंतर्गत जारी ऐसे निसी निर्देश का विश्वविद्यालय द्वारा उल्लंघन किया गया है या विश्वविद्यालय में विभिन्न तभा प्रशासनिक कुश्वारपन की विधि तत्वज्ञ हो गई है तो वह निझी विश्वविद्यालय को 45 दिन तक कारण जाहाजो मृद्दना, इस आशाग का जारी कोरा किए :
- (क) जबों न उसके परिसमापन का आदेश प्रसारित किया जावे,
- (ख) जबों न उपचारा (7) के अंतर्गत प्रबंध मंडल को निलंबित कर, प्रशासन के नियुक्त कर दिया जावे.
- (2) यदि राज्य शासन की यह घारणा नहीं है कि उल्लिखित जांच के लिये प्रबंध मंडल को निलंबित करना आवश्यक है, तो वह राज्यवत्र में अधिकृत प्रकाशित कर, प्रबंध मंडल को विलंबन के आदेश देगा और प्रायोजक निकाय के पारम्परा से निझी विश्वविद्यालय के कार्यों के संचालन हेतु जांच पूर्ण होने की अवधि के लिए ऐसी व्यवस्था करेगा जैसी कि वह आवश्यक समझे।
- (3) निझी विश्वविद्यालय को उपचारा (1) के तहत जारी की गई सूचना का उत्तर प्राप्त कर यदि इस बात का समाधान हो जाता है कि प्रथम इस प्रकारण, कुश्वारपन, कुप्रशासन या अधिनियम के प्रावधानों या उसके अंतर्गत जारी किये गये निर्देशों के उल्लंघन का है, तो वह ऐसी जांच के आदेश प्रसारित कोरा जो आवश्यक हो।
- (4) उपचारा (3) के अंतर्गत एन्ड शासन किसी भी आदेश की जांच के लिए कोई अधिकारी अपना ग्राहिकारी नियुक्त करेगा और उसे जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की कठोरा।
- (5) उपचारा (4) के अंतर्गत नियुक्त जांच अधिकारी को वे सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जैसा कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का क्र. 40) के अंतर्गत नियमांकित मामलों के संबंध में निसी वाद के निराकरण हेतु आवश्यक हों यथा-

(क) गवाहों को समस्त जारी करने तथा उनके उपस्थित होने के लिए बाध्य करना तथा किसी व्यक्ति का शपथ पर परिवार करना,

(ख) किसी दस्तावेज अथवा अन्य सामग्री जो साक्ष में प्रस्तुत की जा सकती हो, का अन्वेषण प्रस्तुत किया जाना,

(ग) किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से सार्वजनिक अधिकारी अधिकारी भूमिका जाना,

(घ) अन्य कोई निन्दा जो निर्धारित की जाये,

(6) इस अधिनियम के अंतर्गत बीच कर रहे प्राप्तकर्ता अधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (सन् 1974 का अ. 2) की घारा 195 तथा अध्याय 26 के प्रयोगन हेतु व्यवहार न्यायालय जाना जावेगा,

(7) बीच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत बदि राज्य शासन संतुष्ट होता है तो वित्तीय कुशलंगन और कुश्रासन के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि निजी विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिता या प्रशासन असुरक्षित हो गया है तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निजी विश्वविद्यालय को विधायित करने का आदेश देगा अथवा निजी विश्वविद्यालय की गतिविधियों को बलाचे रखने हेतु एक प्रशासक को नियुक्त कर सकेगा जिसे शासी निकाय के सभी अधिकार प्राप्त होंगे।

पांचवटक का कोई आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक ऐसे विश्वविद्यालय से संबंधित प्रतिवेदन को अधिनियम की अनुरूपी से हटा न दिया जाये।

(8) उपरांत (7) के अंतर्गत स्थापन की अधिसूचना प्रसारित करने के समय राज्य शासन वर्तमान पाठ्यक्रम की समाप्ति के अंत तक कार्य निधानों के अनुबंध विश्वविद्यालय प्रशासन के संचालन हेतु व्यवस्था करेगा।

(9) उपरांत (8) के अंतर्गत विश्वविद्यालय की व्यवस्था की अवधि में राज्य शासन द्वारा विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध राशि का उपयोग किया जायेगा तथा अधिरिक राशि बदि कोई हो तो स्वयं के हेतु जब्त किया जायेगा।

(10) बीच की प्रक्रिया में और विद्यार्थियों के प्रवेश पूर्ण होते तक हुए सभी व्यय विश्वविद्यालय के विनास निधि और सामान्य निधि से पूर्ण किये जायेंगे।

#### अध्याय-छ: : प्रक्रीण

विषय बनारे की शक्ति:

42. (1) राज्य शासन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियम बना सकेगी।

(2) ऐसे नियम विशेषता और पूर्ववर्ती गति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव दाले जिन नियन्त्रिति बातों के बारे में सभी अथवा किसी का प्रावधान होगा जब्त-

(क) निजी विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी प्रस्ताव की प्रक्रिया तथा घारा 4 की उपरांत देव शुल्क,

(ख) घारा 4 की उपरांत (2) के अंतर्गत परिवोजना प्रतिवेदन में निहित अन्य विवरण,

- (ग) धारा 11 की उपधारा (3) के अंतर्गत विवास निपि के स्थापना की विधि, यांत्रि के विविहोजन की विधि, प्राप्त आय की प्राप्तोजक निकाय वा भुगतान की विधि, उसके सम्बन्धित करने की विधि तथा उसका उपयोग करने की विधि,
- (द) धारा 12 (3) के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालय से प्राप्त शुल्क और इस प्रकार संकेतित राशि को संबंधित विधि में जगा करने की विधि,
- (इ) धारा 26 की उपधारा (1) के अंतर्गत अन्य विषय, जिनका प्रबोधन संबंधित द्वारा किया जाना है,
- (ब) अध्यात्म तथा महात्मों की सेवा-शर्तों आयोग की बैठकों की विधि एवं आयोग के कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी सेवा-शर्तों किसी विशेष प्रयोजन के लिए आयोग के कार्यों से व्यक्तियों को बोझना आयोग कि नियमों, इसके बजाए, वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा तथा अकेडम और इस प्रकार की अन्य बार्ताएँ जो अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (9) के अधीन आयोग के समुचित क्रमों के लिए अप्रीतित हैं,
- (क) इस अधिनियम के नियम द्वारा निर्धारित अन्य कोई बिन्दु जो आवश्यक हैं या हो सकते हैं,
- (3) इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये प्रत्येक नियम एवं विधान मंडल के समझ एवं जावेंगे।
43. यदि इस अधिनियम के उपांगों को लागू करने में कोई कठिनताएँ आती हैं तो राज्य सरकार इस अधिनियम के उपरंभ के असंगत दैसा आवश्यक समझे या कठिनाईयों को दूर करने के लिए समीक्षीय हो, राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर ऐसे प्रबोधन कर सकती है।
44. छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और नियन्त्रण) अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम-2) एवं इस अधिनियम के प्रभावकालीन होने के ठीक पहले तक, यदि कोई आदेश, नियम या संकलन हो तो जैसी भी स्थिति हो ये इसके उपरान्त, विरुद्धित या निरस्त माने जावेंगे।

अन्तर्गती

| पारा १० (१) के अंतर्गत |

राजसुर, दिनांक 24 अगस्त, 2005

क्रमांक 6886/21-अ/प्राप्तिया/04.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसार मैं शासीमाल निवी विस्तृतविद्यालय (स्थाना और संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 मद् 2005) का अंगेजी अनुबाद राष्ट्रपति के प्राधिकरण से एकदृष्ट प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राम्बपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव,

**CHHATTISGARH ACT  
(No. 13 of 2005)**

**CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND OPERATION) ACT, 2005**

**INDEX**

Section	Contents	Page No.
---------	----------	----------

**CHAPTER-I**

**PRELIMINARY**

- 1. Short title, extent and commencement
- 2. Definitions

**CHAPTER-II**

**ESTABLISHMENT OF PRIVATE UNIVERSITY**

- 3. Objects of the Private University
- 4. Submission of Proposal for establishment of a Private University.
- 5. Evaluations of the proposal
- 6. Issuing letter of Intent
- 7. Conditions for establishing a Private University
- 8. Submission of Compliance Report, Verification and Inspection
- 9. Establishment and Incorporation

**CHAPTER-III**

**OPERATION AND MANAGEMENT OF PRIVATE UNIVERSITY**

- 10. Private University to be self-financed
- 11. Endowment Fund
- 12. General Fund
- 13. Application of General Fund
- 14. Officers of the University
- 15. The Visitor
- 16. The Chancellor
- 17. The Vice-Chancellor
- 18. The Registrar
- 19. The Chief Finance and Accounts Officer
- 20. Other Officers
- 21. Authorities of the University
- 22. The Governing Body
- 23. The Board of Management

- 
24. The Academic Council  
 25. Other Authorities  
 26. The First Statutes  
 27. The Subsequent Statutes  
 28. The First Ordinances  
 29. The Subsequent Ordinances  
 30. Vacancies not to invalidate the proceedings of any Authority or Body of the University.  
 31. Filling up of emergent vacancies  
 32. Committee  
 33. Mode of proof of University Record  
 34. Regulations  
 35. Enforcement of Statute, Ordinance and Regulation

**CHAPTER-IV****REGULATION OF PRIVATE UNIVERSITY**

36. Regulatory Commission  
 37. Annual Report  
 38. Annual Accounts and Audit  
 39. Periodic Inspection

**CHAPTER-V****WINDING OF PRIVATE UNIVERSITY**

40. Management of University on dissolution  
 of Sponsoring Body.  
 41. Special Powers of the State Government in certain circumstances.

**CHAPTER-VI****MISCELLANEOUS**

42. Power to make Rules  
 43. Power to remove difficulties  
 44. Repeal and Savings

**CHHATTISGARH ACT  
(No. 13 of 2005)**

**CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND OPERATION) ACT, 2005**

An Act to provide for establishment and for incorporation of self-financed Universities in the State of Chhattisgarh for imparting Higher Education, and to regulate their functions and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the fiftysixth year of the republic of India as follow :

**CHAPTER - I : PRELIMINARY**

- |  |  |
|--|--|
| <p>1. (1) This Act may be called the "CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND OPERATION) ACT, 2005."</p> <p>(2) It extends to whole of the State of Chhattisgarh.</p> <p>(3) It shall come into force on date of its publication in the Official Gazette.</p> <p>2. In this Act, unless the context otherwise requires :-</p> <p>(1) "Academic Council" means Academic Council of the private university.</p> <p>(2) "All India Council of Technical Education" means All India Council of Technical Education established under All India Council of Technical Education Act, 1987 (Central Act No. 52 of 1987).</p> <p>(3) "Bar Council of India" means Bar Council of India constituted under Section 4 of the Advocates Act, 1961 (No. 25 of 1961).</p> <p>(4) "Board of Management" means Board of Management of the private university.</p> <p>(5) "Chancellor" means Chancellor of the private university.</p> <p>(6) "Chief Finance and Accounts Officer" means Chief Finance and Accounts Officer of the private university.</p> <p>(7) "Distance Education Council" means Distance Education Council established under Section 28 of Indira Gandhi National Open University Act, 1985 (No. 50 of 1985).</p> <p>(8) "Endowment Fund" means Endowment Fund of the Private University.</p> <p>(9) "Fee" means collection made by the private university from the students, by whatever name it may be called.</p> <p>(10) "Government" means Government of Chhattisgarh.</p> <p>(11) "Governor" means Governor of Chhattisgarh.</p> <p>(12) "Governing Body" means Governing Body of the private university.</p> <p>(13) "Higher Education" means study of curriculum or course for the pursuit of knowledge beyond 10+2 level.</p> <p>(14) "Medical Council of India" means Medical Council of India constituted under the Indian Medical Council Act, 1956 (No. 2 of 1956).</p> <p>(15) "Main Campus" means Main Campus of the private university situated</p> | <p><b>Short title, extent and commencement.</b></p> <p><b>Definitions.</b></p> |
|--|--|

in Chhattisgarh, consisting of minimum five university teaching departments/schools of studies and where Vice-Chancellor and Registrar reside and also the main office of the private university is located.

- (16) "National Council of Assessment and Accreditation" means the National Council of Assessment and Accreditation, Bangalore, an autonomous institution of UGC.
- (17) "Off-Campus Centre" means centre of the private university established outside the main campus but within the State, operated and maintained as its constituent unit.
- (18) "Ordinance" means Ordinance of the private university.
- (19) "Other Backward Class" means Other Backward Classes which may be declared by the State Government from time to time by Notification.
- (20) "Private University" means a private university established and incorporated under this Act.
- (21) "Pharmacy Council of India" means Pharmacy Council of India constituted under the Pharmacy Act, 1948 (No. 8 of 1948).
- (22) "Regulatory Body" means a Central or a State Regulatory Body established by the Central or State Government for laying down norms and conditions for ensuring standards of higher education.
- (23) "Regulatory Commission" means Commission established under Section 36 of this Act.
- (24) "Regulations" means Regulations made under the provisions of the Act.
- (25) "Registrar" means Registrar of the private university.
- (26) "State" means State of Chhattisgarh.
- (27) "Study Centre" means centre established in the State and maintained by the private university for the purpose of advising, counseling or for rendering any other assistance required by the students in the context of distance education which implies imparting education by combination of any two or more means of communication, viz. broadcasting, telecasting, correspondence courses, seminars, contact programmes and any other such methodology.
- (28) "Statute" means Statute made under the provisions of the Act.
- (29) "Sponsoring Body" in relations to a private university means :-
  - (a) A Society registered under Chhattisgarh Societies Registration Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973);
  - (b) Any registered Public Trust;
  - (c) A Company registered under Section 25 of the Company Act 1956 (No. 1 of 1956); and
  - (d) Any other body registered under any Act time being in force.
- (30) "Student" means a person enrolled in the private university for pursuing a course of study for the award of a degree / diploma / certificate or other academic distinction.
- (31) "Schedule" means Schedule appended to the Act.
- (32) "Scheduled Caste" means the Scheduled Castes specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India.

- (33) "Scheduled Tribe" means the Scheduled Tribes specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India.
- (34) "School of Studies" means an institution maintained by private university as a place of the higher learning and research.
- (35) "Teacher" means a Professor, Reader, Lecturer or a person known by any other designation who is required to impart education or to guide research or to render guidance to the students for pursuing a course of study of the university.
- (36) "University Grants Commission" means the Commission established under the University Grants Commission Act, 1956 (No. 3 of 1956).
- (37) "UGC REGULATIONS, 2003" means UGC (Establishment of and Maintenance of Standards in Private Universities) Regulations, 2003.
- (38) "Visitor" means Visitor of the private university.
- (39) "Vice-Chancellor" means Vice-Chancellor of the private university.
- (40) "BPL Family" means a family whose income is below the poverty line as specified by the Government from time to time.

#### **CHAPTER - II : ESTABLISHMENT OF PRIVATE UNIVERSITY**

3. The following shall be the general objects of the private university :-
- (a) To provide instructions, teaching and training in Higher Education and make provisions for research, advancement and dissemination of knowledge.
  - (b) To create higher levels of intellectual abilities.
  - (c) To establish state of the art facilities for education and training.
  - (d) To carry out teaching and research and offer continuing education programmes.
  - (e) To create centers of excellence for research and development and for sharing knowledge and its application.
  - (f) To provide consultancy to the industry and public organizations.
  - (g) To maintain the standard of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions in accordance with the norms laid down by UGC, AICTE, BCI, MCI, DEC, or any other Regulatory Body.
  - (h) To pursue any other objective as may be approved by the State Government based on the recommendations of the Regulatory Commission from time to time.
4. (1) An application containing the proposal and the project report to establish a private university for carrying out the objectives enumerated in Section 3 of this Act shall be made by the sponsoring body, to the Regulatory Commission along with such fee and in such form with the project report as may be prescribed.
- (2) The project report shall contain the following particulars, namely :-
- (a) the details of the sponsoring body along with the copies of its registration certificate, constitution and bye-laws;

*Objects of the private university.*

*Submission of proposal for establishment of a private university.*

- (b) the information regarding financial resources of the sponsoring body along with audited accounts for past three years;
- (c) the name, location and main campus of the proposed private university;
- (d) the objectives of the private university ;
- (e) availability of land, and details of buildings and infrastructure facilities;
- (f) the details of plans for campus development such as construction of buildings, development of structural amenities and infrastructural facilities and procurement of equipment etc., to be undertaken before the private university starts functioning, and the phase-wise programme for five years;
- (g) phased outlays of capital expenditure proposed for five years and its sources of finance;
- (h) the nature and the number of faculties such as Science, Arts, Commerce, Technology, Education etc., types of programmes (under graduate / post graduate) of study and research proposed to be undertaken by the private university in each faculty, and their relevance to the developmental goals of the state, and phasing of such programmes for five years with coursewise enrolment targets;
- (i) the experience and expertise in the concerned disciplines at the command of the sponsoring body;
- (j) availability of academic facilities such as teaching staff, technical / non technical staff, equipments etc., required for the courses of study and research;
- (k) the estimated recurring expenditure coursewise or activity-wise, sources of finance and estimated expenditure per student;
- (l) the scheme for mobilizing resources and the cost of capital thereto and the manner of repayment to such sources;
- (m) the scheme for generation of funds internally through the recovery of fee from students, revenues anticipated from consultancy services and other activities relating to the objects of the private university, and other anticipated income;
- (n) the proposed fee structure for the different courses, with reference to the details of expenditure on unit cost and the extent of concessions or rebates in fee or free-ships and scholarships, if any, for the students belonging to scheduled caste, scheduled tribe, other backward classes and BPL families;
- (o) the system proposed to be followed for selection of students for admission to the courses of study at the private university;
- (p) the system proposed to be followed for appointment of teachers and other employees at the private university;
- (q) details of distance education programme with proposed study centres;
- (r) programmes related to local needs, the nature of specialized teaching, training or research activities;
- (s) programmes for the benefit of farmers, women and industries especially located in this State;
- (t) details of play grounds and other facilities available or proposed to be created for games and sports and extra curricular activities like National Cadet Corps, National Service Scheme, Scouts and Guides etc;

- (ii) establishment of off-campus centres and study centres specially in the Scheduled areas of the state;
- (v) justification regarding the necessity of establishing the proposed private university.
5. (1) The Regulatory Commission shall, on receipt of the proposal and the project report for establishment of a private university, make such scrutiny, as far as possible within 7 days from the receipt of proposal as to the facts stated in the project report, as it may deem necessary.
- (2) The Regulatory Commission in course of scrutiny may ask for any additional information from the sponsoring body, and after receipt of such information, the Regulatory Commission shall evaluate the project proposal as far as possible, within 45 days. In the course of evaluation, the Regulatory Commission shall take into consideration, the following :-
- (a) existing facilities for higher education and research in the area in which the private university is proposed to be established;
  - (b) the proposed private university has some special features or new programmes and activities which will augment the existing academic resources in the State and help in human resource development;
  - (c) the private university shall have programmes for the upliftment of backward areas or removal of regional imbalances by starting off campus centres in the Scheduled areas of the state;
  - (d) the main motive for establishment of the private university is of social service and welfare of youths by providing them high quality education.
6. (1) After inquiry and evaluation as provided in Section 5, if Regulatory Commission is of opinion that an opportunity to establish a private university be given to the Sponsoring Body, it shall make its recommendation to the state government to issue a *Letter of Intent* to the sponsoring body in this regard.
- (2) After receiving the recommendation from Regulatory Commission, State Government may issue letter of intent to the Sponsoring Body with regard to establishment of private university in the State.
7. The letter of intent as provided under Section 6 (2) shall contain the following conditions, which the sponsoring body will be required to fulfill for establishing a private university in the State ; namely :-
- (1) It shall establish :-
    - (a) the main campus, off-campus centres and study centres within the state;
    - (b) an *endowment fund* in accordance with the provisions of Section 11 of the Act.  - (2) It shall procure a minimum :-
    - (a) 15 acres land in case the main campus is proposed to be established within the Municipal Corporation limits of Raipur.
    - (b) 25 acres of land in case the main campus is proposed to be established at any other place; and submit its ownership papers.  - (3) It shall make available a *minimum built up area of 25,000 square feet* in the form of buildings, and ancillary structures for administrative purposes and for conducting the academic programmes.

Evaluation of the  
Proposal.Issuing Letter of  
Intent.Conditions for  
establishing a private  
university.

- (4) It shall give an undertaking :-
- (a) that the land and buildings of the private university shall be used for the purpose of the private university only;
  - (b) further, to appoint immediately after incorporation of the private university and before starting of the classes, adequate number of faculty members along with necessary supporting staff in each department or discipline;
  - (c) to procure equipments, computers, furniture, and other essential items and invest a minimum of Rs.20 lacs per year during first five years;
  - (d) to purchase books and journals at least worth Rs.10 lacs in the first year and to invest not less than Rs. 50 lacs on books, journals, computer networking and other facilities to make the library facilities adequate for contemporary teaching and research within first three years;
  - (e) to take up co-curricular activities to foster a proper academic and healthy environment, such as seminars, debates, quiz programmes and extracurricular activities like games, sports, National Service Scheme, National Cadet Corps etc., for the benefit of students as per the norms laid down by the regulatory bodies;
  - (f) to establish welfare programmes for the employees of the private university;
  - (g) to fulfill such other conditions and provide such other information as may be prescribed by the central regulatory bodies from time to time;
  - (h) to fulfill the minimum criteria in terms of programmes, faculty, infrastructural facilities, financial viability etc., as laid down from time to time by the regulatory bodies;
  - (i) that the programmes of study leading to a degree and / or a postgraduate degree/diploma offered by a private university shall conform to the relevant regulations/norms of the UGC or the concerned statutory bodies as amended from time to time;
  - (j) that the admission procedure and fixation of fees shall be in accordance with the norms / guidelines, if any, prescribed by the regulatory bodies;
  - (k) that the teaching staff of the private university shall have at least the minimum qualifications prescribed by the U.G.C. or other concerned regulatory bodies, and be paid appropriate emoluments;
  - (l) that the private university shall be open to all persons of either sex, and it shall not discriminate on grounds of caste, creed, religion, race, and it shall not be lawful for the private university to adopt or impose on any person, any test whatsoever of religious belief or any profession in order to entitle him to be appointed as a teacher of the private university or to hold any other office therein or to be admitted as a student or to enjoy or exercise any privilege thereof;
  - (m) that the admissions and conduct of classes shall not be started till concerned Statutes, Ordinances are approved as per provisions of this Act.

**Submission  
Compliance  
Verification  
Inspection.**

**of  
Report,  
and**

**8. (1)**

The sponsoring body shall submit the Compliance Report and an undertaking alongwith the relevant documents to the Regulatory Commission.

- (2) After receiving the Compliance Report from the sponsoring body, the Regulatory Commission shall examine the same and factual data in the manner it may deem fit, including spot inspection.
- (3) The Regulatory Commission, after examination of the Compliance Report and the Undertaking as mentioned under Sub-section (2) above, finds any shortcomings in the same, it may direct the sponsoring body to remove the identified shortcomings at the earliest.
- (4) The Regulatory Commission on being satisfied that the identified shortcomings, as mentioned under Sub-section (3) above, have been removed, it shall send its report regarding status of the proposal for establishment of the private university to the State Government within 15 days from the date of receipt of the report from sponsoring body regarding removal of identified shortcomings.
- (5) The State Government may, after the receipt of the report from the Regulatory Commission mentioned under Sub-section (4) above, ask the University Grants Commission for inspection of the proposed private university.

Provided that University Grants Commission shall submit the report within a maximum period of three months, or else, the state government may take such decision as it may deem fit.

- 9. (1) The State Government, if satisfied considering the report submitted by the Regulatory Commission under Section 8 and Inspection Report of the UGC, if any, that the Sponsoring Body has complied with the provisions of Section 7 and a private university may be established on the basis of its proposal, shall establish, by amending the Schedule appended to this Act, a private university with such name and description as may be specified in this behalf.
  - (2) Such a private university shall be deemed to have been incorporated from the date of the amendment in the schedule in this behalf.
- Provided that, the period between the date of incorporation as mentioned under sub-section (2) above, and the date of submission of the application mentioned under sub-section (1) of section 4, shall not be more than 6 months.
- (3) The private university shall be a body corporate by such name, as shown in the Schedule, having perpetual succession, and common seal with powers subject to the provisions of this Act, to acquire and own property, to contract, and shall sue and be sued by the said name.
  - (4) In all the suits and other legal proceedings by or against such private university, the pleadings shall be signed and verified by the Registrar and all processes in such suits and proceedings shall be issued to and be served on the Registrar.
  - (5) The main campus of the private university shall be at such place as shown in column 5 of the Schedule

Establishment and Incorporation.

### CHAPTER - III : OPERATION AND MANAGEMENT OF PRIVATE UNIVERSITY

- 10. The private university shall be self-financed. However, the Government may consider providing it financial/physical incentives for reasons to be recorded in writing.

Private university to be self-financed.

- Endowment Fund.** 11. (1) On receipt of the letter of intent from the State Government as provided under Section 6 (2) above, a sponsoring body willing to fulfill the conditions and give undertakings as mentioned in the letter of intent, shall establish an endowment fund for the private university by depositing the amount in the Fund of the Regulatory Commission, in the manner prescribed, as under : -
- (a) *One crore rupees* in case the private university is to be established in a Scheduled Area of the State.
  - (b) *Three crore rupees* in other cases;
- Provided that any deposit in the endowment fund prior to the commencement of this Act by the sponsoring body shall be adjusted.
- (2) The endowment fund shall be used as security deposit to ensure that the private university complies with the provisions of the Act, Statutes and Ordinances. The State Government may forfeit, after giving notice, whole or part of endowment fund on the recommendation of the Regulatory Commission in case of a breach or contravention of any provisions of the Act, Statute, Ordinance, or Regulations by the sponsoring body.
- (3) The mode of establishment of endowment fund, the manner of its investment, the payment of income from it to the sponsoring body, its forfeiture and mode of its return to the sponsoring body shall be such, as may be prescribed.
- General Fund.** 12. Every private university shall establish a fund, which shall be called the general fund to which the following shall be credited, namely :-
- (a) fees and other charges received by the private university;
  - (b) any contribution made by the sponsoring body;
  - (c) any income received from consultancy and other work undertaken by the private university in pursuance of its objectives;
  - (d) trusts, bequests, donations, endowment and any other grants; and,
  - (e) all other sums received by the private university.
- Provided that one percent of the fees collected from the students under clause (a), shall be deposited through bank draft/banker's cheque with the Regulatory Commission within 15 days of the month next to the month in which such fees are received. If private university fails to deposit fees within stipulated period then it shall be liable to pay such fee with penal interest at the rate of 1.5% for every 30 days. If default continues further beyond 90 days, this would tantamount to violation of the Act for which necessary action may be taken by the Regulatory Commission.
- Provided further that the Regulatory Commission shall credit this amount to the Consolidated Fund of the State in due course.
- Application  
General Fund.** 13. The General Fund shall be utilized for the following purposes, namely :-
- (1) repayment of debts including interest charges thereto incurred by the university for the purposes of this Act and the Statutes, Ordinances and Regulations made thereunder;
  - (2) for upkeep of the assets of the private university;
  - (3) for the payment of the cost of audit of the funds created under Sections 11 and 12;

- (4) meeting expenses of any suit or proceedings in the Court to which university is a party;
  - (5) for payment of salaries and allowances of the officers and employees of the private university and members of the teaching and research staff, and for payment of any provident fund contributions, gratuity and other benefits to any such officers and employees, and members of the teaching and research staff;
  - (6) for payment of travelling and other allowances of the members of the Governing Body, the Board of management, the Academic Council and other authorities so declared under the Statutes of the private university, and to the members of any committee appointed by any of the authorities or by the Chairperson of the sponsoring body or the Vice-chancellor, in pursuance of any provision of the Act, Statute, Ordinances, or the Regulations made thereunder;
  - (7) for the payment of fellowships, free-ships, scholarships, assistantships and other awards to the students belonging to BPL families or research associates or trainees as the case may be, or to any student otherwise eligible for such awards under the Statutes, Ordinances, Regulations or Rules of the private university made under the provisions of this Act;
  - (8) for the payment of any expenses incurred by the private university in carrying out the provisions of this Act, and the Statutes, Ordinances, or the Regulations made thereunder;
  - (9) for payment of cost of capital, not exceeding the prevailing bank rates of interest, incurred by the sponsoring body for setting up the private university and the investments made there for;
  - (10) for payment of charges and expenditure relating to the consultancy work undertaken by the private university in pursuance of the provisions of this Act and the Statutes, Ordinances and the Regulations made thereunder;
  - (11) for the payment of any other expenses including service fee payable to any organization charged with the responsibility of providing any specific service, including the managerial services to the private university, on behalf of the sponsoring body, as approved by the Board of Management to be an expense for the purposes of the private university;
- Provided that no expenditure shall be incurred by the private university in excess of the limits for total recurring expenditure and total non-recurring expenditure for the year, as may be fixed by the Board of Management, without the prior approval of the Board of Management;
- Provided further that the general fund shall not be utilized for the objects specified under sub-section (1), without the prior approval of the Governing Body of the private university.

14. The following shall be the officers of the private university, namely :-
1. The Visitor;
  2. The Chancellor;
  3. The Vice-chancellor;
  4. The Registrar;
  5. The Chief finance and Accounts Officers;
  6. Such other officers as may be declared by the Statutes to be the officers of the University.

Officers of the  
University.

- The Visitor.**
15. (1) The Governor of Chhattisgarh shall be the Visitor of the private university.
- (2) The Visitor shall, when present, preside at the convocation of the private university for conferring degrees and diplomas.
- (3) The Visitor shall have the following powers, namely :-
- (a) to appoint Vice-chancellor,
  - (b) to call for any paper or information relating to the affairs of the private university
  - (c) if it appears on the basis of the information that any order, proceeding or decision taken by any authority of the private university is not in conformity with the provisions of this Act, Statutes, Ordinances or Regulations made thereunder, Visitor may ask for the opinion of the Regulatory Commission. On being satisfied that certain irregularity has taken place, he may issue such directions as he may deem fit in the interest of the private university and the directions so issued shall be complied with by the private university.
  - (d) to institute inquiry against the Vice-chancellor, on the report of the Chancellor or otherwise.
- The Chancellor.**
16. (1) The Chancellor shall be appointed by the sponsoring body for a period of three years with the approval of the Visitor.
- Provided that, for establishing the private university and making it functional, the sponsoring body shall appoint the Chancellor in consultation with the State Government for a minimum period of one year, but not exceeding three years.
- (2) The Chancellor shall be the head of the private university.
- (3) The Chancellor shall preside over the meetings of the Governing Body and shall, when the Visitor is not present, preside over the convocation of the private university for conferring degrees, diplomas or other academic distinctions.
- (4) The Chancellor shall have the following powers, namely :-
- (a) to call for any information or record,
  - (b) to report to the Visitor for removal of the Vice-chancellor, if he is satisfied on the basis of complaints that the Vice-chancellor has acted in violation of the Act, statutes or ordinances of the private university, or committed financial irregularity.
- The Vice-Chancellor.**
17. (1) The Vice-chancellor shall be appointed by the Visitor from the panel recommended by the Search Committee constituted for the purpose.
- (2) The Search Committee referred to in Sub-section (1) shall consist of the following :-
- (i) Two eminent academicians nominated by the Sponsoring Body.
  - (ii) One eminent person nominated by the State Government in higher education department.
- The Visitor shall appoint one of the members of the Search Committee as Chairman.
- (3) The Search Committee shall submit a panel of at least three eminent academicians for the appointment of Vice Chancellor.
- Provided that if the Visitor does not approve the recommendation of the

Search Committee, he may call for fresh recommendation from the Committee.

Provided further that the Vice Chancellor, to carry out the business of newly established private university, shall be appointed by the Visitor on the advice of the Chancellor for a period of 2 years.

- (4) The Vice-chancellor shall, subject to the provision contained in subsection (10), hold office for a term of four years.

Provided that, a Vice-chancellor shall continue to hold the office even after expiry of his term till a new Vice-chancellor joins. However, in any case this period shall not exceed 6 months.

- (5) The Vice-chancellor shall be the principal executive and academic officer of the private university, and shall exercise general superintendence and control over the affairs of the private university and shall execute the decisions of various authorities of the private university.

- (6) The Vice-chancellor shall preside at the convocation of the private university in the absence of the Visitor and the Chancellor.

- (7) If in the opinion of the Vice-chancellor it is necessary to take immediate action on any matter for which powers are conferred on any other authority by or under this Act, he may take such action as he deems necessary, and shall at the earliest opportunity thereafter report his action to such officer or authority as would have in the ordinary course dealt with the matter;

Provided that if in the opinion of the concerned officer or authority such action should not have been taken by the Vice-chancellor then such case shall be referred to the Chancellor, whose decision thereon shall be final;

Provided further that where any such action taken by the Vice-chancellor affects any person in the service of the university, such person shall be entitled to prefer, within three months from the date on which such action is communicated to him, an appeal to the Governing Body. The decision of the Governing Body shall be communicated to the person concerned within a maximum period of three months from the date of appeal.

- (8) If, in the opinion of the Vice-chancellor any decision of any authority of the private university is not in conformity with the powers conferred by this Act, Statutes, Ordinances, or Regulations made there under, or is likely to be prejudicial to the interests of the private university, he shall request the concerned authority to revise its decision. In case the authority refuses to revise such decision wholly or partly or fails to take any decision within fifteen days, then such matter shall be referred to the Chancellor and his decision thereon shall be final, which will be reported to the Governing Body for ratification.

- (9) The Vice-chancellor shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes and the Ordinances.

- (10) If at any time upon representation made or otherwise, it appears to the Visitor that the Vice Chancellor

- (a) has made default in performing any duty imposed on him by or under this Act, or
- (b) has acted in a manner prejudicial to the interest of the private university, or

- (c) is incapable of managing the affairs of the private university, the Visitor may notwithstanding the fact that the term of office of Vice Chancellor has not expired, by an order, in writing, stating the reasons therein, require Vice Chancellor to relinquish his office as from such date as may be specified in the Order.
- (II) No Order under sub-section (10) shall be passed unless the particulars of the grounds on which such action is proposed to be taken are communicated to the Vice Chancellor and he is given reasonable opportunity of showing cause against the proposed order.
- (12) As from the date specified in the Order under sub-section (10), Vice Chancellor shall be deemed to have relinquished the office and the office of Vice Chancellor shall fall vacant.
- The Registrar.**
18. (1) The appointment of the Registrar shall be made by the Governing Body on the recommendation of the experts committee constituted for the purpose, as prescribed by the Statutes. However, the first registrar shall be appointed by the sponsoring body for a period of 2 years.
- (2) All contracts shall be signed and all documents and records shall be authenticated by the Registrar on behalf of the private University.
- (3) The Registrar shall be the Member-secretary of the Governing Body, Board of Management and Academic Council but he shall not have a right to vote.
- (4) The Registrar shall exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed by the Statutes.
- (5) If at any time upon representation made or otherwise, and after making such inquiry as may be deemed necessary, the situation so warrants that the continuance of the Registrar is not in the interest of the private university, the Vice-chancellor may request the Chancellor, in writing stating the reasons therein, for the removal of the Registrar.
- Provided that before taking an action under this sub-section, the Registrar shall be given an opportunity of being heard.
- The Chief Finance and Accounts Officer.**
19. (1) The appointment of the Chief Finance and Accounts Officer shall be made by the Chancellor as may be prescribed by the Statutes.
- (2) The Chief finance and Accounts Officer shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes.
- Other Officers.**
20. (1) The private university may appoint such other officers as may be necessary for its functioning.
- (2) The manner of appointment of other officers of the private university and their powers and functions shall be such as may be prescribed by the Statutes.
- Authorities of the University.**
21. (1) The following shall be the authorities of the private university, namely :-
- the Governing Body;
  - the Board of Management;
  - the Academic Council;
  - such other authorities as may be created by the Statutes shall be the authorities of the private university.
- (2) The term of the nominated members on the Governing Body and the Board of Management shall be three years. No nominated member shall be nominated for more than two consecutive terms.

22. (1) The Governing Body of the university shall consist of the following, The Governing Body.  
 namely :-
- (a) the Chancellor;
  - (b) the Vice-chancellor;
  - (c) three eminent persons nominated by the sponsoring body out of whom at least one shall be noted educationist;
  - (d) three distinguished persons nominated by the Visitor out of a panel of six names submitted by the State Government;
  - (e) one representative of the State Government, not below the rank of Deputy Secretary.
- (2) The Chancellor shall be the ex-officio Chairman of the Governing Body.
- (3) The Governing Body shall be the highest authority of the university. All the movable and immovable property of the university shall vest in the Governing Body. It shall have following powers, namely :-
- (a) to provide general superintendence and directions and to control functioning of the private university by using all such powers as are provided by this Act or the Statutes, Ordinances or Regulations made thereunder;
  - (b) to review the decisions of other authorities of the private university in case they are not in conformity with the provisions of this Act or the Statutes, Ordinance, or Regulations made thereunder;
  - (c) to approve the budget and annual report of the private university;
  - (d) to lay down the policies to be followed by the private university;
  - (e) to recommend to the sponsoring body about the voluntary liquidation of the private university if a situation arises when smooth functioning of the private university is not possible;
  - (f) such other powers as may be prescribed by the Statutes.
- (4) The Governing Body shall meet at least three times in a calendar year,
- (5) The quorum for meetings of the Governing Body shall be five.
23. (1) The Board of Management shall consist of the following members, The Board of Management.  
 namely :-
- (a) the Vice-chancellor;
  - (b) two representatives nominated by the sponsoring body;
  - (c) two representatives nominated by the State Government;
  - (d) two senior most professors of the private university by rotation;
  - (e) two senior most teachers of the private university, other than in sub-section (I) (d), by rotation.
- (2) The Vice-chancellor shall be the ex-officio Chairperson of the Board of Management.
- (3) The powers and functions of the Board of Management shall be such as may be prescribed by the Statutes.
- (4) The Board of Management shall meet at least once in every two months
- (5) The quorum for meetings of the Board of Management shall be five.

- |                            |                 |  |
|----------------------------|-----------------|--|
| <b>The Council.</b>        | <b>Academic</b> | 24. (1) The Academic Council shall consist of the Vice-chancellor and such other members as may be prescribed by the Statutes.<br>(2) The Vice-chancellor shall be the Chairperson of the Academic Council.<br>(3) The Academic Council shall be the principal academic body of the private university and shall, subject to the provisions of this Act, Statutes, Ordinances and Regulation, co-ordinate and exercise general supervision over the academic policies of the private university.<br>(4) The quorum for meetings of the Academic Council shall be such as may be prescribed by the Statutes.  |
| <b>Other Authorities.</b>  |                 | 25. The composition, constitution, powers and functions of other authorities of the private university shall be such as may be prescribed by the Statutes.   |
| <b>The First Statutes.</b> |                 | 26. (1) Subject to provisions of this Act, and the Rules made there under, the First Statutes of the private university may provide for all or any of the following matters, namely :- <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) the constitution, powers and functions of the authorities and other bodies of the private university as may be constituted from time to time;</li> <li>(b) the terms and conditions of appointment of the Vice-chancellor and his powers and functions;</li> <li>(c) the manner and terms and conditions of appointment of the Registrar, Chief Finance and Accounts Officer and other Officers, and their powers and functions;</li> <li>(d) the manner and terms and conditions of appointment of teachers;</li> <li>(e) the terms and conditions of services of employees of the private university;</li> <li>(f) the procedure for arbitration in case of disputes between officers, teachers, employees and students;</li> <li>(g) the conferment of honorary degrees;</li> <li>(h) the provisions regarding exemption of students from payment of tuition fee and for awarding to them scholarships and fellowships;</li> <li>(i) provisions regarding the policy of admissions, including regulation of reservation of seats specially for students below poverty line (BPL), SC/ST, handicapped and girls categories;</li> <li>(j) provisions regarding fee to be charged from students and concession for the categories mentioned in (i) above;</li> <li>(k) provisions regarding number of seats in different courses.</li> </ul> <p>Provided that the private university shall not make any Statute relating to charging of donation or capitation fee from the students.</p> (2) The first Statutes of the private university shall be made by the Governing Body and shall be submitted to the Regulatory Commission for approval.<br>(3) The Regulatory Commission shall consider the First Statutes submitted by the private university within two months from the date of its receipt and shall give its approval with such modifications as it may deem necessary. |

- (4) The private university shall communicate its agreements to the First Statutes as approved by the Regulatory Commission and if it desires not to give effect to the modifications made by the Regulatory Commission under Sub-section (3), it may give the reasons therefore and the Regulatory Commission may or may not accept the suggestions made by the private university.
- (5) The State Government shall publish the first Statute as approved by the Regulatory Commission in the official gazette and thereafter such Statute shall come into force.
27. (1) Subject to the provisions of this Act and the Rules made there under, the Subsequent Statutes of the private university may provide for all or any of the following matters, namely :-
- (a) creation of new authorities of the private university;
- (b) accounting policy and financial procedure;
- (c) representation of teachers in the authorities of the private university;
- (d) creation of new departments and abolition or restructuring of existing departments;
- (e) institution of medals and prizes;
- (f) creation of posts and procedure for abolition;
- (g) revision of fees;
- (h) alteration of the number of seats in different courses; and
- (i) all other matters which under the provisions of this Act are to be prescribed by the Statutes.
- (2) The Statutes of the private university other than the first Statutes shall be made by the Board of Management with the approval of the Governing Body.
- (3) The Statutes made under sub-section (2) shall be sent to the Regulatory Commission and the Regulatory Commission may, if it considers necessary, give suggestions for modifications in it within two months from the date of receipt of the Statutes;
- (4) The Governing Body shall consider the modifications suggested by the Regulatory Commission and return the Statutes to the Regulatory Commission with its comments on the suggestions.
- (5) The Regulatory Commission shall consider the suggestions made by the Governing Body and the Statutes, as finally approved by the Regulatory Commission, shall be published by the State Government in the gazette and on such publication the Statute shall come into force.
28. (1) Subject to the provisions of this Act or the Rules or Statutes made there under, the first Ordinances may provide for all or any of the following matters, namely :-
- (a) admission of students to the private university and their enrolment mentioning clearly special consideration for the students of Scheduled Caste and Scheduled Tribes, handicapped and girls categories;
- (b) details of courses of study to be laid down for the degrees, diplomas and certificates of the private university;
- (c) award of the degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions, the minimum qualifications for the same and the means to be adopted relating to the granting and obtaining of the same;

The Subsequent  
Statutes.

The First Ordinances.

- (d) conditions for award of fellowships, scholarships, stipends, medals and prizes;
- (e) conduct of examinations, including the terms of office and manner of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators;
- (f) examination fees to be charged for the various courses for degrees and diplomas of the university;
- (g) conditions of residence of the students of the university;
- (h) provision regarding disciplinary action against the students;
- (i) creation, composition and functions of any other body which is considered necessary for improving the academic environment of the private university;
- (j) manner of co-operation and collaboration with other universities and institutions of higher education;
- (k) all other matters which, by this Act or Statutes made thereunder, are required to be provided by the Ordinances.
- (2) The First Ordinances of the private university shall be made by the Vice-Chancellor which shall be submitted to the Regulatory Commission for approval.
- (3) The Regulatory Commission shall consider the First Ordinances submitted by the Vice-chancellor under sub-section (2) within two months from the date of its receipt and shall either approve it or give suggestions for modifications.
- (4) The Vice-chancellor shall give his comments on the suggestions made by the Regulatory Commission and shall return the first Ordinance to the Commission and on receipt of the same, the Commission shall either approve the comments of the Vice-chancellor or disapprove the same and on the basis of the final decision, the Ordinance as approved by the Regulatory Commission shall be notified by the State Government in the gazette and on such publication, the Ordinance shall come into force.
- The Subsequent Ordinances.**
29. (1) All Ordinance other than the First Ordinances shall be made by the Academic Council with the approval of the Board of Management.
- (2) The State Government after approval of the Ordinances by the Regulatory Commission, shall publish all Ordinances made under sub-section (1) in the gazette and on such publication, the Ordinance shall come into force.
- Vacancies not to invalidate the proceedings of any Authority or Body of the University.**
30. No act or proceeding of any authority or body of the private university shall be invalid merely by reason of any vacancy or defect in the constitution thereof.
- Filling up of emergent vacancies.**
31. Vacancies arising in the members of authorities or bodies of the private university due to death, resignation or removal of a member or due to change of capacity in which he was appointed or nominated, shall be filled up as early as possible by the person or the body who had appointed or nominated such a member.
- Provided that the person appointed or nominated as a member of an authority or body of the private university on an emergent vacancy, shall remain member of such authority or body for only the remaining period of the member in whose place he is appointed or nominated.

32. The authorities or officers of the private university may constitute such committees with such terms of reference as may be necessary for specific tasks to be performed by such committees. The constitution of such committees and their duties shall be such as may be prescribed by the Statutes. **Committee.**
33. A copy of any receipt, application, notice, order, proceeding, or resolution of any authority or Committee of the private university or other documents in possession of the private university or any entry in any register duly maintained by the private university, if certified by the Registrar, shall be received as *prima facie* evidence of such receipt, application, notice, order, proceeding, resolution or documents or the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matters and transactions therein where the original thereof would, if produced, have been admissible in evidence. **Mode of proof of University Record.**
34. (1) The Authorities of the private university constituted by or under this Act may make regulations subject to the provisions of this Act, the statutes and the ordinances of the private university. **Regulations.**
- (2) The Board of Management may modify or annul any regulations made under this section by any authority.
35. All Statute, Ordinance or Regulation shall come into force after its publication in the official gazette. **Enforcement of Statute, Ordinance and Regulation.**

#### CHAPTER - IV: REGULATION OF PRIVATE UNIVERSITY

36. (1) A Regulatory Commission shall be established by the state government for the purpose of providing a regulatory mechanism at the state level, and for working as an interface between the State Government and the Central Regulatory Bodies for the purpose of ensuring appropriate standard of teaching, examinations, research, extension programmes, protection of interest of the students and ensuring reasonable service conditions of the employees, while the university has full freedom to function. **Regulatory Commission.**
- (2) The Regulatory Commission shall function under the general control of the Visitor.
- (3) The Regulatory Commission shall consist of :
- (a) a Chairman, two full-time Members, out of which one Member shall be "Member-Academic" and another Member as "Member-Administration" and not exceeding two part-time members to be appointed by the Visitor.
- (b) a full time or part time Secretary.
- (4) The Chairman shall be appointed by the Visitor from a panel recommended by the State Government consisting of eminent educationists who have a thorough knowledge of the working of the institutions of higher education.
- (5) The members shall be appointed by the Visitor from a panel recommended by the State Government consisting of persons of repute in the field of education, finance, law, administration / management etc.
- (6) The Chairman and the members shall not be connected in any way with any of the private universities established under this Act.

- (7) Terms and conditions of services of Chairman and the members, mode of authentication of orders and decisions of the Regulatory Commission and instruments issued by the Commission, procedure for meetings of the Commission, recruitment and service conditions of the staff of the Commission, temporary association of persons with the Commission for particular purposes, funds of the Commission, its budget, annual report, account, audit and such other matter as may be required for proper functioning of the Commission shall be provided in the rules made by the State Government in this regard.
- (8) It shall be the general duty of the Regulatory Commission :-
- to take all such steps as it considers necessary for determination and maintenance of standards of teaching, examination and research in the private universities;
  - to ensure that private universities collect only such fees and other charges which cover the cost of education imparted by them and also give a reasonable surplus to enable them to maintain assets and carry out further expansion.
  - to ensure that the teachers of the university have at least the minimum educational qualifications prescribed by the U.G.C. or other regulatory bodies.
  - to ensure that the staff of the private university is appointed in conformity with the Statutes, Ordinance, and norms /guidelines prescribed by UGC and other concerned Statutory Bodies.
  - to ensure that students enrolled in the private university are not exploited and no un-ethical means are adopted to collect undue excessive fee from them;
  - to take action pertaining to, and pursuant upon, liquidation of a private university by the state, including arrangement for completion of courses, conduct of examinations, award of degrees etc., by assigning the job to some other state university in such a manner that the interest of the students are not adversely affected. Expenditure made for these arrangements for the students along with the process of liquidation of the private university shall be made good from the money deposited in the Endowment Fund and / or General Fund;
  - to regulate in consultation with the concerned private university, the study centres established at different places in the state.
  - The State Government may issue directions on matters of policy to the Regulatory Commission.

**Annual Report.**

37. (1) The annual report of the private university shall be prepared by the Board of Management which shall include among other matters, the steps taken by the private university towards the fulfilment of its objects and shall be approved by the Governing Body, and a copy of the same shall be submitted to the sponsoring body.
- (2) Copies of the annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Visitor, and the Regulatory Commission.

**Annual Audit.**

38. (1) The annual accounts including balance sheet of the private university shall be prepared under the directions of the Board of Management and the annual accounts shall be audited at least once every year by the auditors appointed by the private university for this purpose.
- (2) A copy of the annual accounts together with the audit report shall be

submitted to the Governing Body.

- (3) A copy of the annual accounts and audit report along with the observations, if any, of the Governing Body shall be submitted to the Visitor and the Regulatory Commission.
  - (4) The Regulatory Commission shall examine the annual report and accounts and audit report. The direction of the Regulatory Commission on the subject arising out of the annual report and accounts and audit report of the private university shall be binding on the private university.
39. (1) The UGC may cause periodic inspection of the private university or any of its centres. For this purpose, the UGC may call for all relevant information from the concerned private university, as provided in the UGC (Returns of Information by Universities) Rule, 1979 as amended from time to time.
- (2) After inspection and assessment of a private university providing first degree and / or post-graduate degree / diploma courses, the UGC may indicate to the university any deficiency and non-conformity with the relevant UGC Regulations and give it reasonable opportunity to rectify the same. If the Commission is satisfied that the private university has, even after getting an opportunity to do so, failed to comply with the provisions of any of the Regulations, the Commission may pass an order prohibiting the private university from offering any course for the award of the first degree and / or the post-graduate degree / diploma, as the case may be, till the deficiency is rectified.
- (3) The UGC may take necessary action against a private university awarding a first degree and / or a post-graduate degree / diploma, which are not specified by the UGC, and inform the public in general through a public notification. A private university continuing such programme(s) and awarding unspecified degree(s) shall be liable for penalty under Section 24 of the UGC Act.

#### **Periodic Inspection.**

#### **CHAPTER - V : WINDING OF PRIVATE UNIVERSITY**

40. (1) If the Sponsoring Body proposes to dissolve itself or wants to discontinue the function of the private university established under the Act, it shall inform the Regulatory Commission of its plan by which it shall ensure completion of courses and conduct of examinations, and it shall announce the prospective date from which it shall not admit any new students.
- (2) The Regulatory Commission on receipt of such information shall have the right to issue such directions to the Sponsoring Body for the fulfillment of its obligations under sub-section (1) as it may deem necessary. If the Sponsoring body contravenes the provisions of sub-section (1), the Endowment Fund shall be forfeited by Regulatory Commission and the Commission shall make arrangements for completion of courses, conduct of examinations, award of degrees etc., of students of the university either by undertaking the job itself or by assigning the job to some other university in such manner that the interest of the students are not affected adversely in any manner.

Expenditure made for these arrangements for the students shall be made good from the money deposited in the endowment fund and / or General Fund of the university.

Management  
University  
dissolution  
on  
of  
Sponsoring Body.

**Special Powers of the State Government in certain circumstances.**

41. (1) On report of Regulatory Commission or otherwise if it appears to the State Government that any of the directions issued by it to the private university under this Act has been violated or a situation of financial mismanagement and maladministration has arisen in the private university, it shall issue notice requiring the private university to show cause within forty five days as to :-
- Why an order of its liquidation should not be made;
  - Why the board of management should not be suspended and an administrator be appointed under sub-section (7).
- (2) If the State Government considers it necessary to suspend the Board of Management for the proper investigation, it shall, by notification published in the Gazette, order suspension of the Board Management and shall make such arrangement in consultation with the sponsoring body for the administration of the business of the private university till the completion of investigation as it may consider necessary.
- (3) If the State Government, on receipt of reply of private university in respect of notice issued under sub-section (1), is satisfied that there is a prima-facie case of financial mismanagement, maladministration or violation of any of the provisions of this Act or directions issued thereunder it shall make an order of such enquiry as it may consider necessary.
- (4) The State Government shall, for the purposes of any enquiry under sub-section (3), appoint an officer or authority to enquire into any of the allegations and to make report thereon.
- (5) The enquiring authority appointed under sub-section (4) shall have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (No. 40 of 1908) while trying a suit in respect of the following matters namely :-
- summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
  - requiring the discovery and production of any such document or any other material as may be producible in evidence;
  - requisitioning any public record from any court or office;
  - any other matter which may be prescribed.
- (6) Every enquiring authority enquiring under this Act shall be deemed to be a civil court for the purposes of Section 195 and Chapter 26 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974).
- (7) If the State Government on receipt of the enquiry report is satisfied that owing to financial mismanagement and maladministration, a situation has arisen where by the financial stability or administration of the private university has become insecure, it shall, by notification in the official Gazette, order liquidation of the private university or may cause the functioning of the private university to continue by appointing an Act who shall have the powers vested in the Governing Body.
- Provided that no order of liquidation shall take effect unless the entry relating to such private university shall be deleted from the schedule appended to the Act.
- (8) While issuing notification in respect of liquidation under sub-section (7), the State Government, shall, till the end of its current course, make

arrangement for the administration of business of the private university.

- (9) The State Government during the period of management of private university under sub-section (8) shall use the funds available with the private university and the surplus, if any, shall be forfeited for itself.
- (10) All the expenses incurred in the process of enquiry and till the completion of admission of the students, shall be met from the endowment fund or general fund of the university.

#### CHAPTER - VI : MISCELLANEOUS

- |  |  |
|--|--|
| <p>42. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette make rules for carrying out the purposes of this Act.</p> <p>(2) Without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) the manner of making proposal to establish a private university and the fees payable under sub-section (1) of Section 4.</li> <li>(b) other particulars to be contained in the Project Report, under sub-section (2) of Section 4.</li> <li>(c) the mode of establishment of endowment fund, in the manner of its investment, the payment of income from it to the sponsoring body, its forfeiture and mode of its return to the sponsoring body under Section 11(1).</li> <li>(d) mode of collection of fee from the private university and depositing amount so collected in the Consolidated Fund under proviso to Section 12(e).</li> <li>(e) other matters to be provided for in the Statutes under sub-section (1) of Section 26.</li> <li>(f) mode of authentication of orders and decisions of the Regulatory Commission and the instruments issued by the Commission, terms and conditions of services of Chairman and the members, procedure for meetings of the Commission, provision of staff to the Commission and their service conditions, temporary association of persons with the Commission, its budget, annual report, accounts and audit and such other matters as may be required for proper functioning of the Regulatory Commission under sub-section (9) of Section 30;</li> <li>(g) other matters which are required to be, or may be, prescribed by rules under this Act.</li> </ul> <p>(3) All rules for which provision is made in this Act, shall be Act in the state legislative Assembly.</p> <p>(4) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as it may be deemed necessary or expedient for removing the difficulty.</p> <p>(44) The Chhattisgarh Niji Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapana Aur Vinayakam) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) and orders, rules, resolutions, if any, in force immediately before the commencement of this Act, are hereby repealed and rescinded, as the case may be.</p> | <p><b>Power to make Rules.</b></p> <p><b>Power to remove difficulties.</b></p> <p><b>Repeal and Savings.</b></p> |
|--|--|

Provided that all orders made or actions taken under the Act so repealed, except under Sections 5 and 6, shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of this Act.

“विवेस पीरट के अन्तर्गत १०  
सुन्दर के नाम भुगतान (बिना डाय  
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति, राज्याल  
यो, २-२२-छत्तीसगढ़ गजट/३४ रि. सं.  
भिलाई, दिनांक ३०-५-२००१।”

पंजीयन नं.मासिक  
छत्तीसगढ़/०५/२०१०-२०११



# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

अन्तर्गत 145 ]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 17 मई 2010—वैशाख 27, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग  
मंत्रालय, दाक कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 मई 2010

क्र. 5184/116/21-ड/प्र./छ. ग.1/10.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम चित्र पर दिनांक 06-05-2010 को  
राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एवं इसका सर्वसाधारण की जलनकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. तिवारी, अधिकारी, सचिव



## 天津財政專科學校

天津財政專科學校  
Tianjin College of Finance

天津財政專科學校

उत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक : २७ मई २०१०

उत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक १० सं. २०१०)

उत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) ( संशोधन )  
अधिनियम, २०१०

उत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) अधिनियम, २००५ ( क्रमांक १३ सं. २००५ ) में अंतर संशोधन हेतु अधिनियम,

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में उत्तीसगढ़ विभान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम बताया गया है।

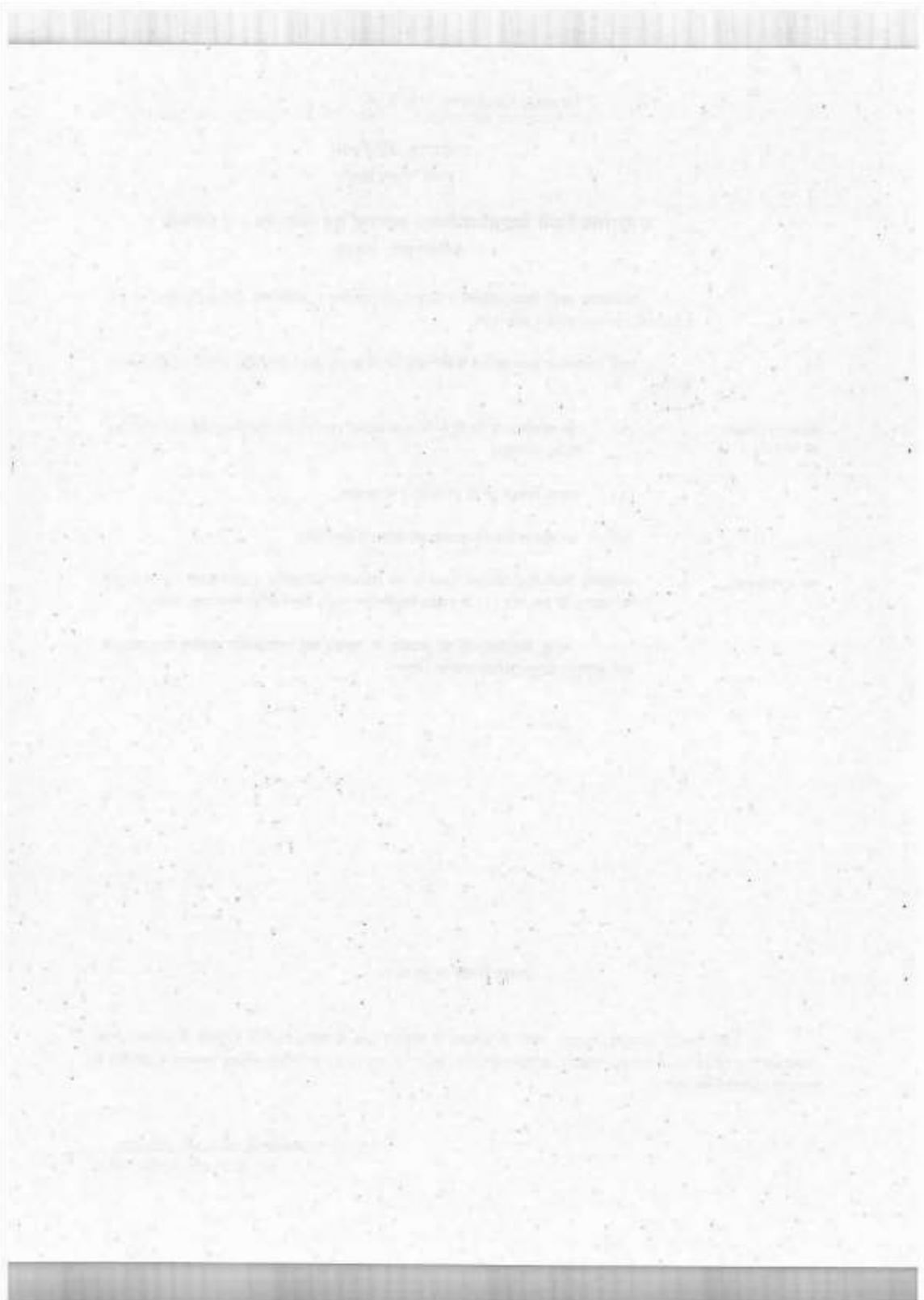
- मंडिर नाम, विस्तार  
तथा प्रांगण
१. (१) यह अधिनियम उत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) ( संशोधन ) अधिनियम, २०१० कहलाएगा।
- (२) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तीसगढ़ राज्य पर होगा।
- (३) यह गवर्नर में इसके प्रकालन को लाठीख से प्रवृत्त होगा।
- भाग १ का संशोधन
२. उत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) अधिनियम, २००५ ( क्रमांक १३ सं. २००५ ) को भाग १ की उप-भाग (१) के गवर्नर निम्नलिखित पांचुक अंतर्स्थापित किया जाए, अर्थात् :

“गवर्नर विश्वविद्यालय को स्थापना के पश्चात् छोई नवा शिक्षण कार्यक्रम, राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से पुरा स्थापित किया जा सकेगा”।

रायपुर, दिनांक १४ मई २०१०

क्र. ५१८४/११६/२१-म/प्रा/१३, ग./१०.—भारत के मंत्रिभान के अनुच्छेद ३४८ के छठह (३) के अनुसार में उत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) ( संशोधन ) अधिनियम, २०१० ( क्रमांक १० सं. २०१० ) का अंगेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से उत्तद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम के अनुसार निम्नांकन दिया गया है।



**HATTISGARH ACT  
(No. 10 of 2010)**

**CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND OPERATION) (AMENDMENT) ACT, 2010**

**An Act further to amend the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005).**

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-first year of the Republic of India, as follows :-

- |    |  |                                       |
|----|--|---------------------------------------|
| 1. | (1) This Act may be called the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) (Amendment) Act, 2010.  | Short title, extent and commencement. |
|    | (2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.   |                                       |
|    | (3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.   |                                       |
| 2. | After sub-section (1) of Section 9 of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005), the following proviso shall be inserted, namely :— | Amendment of Section 9.               |

"Provided that after the establishment of the University any new teaching programme may be introduced with the prior approval of the State Government"



“विजेनेस पोस्ट के अनार्थि डाक शुल्क के नगद भुगतान (विना डाक टिकट) के द्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक नं. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. फिल्म्स, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/टुर्न/09/2010-2012.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 81 ]

रायपुर, मोमकार, दिनांक 28 मार्च 2011—वैत्र 7, शक 1933

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 28 मार्च, 2011 (वैत्र 7, 1933)

क्रमांक-4626/वि. स./विधान/2011.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी विधायकाली के नियम 64 के उपर्योग के फलत में छत्तीसगढ़ विधान सभा की विधायिकालय (स्थापना एवं संचालन) (संसोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 2 सन् 2011), जो दिनांक 28 मार्च, 2011 को पुरक्रमापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

हस्ता/-  
(देवेन्द्र चर्मा)  
सचिव

## छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 2 सं. 2011)

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन)  
विधेयक, 2011

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सं. 2005) को और संशोधित करने हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के बासिन्दों वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियम  
हो :—

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा<br>प्रारंभ | <p>1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम,<br/>2011 कहलाएगा।</p> <p>(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।</p> <p>(3) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।</p>   |
| धारा 7 का संशोधन                      | <p>2. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सं. 2005)<br/>(जो इसके विवादात् गृह अधिनियम के रूप में गिरिष्ठ है) धारा 7 की उपधारा (2) के ७<sup>o</sup> ओं<br/>(ख) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तु अन्त स्थापित किया जाए, अधारौ :—</p> <p style="text-align: center;">“परन्तु राज्य शासन अधिकारी इसकी एजेंसी के द्वारा इस प्रयोजन के लिए दी गई अहसंतोषीय<br/>लौज (जो 30 वर्षों से कम की नहीं होगी) मान्य होगी।”</p> |
| धारा 9 का संशोधन                      | <p>3. मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के परन्तु में अंक एवं शब्द “6 माह” के स्थान पर अंक एवं<br/>शब्द “2 वर्ष” प्रतिस्थापित किए जाएं।</p>  |

## उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

धारा 2 की उपधारा (2) के अंतर्गत यह उपर्योगित है कि प्राकोलक निकाय को भूमि के लिए स्वामित्व के दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए,  
वास्तव में नये राज्य में शासन प्राकोलक निकाय को भूमि के अंतर्गत कर सकता है तथा उसके स्थान पर शासन लौज पर भूमि उपलब्ध  
रूप सकता है अतः धारा 2 की उपधारा (2) के उल्लेख (ख) के पश्चात् परन्तु उल्लेख अन्त स्थापित किया गया है।

इसके अतिरिक्त मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के परन्तु में अंक एवं शब्द “6 माह” “2 वर्ष” के द्वारा प्रतिस्थापित  
किये जाने हेतु प्रस्तावित है, व्यावधान एवं निगमन की प्रक्रिया की पूर्णता के लिये 6 माह पूर्ण नहीं है।

2. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

गणपत्र

दिनांक 28 फरवरी, 2011

हेमचंद यादव  
उच्च शिक्षा मंत्री,  
(भारतीय सदन)

### उपाबंध

छत्तीसगढ़ निवी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) अधिनियम, 2005 ( क्रमांक 13 सन् 2005 ) की धारा 7 एवं 9 का सुरक्षित उद्धरण—

**धारा - 7** धारा (2) में डल्लीखित आज्ञा पत्र में निम्नलिखित अंत सम्पूर्णित होगी जो आयोजक निकाय को इस राज्य में निवी विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए पूरी करनी होगी।

- (1) वह स्थापित करेगा :—
    - (क) छत्तीसगढ़ राज्य में ही मुख्य परिसर, दूर परिसर एवं अध्ययन केन्द्र,
    - (ख) इस अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों के अनुरूप विनाश निधि,
  - (2) वह न्यूनतम निम्नलिखित प्राप्त करेगा :—
    - (क) 15 एकड़ भूमि यदि रायपुर नगर-निगम की सीमा के अंदर मुख्य परिसर की स्थापना प्रस्तावित है,
    - (ख) 25 एकड़ भूमि यदि अन्यत्र मुख्य परिसर स्थापना प्रस्तावित है, तथा साथ ही वह इनके भू-स्थानित अधिनियम प्रस्तुत करेगा,
  - (3) वह प्रशासकीय कार्य तथा अकालीन कार्यों के सम्बद्धन के लिए कम से कम 25,000 बांगफोट का निवित से उपर्योग अथवा सहायता निर्माणों के 45 में उपलब्ध करायेगा।
- 
- (1) विनियमक आयोग द्वारा धारा 8 के अंतर्गत, प्रस्तुत प्रतिवेदन तथा यू.जी.सी. का निरीक्षण प्रतिवेदन, यदि ऐसा कोई है, पर विचार उपरान्त यदि राज्य सासान की संतुष्टि हो जाती है कि प्रायोजक निकाय ने धारा 7 के प्रावधानों को पूरा किया है तथा प्रस्ताव के आधार पर एक निवी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा सकता है, तो इस अधिनियम में संलग्न अनुसूची में संशोधन कर वह ऐसे नाम तथा विवरण जैसा इस संबंध में विचारित किया जाये निवी विश्वविद्यालय स्थापित करेगा।
  - (2) इस प्रकार के निवी विश्वविद्यालय का निगमन उस तिथि से याना जायेगा जिस तिथि से अनुसूची का संशोधन हुआ है, परन्तु यह भी कि उक्त उपाधारा (2) दत्तात्री निगमन की तिथि तथा धारा 4 की उपाधारा (1) में उल्लिखित आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होगा।
  - (3) निवी विश्वविद्यालय अनुसूची में संशोधित नाम का एक नियमित निकाय होगा, जिससे शासक उत्तराधिकार एवं सम्बन्ध चिन्ह होगा, जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यात्र रहते हुए सम्पूर्ण एवं उसका स्थानित प्राप्त कर सकेगा, जो अनुबंध का सकेगा, याद रखता सकेगा या उस नाम से उस पर याद बलात्कार या सकेगा।

देवेन्द्र चर्मा  
सचिव,  
छत्तीसगढ़ विधान सभा।

Digitized by srujanika@gmail.com

"विवेस गोप्ट के अनार्पि डाक  
शूलक के नाम शुगाल (विवा डाक  
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति, छत्तीसगढ़  
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गवर्नर/38 सि. से.  
भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंचायत न्यायांक "छत्तीसगढ़/दृष्टि/  
तक. 114-009/2003/20-01-03."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

प्राप्तक 282 ]

गढ़पुर, शुक्रवार, दिनांक 3 नवम्बर 2006—कार्तिक 12, शक 1928

### विधि और विधायी कार्य विभाग

गढ़पुर, दिनांक 3 नवम्बर 2006

क्रमांक 13069/दी-342/21-म/प्राप्तक/06.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का नियन्त्रित अधिकारियम जिस पर दिनांक 18-8-2006 का  
राज्यसत्र महोरप्य की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एवंद्वारा सर्वसाधारण वीच चानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यसत्र के नाम से उथा अलंगानुसार,  
अझोक कुमार पोददार, उप-मार्चिन

छत्तीसगढ़ अधिनियम  
(अन्वयक 29 सन् 2006)

**छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) ( संशोधन )  
अधिनियम, 2006**

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) अधिनियम, 2005 ( क्रमांक 13 सन् 2005 )  
में संशोधन हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्रावनवै चर्च में छत्तीसगढ़ को विधान सभा द्वारा निर्वाचित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ 1. (1) यह अधिनियम "छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) संशोधन अधिनियम 2006" के नाम से जाना जावेगा।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की रिक्ति से प्रभावशील होगा।

परिभ्रान्त 2. इस अधिनियम में जब तक अन्यथा अनोखा न हो,—

"मूल अधिनियम" से जापर्य है, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) अधिनियम, 2005

प्रारूपी नामोदार 3. यह अधिनियम परो व्याप्ति से ज्ञाप यह निष्पत्तिशील प्रतिक्रिया प्राप्त होगा, यथा :—

(1)	(2)	(3) -	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	कौ. श्री. व्हो. रमन विश्वविद्यालय	आल इंडिया सोसायटी फार इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड टेक्नोलॉजी ( आई सेम्स )	वर्ष एवं सोसायटी का पंजीकरण अधिनियम: 1973 ( क. 44 सं; 1973 ) ( आई सेम्स )	कर्मी रोह, कोटा, जिला-बिलासपुर राज्य दिल्ली एवं प्रद्युम्नी जो तकनीकी पंजीकरण होनेक क. रा. ३०४-२०८ दिनांक १४-०६-२००२	छत्तीसगढ़ राज्य राज्य-बिलासपुर राज्य दिल्ली एवं प्रद्युम्नी ( अधिकारीको, प्राप्त एवं सूचना ), विद्या, वायिनी, निक्षा तथा उच्च संविधान सभा	स्नातक, सालकोचर एवं दिल्ली एवं प्रद्युम्नी जो तकनीकी पंजीकरण होनेक का प्रबोध, विद्यालय, वायिनी, उच्चवाचिका, सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियर, उच्चवाचिका, एवं मानवरक्षा, निधि, जिला, विज्ञान तथा उपर्यु संरचित विषय
2.	मैट्रिस विश्वविद्यालय श्री भगवान महावीर जीव एवेक्षणल एण्ड कॉर्पस सोसायटी,	फर्स्ट एवं सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम एण्ड कॉर्पस सोसायटी,	आरंभ-खोरा हार्डवे यर पंजीकरण गुल्म 1973 ( क. 44 सं. 1973 ) पंजीकरणक क. रा. ३०४-२३४२ दिनांक ०७-०५-२००३	छत्तीसगढ़ राज्य राज्य-बिलासपुर राज्य दिल्ली राज्य	स्नातक, सालकोचर एवं गोप एवं उच्चवाचिका जो प्रबोध, विद्यालय, वायिनी, उच्चवाचिका, सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियर, उच्चवाचिका, एवं मानवरक्षा, निधि, जिला, विज्ञान तथा उपर्यु संरचित विषय	

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2006

क्रमांक 13069/दी-342/21-3/प्रस्ताव/06.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अन्तर्गत में ह. न. निवी विनाविद्यालय (स्थापना तथा संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2006 (क्र. 29 सन् 2006) वर्त अंतर्जी अनुच्छेद राज्यपाल के प्रधिकार से एवं द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यकाल के नाम से तथा आदेशप्राप्त,  
अधोलक्षण कुमार पोदट्टम, उप-मंत्री।

**CHHATTISGARH ACT  
(No. 29 of 2006)**

**CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND OPERATION) (AMENDMENT) ACT, 2006**

An Act to amend the Chhattisgarh Private Universities (Establishment And Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-Seventh year of the Republic of India.  
as follows :—

- |   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
| 1.  | (1) This Act may be called the Chhattisgarh Private Universities (Establishment And Operation) (Amendment) Act, 2006.<br>(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette. | Short title and commencement. |
| 2.  | In this Act, unless the context otherwise requires,—  | Definition.                   |
| "Principal Act" means Chhattisgarh Private Universities (Establishment And Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005). |   |                               |
| 3.  | In Schedule in the Principal Act, the following shall be inserted, namely :—  | Amendment of Schedule.        |

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Dr. C. V. Raman University	All India Society for Electronics and Computer Technology (AISECT)	Firms and Societies Registration Act, 1973 (No. 44 of 1973) Registration No. C. G. State 208 dated 14-8-2002.	Kargi Road, (Kota) District : Bilaspur	Chhattisgarh State	Under Graduation, Post-Graduation and Diploma Courses in the faculties of Technology Engineering, Rural Information Science, Commerce, Education and other fields.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	MATS University	Shri Bhagwan Mahavir Jain Educational and Cultural Society.	Firms and Societies Registration Act, 1973 (No. 44 of 1973) No. C. G. State 2342 dated 7-5-2003.	Arang Kharora Highway, Gram Panchayat : Gullu. Village : Gullu, Tehsil : Arang. District : Raipur	Chhattisgarh State	Under Graduation Post Graduate and Research Courses in the faculties of Management, Business, Commerce, Engi- neering, Information Technology, Life Sciences, Pharmacy, Arts & Humanities, Law, Education and Science and matters related to.

“बद्रीनाथ धोरे के अन्तर्गत दलन  
शुल्क के बाद भूमिका (विषय दाख  
टिकट) के प्रेसपत्र से अनुभाव, अधिकार  
नं. 2-22-छत्तीसगढ़ गवर्नर/38 फि. रो.  
भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”

पंजीयन : -क  
“छत्तीसगढ़/09/2010/112”



# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

प्रभारीक 74 ]

रायपुर, झुकावार, दिनांक 25 मार्च 2011—बैंड 4, शंक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग  
मंत्रालय, दाठ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 मार्च 2011

क्रमांक 2260/दी-73/21-3U/प्रा./उ. 7/11.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम विस पर दिनांक 24-02-2011  
को राज्यपत्र की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एवं द्वारा सर्वसाधारण को जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपत्र के चाप से उन्हें अटेंशन करता,  
डॉ. धौ. पाठाड़ा, उप-सचिव,

## छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 6 मा॒ 2011)

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) ( संशोधन )  
अधिनियम, 2008

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) अधिनियम, 2005 ( क्रमांक 13 मा॒ 2005 ) में संशोधन हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के उन्नतवे पर्व में छत्तीसगढ़ विधान प्रणाले द्वारा निन्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा  
प्रतीक्षा 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन )  
( संशोधन ) अधिनियम, 2008 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र ने इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

अनुसूची का बोधाध्य 2. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) अधिनियम, 2005 ( क्रमांक 11 मा॒ 2005 )  
अधिनियम के अनुसूचे में सरल क्रमांक 2 के परचम, निन्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे संबंधित प्रतिक्रिया प्रतिवाचित यह जावे, जिन्हें :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. कलिंग विश्वविद्यालय— विद्यालय	भवान श्री बद्दा संस्कृतकानन्द	कर्म एवं संविधानटीज पंजीकरण अधिनियम एंड चैरिटेबल सोसायटी, रायपुर।	ग्राम कोटनी, पल्लीद, गन्ड नहसील— आरंग, जिला- 2561 छ. ग. रायपुर।	छत्तीसगढ़ विनायक पल्लीकरण पल्ली, गन्ड नहसील— आरंग, जिला- टेकलानी, बाये टेस्टा- ताली, बाये इंपरीटेक्स, बल्ल, विजन एवं वारिन्य संकाय में स्नातक, स्नात- कोत्तर एवं अनुसंधान प्रशिक्षण,		
4. गाहू.सो.एफ. ए.बी.ई.	दि. अहं.सी.एफ. विश्वविद्यालय गणपति	छत्तीसगढ़ सोसायटी राजस्ट्रीकरण अधि- नियम, 1973 ( मा॒ 1973 आ. क्रमांक ५. ११३८ क्रमांक ७. ११३८ देवाक २३ जनवारी 2002।	ग्राम खोरहा, जात. आई. नर्मिल, १९७३ आ. क्रमांक ५. ११३८ क्रमांक ७. ११३८ देवाक २३ जनवारी 2002।	छत्तीसगढ़ व्यवसाय व्यवसाय, व्यवसाय, वारिन्य, व्यवसाय, वीटा- पेंजी जात दृष्टिकोण विज्ञान तथा उससे संबंधित विषय,		

राष्ट्रपुर, दिनांक 24 मार्च 2011

क्रमांक 2260/डो-73/21-31/ज्ञ/उ. ग./11 — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसार ये छत्तीसगढ़ नियोगित विश्वविद्यालय (स्वायत्ता एवं संपादन) (संशोधन) विधिनियम, 2008 (प्रारंभिक 06 मार्च 2011) का अंतिम अनुदान ग्रन्थालय के प्राप्तिकर्ता से एवं दृष्टिकोण प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपर के नाम से तथा अदित्यानुसार,  
ही. पी. पाराशर, उप-सचिव,

**CHHATTISGARH ACT  
(No. 6 of 2011)**

**THE CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND OPERATION) (AMENDMENT) ACT, 2008**

An Act to amend the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-Ninth year of the Republic of India, as follows :-

- | 1. | (1) This Act may be called the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) (Amendment) Act, 2006.<br><br>(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.<br><br>(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette. | Short title, extent and Commencement. |
|----|---|---------------------------------------|
| 2. | In schedule of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005) Act after serial No. (2) the following serial and the entries related thereto, shall be added.  | Amendment of Schedule.                |

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Kalinga University	Bhagwan Bala Sai Educational and Charitable Society, Raipur.	Firms and Societies Registration Act, 1973 (No. 44 of 1973) Registration No. CG State 2561 dated 8-1-2004.	Gram Kotni, Palod, Teh. Arang District- Raipur (C.G.)	Chhattisgarh State.	Management Computer Science, Information Technology, Bio Technology, Bio Informatics UG and PG, M.A., Science and Commerce faculties.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. I.C.F.A.I. University Society, Raipur.	The I.C.F.A.I. Firms and Societies Registration Act, 1973 (No. 44 of 1973) Registration No. CG State 203 dated 25-6-2002.	Gram Chorha. R.L. Circle Ahirwa Dhamdha Dist.- Durg (C.G.)	Chhattisgarh State.	Business Management Commerce, Information Technology, Arts, Humanities, Law, Education, Science & related subject		

*E. S. G. M. A. I. -  
University*

नियम '2005

Nodal Officer  
 Govt. of Chhattisgarh  
 Chhattisgarh Private Universities  
 Regulatory Commission  
 RAIPUR - 492 007  
 पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/  
 शी. ओ./राष्ट्रपु/17/2002."

"विजनेस पोर्ट के अन्तर्गत दाक  
 गृह के नाम धूमलग (विना डाक  
 टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक  
 नं. 2-22-छत्तीसगढ़ गवर्नर/38.पि. से.  
 मिलाई, दिनांक 30-5-2001."



# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)  
 प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 312 ]

राष्ट्रपुर, राष्ट्रपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2005—जाप्रहावण 25, शक 1927

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग  
 मंत्रालय, दाक कल्याण सिंह भवन, राष्ट्रपुर

राष्ट्रपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2005

अधिसूचना

क्रमांक शफ 3-62/2005/38.—छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 (क्रमांक 13  
 सन् 2005) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत राज्य शासन निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम 2005  
 का निम्नलिखित नियमन निर्धारित कर रही है।

## 1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

(क) ये नियम "छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम 2005" कहे जाएंगे।

- (ख) विन्यास निधि से प्राप्त आय किसी अनुसूचित बैंक में एक संयुक्त बचत खाते में जमा की जावेगी। संयुक्त खाता प्रायोजक निकाय तथा "छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग" के नाम से होगा।
- (ग) विन्यास निधि की आय का उपयोग ऐसे किसी कार्य में नहीं किया जाएगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रायोजक निकाय से संबंधित हो। विन्यास निधि से प्राप्त आय का उपयोग निजी विश्वविद्यालय द्वारा मात्र विश्वविद्यालय के विकास कार्यों में ही किया जाएगा।

#### **7. विन्यास निधि का समर्पण किया जाना।**

- (क) विनियामक आयोग का यह समाधान होने पर कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि उसे अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) अथवा / एवं धारा 40 अथवा 41 के प्रावधानों के अंतर्गत सौंपे गये दायित्वों का, निर्वहन करना आवश्यक हो गया है तो इस संबंध में वह संबंधित निजी विश्वविद्यालय, के प्रायोजक निकाय को पूर्ण विन्यास निधि या उसके एक अंश तथा उस पर प्राप्त आय, यदि कोई हो, को अपने लिए समर्पण करने के लिए, अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) के प्रावधानों को कियान्वित करने हेतु, कारण बताओ सूचना जारी करेगा।
- (ख) विन्यास निधि को रामपहाड़ पर्याप्त हेतु जारी किये गये कारण बताओ सूचना का जवाब प्रायोजक निकाय को सूचना प्राप्ति के 45 दिनों के अंदर देना होगा।
- (ग) कारण बताओ सूचना के जवाब की प्राप्ति निर्धारित अवधि के अंदर प्रायोजक निकाय से प्राप्त न होने पर विनियामक आयोग, विन्यास निधि समर्पण करने हेतु आदेश प्राप्त करने की अनुशंसा राज्य शासन को कर सकेगा तथा आदेश प्राप्त हो जाने पर विन्यास निधि समर्पण कर ली जाएगी और समर्पण राशि राज्य के खाते में शीर्ष "0202 -- शिक्षा" खेल, कला और संस्कृति; (103) - विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा; (0883) - निजी विश्वविद्यालय से प्राप्तियों" के अंतर्गत जमा की जाएगी।

#### **8. विन्यास निधि और उससे प्राप्त आय की वापसी।**

- (क) यदि प्रायोजक निकाय अपने द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अधीन स्थापित निजी विश्वविद्यालय को किन्हीं कारणों से अथवा ऐसी परिस्थितियों के कारण जो उसके नियन्त्रण में नहीं है स्वयं बंद करना चाहे तो इन परिस्थितियों में प्रायोजक निकाय को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उसके द्वारा स्थापित उस निजी विश्वविद्यालय में भर्ती किया गया कोई भी विद्यार्थी प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा। इसके लिए प्रायोजक निकाय को अध्ययनसत् विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम पूरा करने, परीक्षा सम्पन्न कराने तथा उसके आधार पर संबंधित विद्यार्थियों की उपाधि, पत्रोपाधि, प्रमाणपत्र आदि देने की संपूर्ण योजना भी विनियामक आयोग को प्रस्तुत करना होगा। विनियामक आयोग पूर्ण रूप से सतुष्ट होने पर कि प्रायोजक निकाय ने प्रस्तुत की गई योजना के अनुसार छात्रों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर लिया है, प्रायोजक निकाय से इस आशय का सापथ प्रस्तुत करने को कहेगा कि प्रायोजक निकाय की राज्य सरकार, विद्यार्थियों, और निजी विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों तथा अन्य किसी के प्रति कोई देनदारी नहीं है। शपथपत्र प्राप्त होने पर विनियामक आयोग शपथपत्र के तथ्यों का परीक्षण करेगा। इस बात से संतुष्ट होने पर कि शपथपत्र पूरी तरह से सही हैं, विनियामक आयोग विन्यास निधि तथा उस पर प्राप्त आय, यदि कोई हो, प्रायोजक निकाय को वापस करेगा।

- (ख) विनियामक आयोग प्रायोजक निकाय द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र का परीक्षण करेगा और यदि विनियामक आयोग प्रस्तुत शपथपत्र के तथ्यों से सहमत नहीं है, तो वह वहाँ विन्यास निधि और उससे प्राप्त आय के ऐसे अंश को, जिसे वह उचित समझे, रोक कर रखेगा और उस समय तक वापस नहीं करेगा जब तक कि वह इस बात से संतुष्ट न हो जावे कि प्रायोजक निकाय की राज्य सरकार, विद्यार्थियों और निजी विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के प्रति अब कोई देनदारी नहीं है तथा निजी विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम व परीक्षा पूरी करने तथा इनके आधार पर विद्यार्थियों को उपाधि, पत्रोपाधि, प्रमाणपत्र आदि देने की व्यवस्था कर ली गई है।
- (ग) परंतु यह भी कि, जहाँ किसी प्रायोजक निकाय ने निजी विश्वविद्यालय प्रारंभ करने की मंशा से अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अंतर्गत आशय पत्र प्राप्त होने के पश्चात विन्यास निधि की राशि विनियामक आयोग की निधि में जमा की है तथा जहाँ विनियामक आयोग इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 8 के अनुसार विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी प्रस्ताव से, वह उन कारणों से सहमत नहीं हो सकता जिन्हें वह लिखित में उल्लेख करेगा और इसलिए इस रिप्टिटि में नहीं है कि राज्य सरकार को यह सत्ताह दे कि अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अनुसार विश्वविद्यालय की स्थापना की जाये तो विनियामक आयोग विन्यास निधि की राशि प्रायोजक निकाय को उस पर प्राप्त आय, यदि कोई हो, के सहित वापस करेगा।

#### 9. शुल्क जमा करने की प्रक्रिया।

- (क) प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों से एकत्रित किये गये शुल्क का यह अंश जो विनियामक आयोग के पास अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों के अंतर्गत देय होगा, क्रॉस्ड एकाउण्टपेची बैंक ड्रॉफ्ट / बैंकर चेक, जो कि “छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग” के नाम से होगा तथा रायपुर में भुगतान योग्य होगा, संलग्न प्रारूप-घ में दर्शाये अनुसार किया जाएगा।
- (ख) विनियामक आयोग निजी विश्वविद्यालयों द्वारा जमा की गई राशि 15 दिन के अंदर राज्य के कोषालय में शीर्ष “0202 – शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति; (103) – विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा; (0883) – निजी विश्वविद्यालय से प्राप्तियाँ” के अंतर्गत जमा करेगा जिसका विवरण संलग्न प्रारूप-ड. में दर्शाये अनुसार रखा जावेगा और इसकी एक प्रतिलिपि प्रायोजक निकाय को भेजी जाएगी।
- (ग) इन नियमों के प्रावधानों के तहत निजी विश्वविद्यालयों से एकत्रित किया गया और शासकीय कोषालय में जमा किये शुल्क, तथा दंडात्मक ब्याज यदि कोई हो, जो लगाया गया हो और शासकीय कोषालय में जमा किया गया हो तो इस संबंध का जरूरी विवरण हर वित्तीय वर्ष में विनियामक आयोग के कार्यालय में रखा जायेगा। संलग्नक-बृंद में दर्शाये अनुसार दण्डात्मक ब्याज की जानकारी रखी जावेगी।

#### 10. विनियामक आयोग की स्थापना।

- (क) राज्य में कार्यरत “छत्तीसगढ़ निजी बोर्ड विश्वविद्यालय विनियामक आयोग” का उत्तराधिकारी “छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग” होगा तथा अधिनियमों एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगा।

(ख) "छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग" का मुख्यालय रायपुर होगा।

#### 11. विनियामक आयोग के कृत्य.

(क) विनियामक आयोग उन समर्त कृत्यों का निर्वहन करेगा जैसा कि अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (8) में उल्लिखित है तथा ऐसे अन्य कृत्य भी जिन्हे वह अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) में उल्लिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक समझता है।

(ख) निजी विश्वविद्यालयों तथा निजी क्षेत्र की उच्च शिक्षा संस्थाओं से संबंधित अन्य ऐसे विषय जो राज्य शासन द्वारा संदर्भित किया जावे।

#### 12. विनियम बनाने की शक्तियाँ.

(क) आयोग अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन तथा प्रशासन और प्रबंध की प्रक्रिया विनियमन के रूप में निर्धारित करेगा।

(ख) जब तक इन नियमों के प्राप्तानों के अनुसार विनियमन नहीं बन जाते, विनियामक आयोग अपने प्रशासन और प्रबंध के लिए छत्तीसगढ़ शासन का, यथावश्यक परिवर्तन सहित, नियम अपना सकेगा गा ऐसी व्यवस्था कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे।

#### 13. कुलाध्यक्ष का सामान्य नियंत्रण.

(क) विनियामक आयोग कुलाध्यक्ष के सामान्य नियंत्रण में अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(ख) विनियामक आयोग के सामान्य नियंत्रण के कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए कुलाध्यक्ष विनियामक आयोग के क्रियाकलापों से संबंधित कोई भी कागज-पत्र या जानकारी मंगा सकेगा और ऐसा करने के कारण लिखित में अंकित किये जायेंगे तथा इस आधार पर लिखित में विनियामक आयोग को ऐसे निर्देश दिये जा सकेंगे।

(ग) कुलाध्यक्ष ऐसा कोई निर्देश देने के पहले चाहे तो आयोग से विषय पर उसके विचार प्राप्त कर सकेगा तथा यदि वो चाहेगा तो किसी विषय पर निर्देश देने के पहले विनियामक आयोग से प्रकरण व्यवित्रण प्रस्तुत करने के लिए भी कह सकेगा।

#### 14. अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवाओं का निबंधन तथा रातें.

(1)(क) अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य या अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति 3 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा।

(ख) कोई व्यक्ति जो अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद धारण कर चुका है, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में आगे एक और अवधि की नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(ग) कोई ऐसा व्यक्ति जो अधिनियम की व्यवस्था के तहत स्थापित निजी विश्वविद्यालय में पद धारण किया था या किये हैं या छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर स्थित किसी निजी विश्वविद्यालय में पद धारण किया था या किये हैं, वह अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य या अंशकालिक सदस्य के पद की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

- (2) कोई व्यक्ति 70 वर्ष की आयु के पश्चात् पद पर नहीं रह सकेगा।
- (3) अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य या अंशकालिक सदस्य कुलाध्यक्ष को संबोधित किये गये अपने हस्ताक्षरयुक्त लिखित पत्र द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा तथा वह उस त्याग पत्र की प्रतिलिपि छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग को पृष्ठांकित करेगा।
- (4) यदि किसी समय किसी ज्ञापन के आधार पर या अन्यथा कारणों से कुलाध्यक्ष को यह प्रतीर होता है कि अध्यक्ष अथवा सदस्य द्वारा –
- (क) अधिनियम के अंतर्गत उसको सौंपे गये कर्तव्यों के निवाहन में चूक हुई है, या,
  - (ख) विनियामक आयोग के हितों के विपरीत पूर्वग्रह से कार्य किया गया है, या,
  - (ग) विनियामक आयोग के कार्यों का प्रबंधन करने में अक्षम है, तो कुलाध्यक्ष यह मानते हुए भी कि उसके कार्यकाल की अवधि समाप्त नहीं हुई है, लिखित आदेश द्वारा कारणों का उल्लेख करते हुए, अध्यक्ष/सदस्य को पदमुक्त होने के लिए उस दिनांक से जैसा कि आदेश में उल्लेख हो, आदेशित कर सकता है।
- (5) उप धारा (4) में उल्लिखित दिनांक से अध्यक्ष अथवा सदस्य अपने कार्यभार से मुक्त माने जाएंगे और अध्यक्ष या सदस्य का कार्यालय रिक्त मान लिया जाएगा।
- (6) यदि अध्यक्ष अथवा पूर्णकालिक सदस्य या अंशकालिक सदस्य का पद मृत्यु के कारण त्याग पत्र के कारण या अन्यथा भी आकस्मिक रूप से रिक्त होता है, तो नई नियुक्तियों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति की जावेगी।
- शिक्षा विभाग, कुलाध्यक्ष से सम्पर्क करके, किसी पूर्णकालिक सदस्य को अध्यक्ष के कार्यालय की आकर्षित रिक्तता को भरने के लिये नियुक्त कर सकेगा जो दो माह से अधिक समय के लिये नहीं होगा।
- (7) अध्यक्ष के छुट्टी पर रहने के कारण या उसकी रुग्णता के कारण या अन्य कारणों से अनुपस्थित रहने के दौरान अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट पूर्णकालिक सदस्य अध्यक्ष के कृत्यों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।
- (8) अध्यक्ष तथा पूर्णकालिक सदस्यों का पद पूर्णकालिक एवं वैतनिक होगा।
- (9) पूर्णकालिक सदस्य ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जो समय-समय पर उन्हें अध्यक्ष द्वारा सौंपे जायेंगे।
- (10) अध्यक्ष को समग्र रूप से रुपये 25,000/- प्रतिमाह का वैतन, पेशन तथा पेशन के बराबर उपादान (ग्रेच्युटी) की पात्रता होते हुए भी प्राप्त होगा।  
परंतु यदि अध्यक्ष को कोई पेशन प्राप्त नहीं हो रही है तो उसे प्रतिमाह रुपये 25,000/- वैतन तथा उस पर छत्तीसगढ़ राज्य शासन के प्रथम श्रेणी अधिकारी/कर्मचारी को समय-समय पर देय महँगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते प्राप्त करने की पात्रता होगी।
- (11) अध्यक्ष को विनियामक आयोग के मुख्यालय में निःशुल्क साज-सज्जा युक्त आवास की पात्रता होगी, जिसका रख-रखाय राज्य शासन द्वारा किया जावेगा।

- (12) अध्यक्ष को एक कार, एक ड्राइवर तथा कार्यालय में एवं निवास पर एस.टी.डी. सुविधा सहित दूरभाष उपलब्ध कराए जायेगे।
- (13) पूर्णकालिक सदस्यों को समग्र रूप से रूपये 18,400/- प्रतिमाह वेतन, पेंशन तथा पेंशन के बराबर उपादान की पात्रता होते हुए भी प्राप्त होगा।  
यदि किसी सदस्य को पेंशन प्राप्त नहीं हो रही हो तो उसे प्रतिमाह रूपये 18,400/- वेतन तथा राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारी/कर्मचारी को देय समय-समय पर मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते की पात्रता होगी।
- (14) पूर्णकालिक सदस्यों को राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी कर्मचारियों को तत्समय दिये जाने वाले दर से मकान भाड़ा भत्ता की पात्रता होगी और इसके साथ ही उनके कार्यालय एवं निवास पर एस.टी.डी. सुविधा सहित टेलिफोन की पात्रता होगी।
- (15) अध्यक्ष तथा पूर्णकालिक सदस्यों को एक कैलेडर वर्ष में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश तथा 1 माह के अंजित अवकाश/मेडिकल अवकाश की पात्रता होगी। अध्यक्ष तथा पूर्णकालिक सदस्यों के अवकाश का लेखा विनियामक आयोग के कार्यालय में रखा जायेगा।
- (16) आयोग अध्यक्ष शासन के कार्यों से यात्रा के दौरान राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी कर्मचारियों को देय यात्रा एवं दैनिक भत्तो ग्री दर से दून भत्तो वी पात्रता अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों को होगी। इसके साथ वे तीन सितारा तक के होटल में रह सकेंगे जिसके व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
- (17) राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों को देय मेडिकल सुविधाएँ या उसके बदले में मेडिकलेम, जैसा कि शिक्षा विभाग तय करे, पात्रता अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक सदस्यों को होगी।
- (18) अध्यक्ष तथा पूर्णकालिक सदस्यों को आयोग से सेवानिवृत्ति संबंधी सुविधाएँ, प्राप्त नहीं होंगी जैसे पेंशन, उपादान या दोनों।
- (19) अंशकालिक सदस्यों को रूपये 1,000/- प्रतिदिन की दर से बैठक शुल्क तथा राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों को देय दर से यात्रा भत्तो की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त कर्तव्य पर व्यतीत अवधि के लिए तीन सितारा तक के होटल में रुकने के व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
15. आयोग का सम्मिलन
- (क) आयोग ऐसे समय तथा स्थान पर सम्मिलन करेगा, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा तय किया जायेगा।
- (ख) आयोग के सम्मिलनों में अध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में आयोग के वरिष्ठतम् पूर्णकालिक सदस्य अध्यक्षता करेंगे।
- (ग) आयोग के किसी सम्मिलन में विचारार्थ सभी प्रश्नों पर निर्णय उपस्थित तथा भत्तदान करने वाले सदस्यों के बहुमत के आधार पर होगा।

परंतु यदि कोई भी सदस्य नहीं नियुक्त हुआ है तो अध्यक्ष प्रश्नों पर निर्णय सकारण जारी किये गये आदेश/संकल्पों द्वारा लेगा।

परंतु यह और भी कि यदि बैठक में अध्यक्ष और केवल एक सदस्य उपस्थित हों तो प्रश्नों पर निर्णय सकारण आदेश/संकल्प जारी करके अध्यक्ष द्वारा उपस्थित सदस्य का मत रिकार्ड करते हुए लिया जायेगा।

- (घ) विनियामक आयोग की बैठक का कार्यवृत्त अध्यक्ष द्वारा अधिकृत किसी पूर्णकालिक सदस्य या आयोग के अधिकारी द्वारा तैयार किया जायेगा। कार्यवृत्त का अभिप्रामाणीकरण अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा तथा उन्हें विनियामक आयोग के स्थायी रिकार्ड के रूप में रखा जायेगा।

**16. रिकितयों आदि से आयोग की कार्यवाहियों का अधिकारिता न होना।**

आयोग की कोई भी कार्यवाही केवल इस कारण अधिकारिता नहीं समझी जायेगी कि—

- (क) आयोग में कोई रिकित है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या  
 (ख) आयोग के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या  
 (ग) आयोग की कार्यवाही में कोई अनियमितता है;

निम्नु जो निम्न गुणकला को प्राप्तित नहीं करती है।

**17. विशिष्ट प्रयोजनों के लिए आयोग के साथ व्यक्तियों की अस्थायी सहयोगिता।**

- (क) आयोग किसी भी व्यक्ति को, जिसकी सहायता या सलाह अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए चाहता है, वह अपने साथ सहयुक्त कर सकेगा।  
 (ख) आयोग द्वारा उसके साथ उपनियम (1) के अधीन किसी भी प्रयोजन के लिए सहयुक्त किये गये व्यक्ति को उस प्रयोजन से संगत चर्चाओं में भाग लेने का अधिकार होगा, किंतु उसे आयोग के सम्बिलन में मत देने का अधिकार नहीं होगा और वह किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए सदस्य नहीं होगा।  
 (ग) नियम 17 के अंतर्गत आयोग के साथ सहयुक्त किये गये व्यक्ति को रूपये 500/- प्रतिदिन की दर से बैठक शुल्क एवं छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों को तत्समय देय यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।

**18. विनियामक आयोग के आदेशों तथा अन्य लिखितों का अभिप्रामाणीकरण।**

आयोग के समस्त आदेशों तथा विनियम, सचिव के हस्ताक्षर द्वारा अभिप्रामाणित किये जावेंगे और इस कार्य के लिए सचिव की नियुक्ति होते तक अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर से अभिप्रामाणित किया जावेगा और आयोग द्वारा जारी किये गये समस्त निर्णयों या अन्य लिखितों को सचिव या सचिव की नियुक्ति होते तक अध्यक्ष या अयोग के किसी अन्य व्यक्ति, जिसे इस संबंध में उसी रीति में प्राधिकृत किया गया है, अभिप्रामाणित किया जायेगा।

**19. आयोग को संदाय.**

छत्तीसगढ़ शासन, राज्य विधानसभा द्वारा सम्यक विनियोग के पश्चात्, आयोग को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी राशि का जो कि अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों के पालन वे लिए आवश्यक समझा जाये, संदाय करेगा।

**20. विनियामक आयोग की निधि.**

- (क) विनियामक आयोग की अपनी स्वयं की निधि होगी और ऐसी समस्त राशियों जिनका समय-समय पर, राज्य राजकार द्वारा उसे संदाय किया जाये तथा आयोग की समस्त प्राप्तियाँ (जिनमें विन्यास निधि, अतिरिक्त निधि तथा कोई भी ऐसी राशि सम्मिलित होगी जो किसी अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा आयोग को सौंपी जाये) निधि में रखी जायेगी तथा आयोग द्वारा समस्त संदाय उसी में से किया जायेगा।
- (ख) निधि का समस्त धन किसी अनुसूचित बैंक, जैसा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 (क्रमांक 2 सन 1934) में परिभाषित किया गया है, में जमा किया जायेगा।
- (ग) आयोग अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए ऐसी राशियों, जो कि वह उचित समझे व्यय कर सकेगा, और ऐसी राशियों को विनियामक आयोग की निधि से चर्च की जाने वाली मानी जायेगी।

**21. बजट.**

आयोग प्रतिवर्ष ऐसे प्रारूप में तथा ऐसे समय पर, जैसा कि वह तय करे, आगामी वित्तीय वर्ष के संबंध में बजट तैयार करेगा जिसमें प्राक्कलित प्राप्तियाँ तथा व्यय दर्शाये जायेंगे और उसकी प्रतिलिपियाँ उच्च शिक्षा विभाग को इस आशय से अग्रेषित की जायेंगी कि वह राज्य विधानसभा द्वारा इस संबंध में किये गये रायक विनियोग के पश्चात् आयोग को राशियों का संदाय कर सके, जैसा कि ऊपर नियम 19 में उल्लिखित है।

**22. वार्षिक रिपोर्ट.**

आयोग प्रत्येक वर्ष में एक बार, ऐसे प्रारूप में तथा ऐसे समय पर जैसा कि आयोग द्वारा तय किया जाये, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पिछले वर्ष के दौरान के उसके क्रियाकलापों का सही तथा पूर्ण लेखा-जोखा दिया जायेगा तथा उसकी प्रतिलिपि उच्च शिक्षा विभाग को अग्रेषित की जायेगी। उच्च शिक्षा विभाग उसे राज्य विधानसभा के समस्त रखवायेगा।

**23. लेखा तथा सम्परीक्षा.**

- (क) विनियामक आयोग अपने लेखा के संबंध में ऐसी लेखा पुस्तकें तथा अन्य पुस्तकें ऐसे प्रारूप में तथा ऐसी शीति में जैसा कि उसके “” तय किया जाये, रखवायेगा।
- (ख) विनियामक आयोग अपनी वार्षिक लेखाओं को बंद करने के पश्चात्, यथाशीघ लेखाओं का विवरण ऐसे प्रारूप तथा ऐसी तारीख तक तैयार करेगा, जैसा कि आयोग तय करे।

- (ग) आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा थार्टर्ड अकांउटेंट द्वारा वित्तीय वर्ष समाप्ति के तुरंत बाद की जायेगी।
- (घ) विनियामक आयोग की वार्षिक लेखा, जैसा कि थार्टर्ड अकांउटेंट द्वारा प्रमाणित किया गया है, उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट सहित उच्च शिक्षा विभाग को अप्रेषित किया जायेगा तथा उच्च शिक्षा विभाग उन्हें राज्य विधानसभा के समक्ष रखवायेगा।

**24. विनियामक आयोग के कर्मचारीबद्द, आवास और अन्य सुविधाएँ।**

- (क) विनियामक आयोग उतने कर्मचारी जितने कि अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के दश पालन के लिए आवश्यक हों, प्रतिनियुक्ति पर या अच्युत तरीके से नियुक्त करेगा।
- (ख) विनियामक आयोग अपने अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए आवास साज-सज्जा और ऐसी अन्य सुविधाएँ प्राप्त करेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे।

**25. नियमों का शिथिलीकरण (Relaxation of rules).**

इन नियमों द्वारा जिन प्रकरणों का समाधान न हो सकता हो उन प्रकरणों पर विनियामक आयोग की अनुशंसा पर राज्य शासन ऐसा निर्णय ले सकेगा जो साम्य के सिद्धांत (Principle of Equity) द्वारा समर्थित है।

**26. नियम विधानसभा के पटल पर रखा जाना।**

ये नियम विधानसभा के पटल पर रखे जायेंगे।

**27. निरस्त एवं व्यावृति।**

छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय नियम 2004 एवं इस नियम के प्रभावशील होने के ठीक पहले तक यदि कोई आदेश, संकल्प प्रभावी हो, तो जैसी भी रिक्ति हो, वे इसके उपरांत विचारित या निरस्त माने जायेंगे।

परंतु इन निरस्त नियमों के अधीन दिया गया कोई आदेश या की गई कार्यवाही, इन नियमों के तत्स्थानी उपर्यादों द्वारा किया गया या की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जी. डी. गुप्ता, डॉ- सचिव,

## संलग्नक - क

**छत्तीसगढ़ राज्य में निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए आवेदन का प्रारूप**

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की घारा 4 में निहित फ़्लक्षणों के अंतर्गत

[दखें नियम 3 से 6]

प्रति,

अध्यक्ष,

छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग  
रायपत्र (छ0ग0)

(1)	प्रायोजक निकाय का विवरण (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कठिका ..... में है)	
(क)	नाम	
(ख)	पता	
(ग)	पिन कोड क्रमांक	
(घ)	दूरभाष क्रमांक (एस.टी.डी. कोड सहित)	
(ङ.)	फैक्स क्रमांक	
(2)	(च) ई-मेल प्रायोजक निकाय के गजीकरण एवं उसके संबंधान तथा उपविधियों संबंधी विवरण (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कठिका ..... में है)	
(क)	प्रायोजक निकाय छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973 के अंतर्गत पंजीकृत है; या	
(ख)	यह कोई सार्वजनिक न्यास है; या	
(ग)	क्या कंपनी अधिनियम 1956 (सन् 1956 का क्रमांक-1) की घारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी है.	
(घ)	क्या प्रायोजक निकाय एक ऐसा निकाय है जो उक्त (क), (ख), (ग) की व्यवस्था अनुसार पंजीकृत नहीं है किन्तु तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन पंजीकृत है ? यदि हौं तो उस अधिनियम की जानकारी जिसके अंतर्गत पंजीकृत है.	
(ङ.)	पंजीकरण की प्रामाणिक प्रति आवेदन के साथ संलग्न करें.	
(च)	संविधान तथा उपविधियों की प्रति संलग्न करें.	

(3)	प्रायोजक निकाय के विगत् 03 वर्षों के अंकेक्षण प्रतिवेदन की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें। (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कठिका .....में है)	
(4)	प्रायोजक निकाय के वित्तीय संसाधन की विस्तृत जानकारी। (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कठिका .....में है)	
(5)	प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नाम। (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कठिका .....में है)	
(6)	उस स्थान का पूरा पता जहाँ प्रस्तावित विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर रहेगा। (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कठिका .....में है)	
(7)	प्रस्तावित विश्वविद्यालय के उद्देश्य। (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कठिका .....में है)	
(8)	क्या प्रस्तावित विश्वविद्यालय, भारतीय संविधान की घारा 30 के प्रावधानों के अनुसार अल्पसंख्यक दर्जे नी मांग करेगा, यदि हाँ, तो उसका निररण (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कठिका .....में है)	
(9)	विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर का स्थानन्, यदि सामान्य क्षेत्र से अलग हो। (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कठिका .....में है)	
(क)	प्रस्तावित विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर क्या किसी अनुसूचित क्षेत्र में रहेगा ? यदि हाँ तो सकाम प्राधिकारी से इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न करें कि प्रस्तावित स्थानन् रायपुर नगर निगम सीमा के अधीन है।	
(ख)	क्या विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर रायपुर नगर भीमा के अधीन स्थापित करना प्रस्तावित है ? यदि हाँ तो सकाम प्राधिकारी से इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत करें कि प्रस्तावित स्थानन् रायपुर नगर निगम सीमा के अधीन है।	

(10)	प्रस्तावित विश्वविद्यालय के उपयोग के लिए आवश्यक भूमि की जानकारी (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कठिका _____ में है)	
(क)	आवेदन की तिथि में विश्वविद्यालय के पूर्ण उपयोग के लिए यदि कोई भूमि उपलब्ध है तो उसका विवरण.	
(1)	भूमि का स्वामित्व (आवश्यक प्रमाण वं साथ)	
(2)	भूमि का क्षेत्रफल.	
(3)	भूमि का नक्शा.	
(ख)	आशय पत्र प्राप्त होने के पश्चात् प्राप्त की जाने वाली भूमि संबंधी जानकारी.	
(1)	भूमि का स्वामित्व (आवश्यक प्रमाण के साथ)	
(2)	भूमि का क्षेत्रफल.	
(3)	भूमि का नक्शा.	
(4)	भूमि पिंससे प्राप्त की जायेगी.	
(5)	भूमि प्राप्त करने हेतु वित्त व्यवस्था.	
(11)	विश्वविद्यालय प्रारंभ होने के पहले परिसर विकास का विस्तृत व्यूहा. (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कठिका _____ में है)	
(क)	भवन निर्माण, अन्य संरचनात्मक सुविधायें एवं अधोसरंचनात्मक सुविधाएँ.	
(ख)	उपकरणों को प्राप्त करने हेतु योजना	
(ग)	आगामी पांच वर्षों हेतु चरणबद्ध कार्यक्रम की रूप-रेखा.	
(12)	पूँजीगत व्यय का आगामी पांच वर्षों के लिए चरणबद्ध विवरण तथा वित्त व्यवस्था के स्रोत. (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कठिका _____ में है)	
(13)	संकायों की प्रकृति (नाम) (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कठिका _____ में है)	
(क)	संकायों का नाम यथा : विज्ञान, कला, वाणिज्य, तकनीकी शिक्षा आदि	
(ख)	प्रत्येक संकाय के अंतर्गत पाठ्यक्रमों के प्रकार यथा : स्नातक, स्नातकोत्तर आदि	

(ग)	प्रत्येक पाठ्यक्रम की राज्य के विकास के संदर्भ में प्रासारणिकता .	
(घ)	प्रत्येक पाठ्यक्रम में छात्रों की लक्षित संख्या .	
(ङ.)	पाठ्यक्रमों के लिए अगले 05 वर्षों हेतु चरणबद्ध प्रस्तावित कार्यक्रम .	
(च)	प्रत्येक पाठ्यक्रम के संबंध में यह जानकारी की क्या इसे प्रारम्भ करने के लिये केन्द्रीय नियामक अभिकरण अथवा / और राज्य नियामक अभिकरण की पूर्व अनुमति आवश्यक है ? यदि हों तो उसके संबंध में जानकारी, यदि पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की गयी है तो प्राप्त न करने का विस्तृत विवरण, इस विवरण में यह भी स्पष्ट किया जाए कि केन्द्र / राज्य सरकार के किस अधिनियम / आदेश के तहत पूर्व अनुमति आवश्यक है.	
(14)	प्रायोजक निकाय की संबंधित विधाओं में उपलब्ध (यदि कोई हो) पूर्व अनुग्रह तथा विशेषज्ञता . (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कठिका _____ में है)	
(15)	प्रस्तावित पाठ्यक्रमों एवं शोध हेतु आवश्यक अकादमिक सुविधाओं की उपलब्धता . (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कठिका _____ में है)	
(क)	अध्यापक.	
(ख)	तकनीकी / गैर-तकनीकी कर्मचारी.	
(ग)	उपकरण एवं प्रयोगशाला.	
(16)	प्रस्तावित प्रत्येक पाठ्यक्रमों पर अलग-अलग व्यय का विवरण (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कठिका _____ में है)	
(क)	आवर्ती व्यय का अनुमान.	
(ख)	उपलब्ध वित्त स्रोत.	
(ग)	अनुमानित व्यय प्रति विद्यार्थी.	
(17)	संसाधनों को गतिमान करने की योजना हेतु . (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कठिका _____ में है)	
(क)	पूँजी की लागत.	
(ख)	स्त्रीतों के भुगतान की प्रक्रिया	

(18)	विभिन्न आंतरिक स्त्रोतों से प्रत्याशित आय से कोष निर्माण की योजना (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कठिका ..... में है)	
(क)	छात्र शुल्क द्वारा.	
(ख)	परामर्श सेवा द्वारा.	
(ग)	विश्वविद्यालय के उददेश्यों से संबंधित अन्य गतिविधियों द्वारा.	
(19)	प्रस्तावित पाठ्यक्रमों हेतु प्रस्तावित शुल्क ढौंचा, रियायत एवं छात्रवृत्ति (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कठिका ..... में है)	
(क)	सामान्य वर्ग हेतु.	
(ख)	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हेतु.	
(ग)	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु.	
(20)	पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रस्तावित प्रक्रिया (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कठिका ..... में है)	
(21)	अध्यापकों तथा अन्य कर्मदारियों की नियुक्ति हेतु प्रस्तावित प्रक्रिया (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कठिका ..... में है)	
(22)	शिक्षा प्रदाय की विधि (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कठिका ..... में है)	
(क)	परम्परागत शिक्षा पद्धति.	
(ख)	दूरवर्ती शिक्षा पद्धति.	
(ग)	उपरोक्त वर्णित दोनों प्रकार की शिक्षा पद्धति	
(23)	यदि दूरवर्ती शिक्षा प्रस्तावित हो तो प्रस्तावित केन्द्रों के नाम तथा विवरण (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कठिका ..... में है)	
(24)	स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यक्रम तथा विशिष्ट अध्यापन, प्रशिक्षण या शोध गतिविधियों का विवरण (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कठिका ..... में है)	

(25)	कृषक, महिलाओं तथा विशेष रूप से इस राज्य में स्थित उद्योगों के लाभ हेतु चलाये जाने वाले कार्यक्रम (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कठिका .....में है)		
(26)	उपलब्ध या/प्रस्तावित अन्य सुविधाएं		
	(क)	छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास की उपलब्धता.	
	(ख)	खेल मैदान.	
	(ग)	राष्ट्रीय कैडेट कोर, रक्षाकूट एवं गाइड, राष्ट्रीय सेवा योजना आदि.	
(27)	छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में प्रस्तावित दूर परिसर केन्द्र/अध्ययन केन्द्र का विवरण (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कठिका .....में है)		
(28)	प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता एवं औचित्य (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कठिका .....में है)		
(29)	यदि प्रायोजक निवासग्राम पूर्णार्थी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था तो उसकी सम्पूर्ण जानकारी जिसमें स्थापना की अधिसूचना क्रमांक व दिनांक तथा पूर्व अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची 1 का क्रमांक दर्शाएं। इसके साथ यह भी दर्शाएं कि क्या विन्यास निधि अथवा/अतिरिक्त निधि जमा की गई है या जमा है? यदि हों, तो इसके संबंध में साप्रमाण सम्पूर्ण जानकारी (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कठिका .....में है)		
(30)	आवेदन शुल्क की जानकारी (वताये) :- (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कठिका .....में है)		
	(क)	रेखांकित डिमाण्ड ड्राफ्ट की राशि.	
	(ख)	उस बैंक का नाम जिसने डिमाण्ड ड्राफ्ट जारी किया है.	
	(ग)	डिमाण्ड ड्राफ्ट का क्रमांक एवं दिनांक.	
	(घ)	डिमाण्ड ड्राफ्ट के पीछे की ओर प्रायोजक निकाय का तथा प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नाम दे	

उपरोक्तानुसार .....(प्रायोजक निकाय का नाम) की ओर से .....  
(प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय का नाम) के स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना

एवं संचालन) अधिनियम 2005 (क्रमांक - 13 सन् 2005) के प्रावधानों के अनुसार एतद् द्वारा आवेदन प्रस्तुत है। इस आवेदन के प्रत्येक विन्दु पर विस्तृत विवरण परियोजना प्रतिवेदन में दिया गया है। प्रत्येक विन्दु के आगे दर्शायी परियोजना प्रतिवेदन की संदर्भित काँडिका/काँडिकाओं में विस्तृत जानकारी देखी जा सकती है।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि :-

- (क) मुझे .....(हस्ताक्षरकर्ता का नाम) को .....(प्रायोजक निकाय का नाम) की ओर से आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया गया है।
- (ख) प्रायोजक निकाय ने यह संकल्प किया है कि .....(प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय का नाम) के नाम से निजी विश्वविद्यालय स्थापित करेगा तथा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 (क्रमांक - 13 सन् 2005) तथा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालयों के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों एवं प्रावधानों का पालन किया जायेगा और यह भी संकल्प किया है कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा (संकल्प की प्रति संलग्न वीज जायेगी)।

स्थान : .....  
दिनांक : .....

हस्ताक्षर .....  
नाम एवं पदनाम .....  
प्रायोजक निकाय का नाम .....

संलग्नकों की सूची :

दो गवाहों के हस्ताक्षर, नाम एवं पता :-

(1)	हस्ताक्षर	
	नाम	
	पता	
(2)	हस्ताक्षर	
	नाम	
	पता	

**निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के आवेदन प्रस्तुत करने हेतु मार्गदर्शी टीप :-**

- (1) छत्तीसगढ़ राज्य में निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये आवेदन देने से पहले छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) में दिये गये प्राक्धानों को सावधानीपूर्वक पढ़ लेवे।
- (2) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, 29/778, स्टाट न.-5, ब्लॉक न.-3, राम मंदिर के सामने, मधुपिल्लै घौक, शांति नगर, रायपुर, पिनकोड - 492007 में रुपए 500/- (रु० पाँच सौ रुपये) का क्रास्ड अकाउन्ट पेंथी ड्राफ्ट, जो कि “छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग” के नाम से हो तथा रायपुर में मुगतान योग्य हो जमा कर व्यवितरण: या ऐसा ही रुपया 550/- (रु० पाँच सौ पचास) का ड्राफ्ट भेजकर विश्वविद्यालय स्थापित करने के आवेदन का प्रारूप अधिनियम तथा नियमों की प्रति डाक हारा प्राप्त की जा सकती है।
- (3) प्रायोजक इनकाय या उनका प्रतिनिधि निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में विनियामक आयोग से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। मार्गदर्शक सत्र पहले से समय निर्धारित करने पर ही आयोजित किया जा सकेगा।

\* \* \* \* \*

सलगनक—खविन्यास निधि की स्थापना के लिए आवेदन

प्रति,

अध्यक्ष

छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियोगक आयोग  
रायपुर. (छ0ग0)

(1)	प्रायोजक निकाय का विवरण	
(क)	नाम	
(ख)	पता	
(ग)	पिन कोड क्रमांक	
(घ)	दूरभाष क्रमांक (एस.टी.डी. कोड सहित)	
(ङ.)	फैक्स क्रमांक	
(च)	ई-मेल	
(2)	प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नाम	
(3)	उस स्थान का पूरा पता जहाँ प्रस्तावित विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर रहेगा	
(4)	विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर का स्थानन्, यदि सामान्य क्षेत्र से अलग हो	
	(क)	प्रस्तावित विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर क्या, किसी अनुसूचित क्षेत्र में रहेगा ? यदि हों, तो सक्षम प्राधिकारी से इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न करें कि प्रस्तावित स्थानन् क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है.
	(ख)	क्या विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर रायपुर नगर सीमा के अधीन स्थापित करना प्रस्तावित है ? यदि हों तो सक्षम प्राधिकारी से इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत करें कि प्रस्तावित स्थानन् रायपुर नगर निगम सीमा के अधीन है.
(5)	पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय की विन्यास निधि का विवरण (बताए)*	

(क)	पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय का नाम.	
(ख)	पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय के प्रायोजक निकाय का नाम.	
(ग)	अधिसूचना का क्रमांक एवं दिनांक जिसके अंतर्गत पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था.	
(घ)	पूर्व अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची 1 में पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय का क्रमांक.	
(ङ.)	क्या पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर अनुसूचित क्षेत्र में स्थापित था ?	
(च)	पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय के विन्यास निधि की राशि जो विनियामक आयोग के पास जमा है (बैंक की पे-इन-रलीफ) की फोटो प्रति लगाकर प्रमाण दें.	
(छ)	अधिनियम की धारा 11 के उपधारा (1) के खण्ड (ख) के परतुक में प्रावधानेत अनुसार विन्यास निधि की बहुत शुद्ध राशि जो प्रायोजक निकाय द्वारा पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय की विन्यास निधि को समायोजित कर जमा करना प्रस्तावित है.	
(6)	विन्यास निधि का विवरण (बताए).	
(क)	विन्यास निधि की राशि	
(ख)	बैंक ड्राफ्ट नं. तथा पूर्ण विवरण जिसमें बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, ब्रांच का नं., ब्रांच का कोड उस बैंक का शामिल हो जिसने बैंक ड्राफ्ट जारी किया हो.	
(ग)	बैंक ड्राफ्ट जारी करने का दिनांक.	
(घ)	उस व्यक्ति का नाम तथा पदनाम जिसने प्रायोजक निकाय की ओर से विन्यास निधि की राशि जमा की है.	
(ङ.)	बैंक ड्राफ्ट के पीछे प्रायोजक निकाय तथा प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नाम लिखें.	

\* यह जानकारी केवल उन प्रायोजक निकायों को देना है जिन्होंने पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय स्थापित किये थे अन्य प्रायोजक निकाय यहाँ निरंक जानकारी देते हैं।

(7)	विन्यास निधि से प्राप्त आय जमा करने के लिये बचत खाता खोलने का प्रमाण .	
(क)	उस अनुशूलित बैंक का नाम, उसके शाखा का नाम सहित जिसमें बचत खाता खोला गया है।	
(ख)	यह राशि जिससे बचत बैंक खाता खोला गया है। बैंक द्वारा जारी पे-इन-रलीप सलग्न करें।	
(ग)	उस व्यक्ति का नाम एवं पदनाम जो कि प्रायोजक निकाय की ओर से बचत खाते का संचालन करेगा।	
(घ)	बचत बैंक खाता क्रमांक एवं इस खाते की स्थापना का दिनांक।	
(8)	आशय पत्र का विवरण (बताए)	
(क)	जल्दी करने का क्रमांक और दिनांक।	
(ख)	प्रायोजक निकाय को प्राप्त होने का दिनांक।	
(ग)	आशय पत्र की फोटो प्रति सलग्न करें।	
(9)	विन्यास निधि की स्थापना के संदर्भ में अन्य कोई जानकारी जो प्रायोजक निकाय देना चाहे या कोई आवेदन जो इस संदर्भ में प्रायोजक निकाय करना चाहे ।	

उपरोक्तानुसार .....(प्रायोजक निकाय का नाम) की ओर से .....(प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नाम) की विन्यास निधि की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 (क्रमांक – 13 सन् 2005) के प्रावधानों के अनुसार आवेदन प्रस्तुत है।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि :-

- (क) मुझे .....(हस्ताक्षरकर्ता का नाम) को .....(प्रायोजक निकाय का नाम) की ओर से विन्यास निधि की स्थापना हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया गया है।
- (ख) प्रायोजक निकाय ने यह संकल्प किया है कि .....(प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नाम) के नाम से विश्वविद्यालय स्थापित करेगा तथा रूपया (अंकों में) ..... रूपया (शब्दों में) ..... विन्यास निधि के रूप में जमा करेगा तथा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 (क्रमांक – 13 सन् 2005) तथा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालयों के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों एवं प्रावधानों का पालन किया जायेगा और यह भी संकल्प किया है कि छत्तीसगढ़ निजी

विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा।

स्थान : .....  
दिनांक : .....

हस्ताक्षर .....  
नाम एवं पदनाम .....  
प्रायोजक निकाय का नाम.....

दो गवाहों के हस्ताक्षर, नाम एवं पता :-

(1)	हस्ताक्षर
	नाम
	पता
(2)	हस्ताक्षर
	नाम
	पता

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, रायपुर

14 - 99

दूरभाष क्र.	
फैवस फ़्र.	
ई—मेल	
दिनांक	

16

卷之三

卷之三

卷之三

ਤੁਹਾਨਾਥ

प्रायोजक निकाय का नाम (पद सदा सहित)

एकत्रित किये गये शुल्क का विवरण जो विनियामक आदेश को भेजा गया

## विवरविधालय का नाम

पिनकोड सहित पता	
दूरभाष क्रमांक एस.टी.डी. कोड नम्बर सहित	केवल नं.
विवरण क्रमांक	ई-मेल

उस माइट का नाम जिसके लिए शुल्क एकत्रित किया गया है

स.क्र.	परिचार / अध्ययन केन्द्र का नाम	पाठ्यक्रम का केन्द्र का पता	पाठ्यक्रम का नाम	प्रतिशिल्प की विधार्थी की संख्या	शुल्क की दर	कुल एकत्रित शुल्क	कोर्टमध्ये दराये शुल्क का 1 %	विशेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
कोर्टमध्ये-7 का योग : करपर कोर्टमध्ये-8 का योग : करपूर	(अंकों में) लघुपूर्ण (अंकों में) लघुपूर्ण							(गद्दों में) (गद्दों में)

- (1) उस वैदिक जा तथा उसकी शाखा का नाम, जिसके द्वारा उसमें ड्राफ्ट जारी किया गया।
- (2) विषाङ्ग और क्रमांक
- (3) विषाङ्ग ड्राफ्ट जारी करने की तारीख

यह प्रताग्रित किया जाता है कि उस विवरण ने दी गई शुल्क एकत्रित करने की जागतिकी हमारे साथ जांच नहीं गई है तथा सही है।

दिनांक

मार्गदर्शी दीप :

- (1) कोर्टमध्ये क्रमांक - 4 :
- (2) कोर्टमध्ये क्रमांक - 6 :

शुल्कसंचित

मुख्य वित्त एवं लेखाचिकारी

उस पाठ्यक्रम का उल्लेख करै, जिसके लिए शुल्क विधार्थियों से एकत्रित किया गया है।  
“शुल्क” से अभियंत है नियो विवरविधालय द्वारा विचारितगी से लिया जाने पाला शुल्क जो किसी भी नाम से परंतु वापसी  
दोष नहीं है।

## छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियोगक आवेदन रायपुर

दृश्याप क्रमांक	
फैक्टर क्रमांक	
ई-मेल	
दिनांक	

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य की सचित निवि में जना किया गया शुल्क का विवर।

संदर्भ :- छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 (झारख 13, 2005) ने धारा - 12 देखें।

कोषालय में जना की गई शुल्क की राशि का विवरण

सं. क्र.	विश्वविद्यालय का नाम	वह माह जिसमें शुल्क एकान्तर की गई	विवरण क्रमांक दरमा राशि	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

कौटलम-5 का योग : राशि ..... (अको में रुपये ..... रुपयों में)

- (1) Payee का नाम : छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर
- (2) वह माह, जिसके अंतर्गत राशि की सचित निवि में जना की गई है
- (3) कोषालय का नाम जिसमें राशि जना की गई है
- (4) Account Payee बोक का क्रमांक
- (5) बोक जारी करने का दिनांक
- (6) शुल्क का नाम जिस पर चेक आहति किया गया है
- (7) विनियोगक आवेदन के उस अधिकारी का नाम एवं पदनाम जिसने चेक पर हस्ताक्षर किये हैं

(1) हस्ताक्षर ..... (2) हस्ताक्षर .....  
पदनाम ..... पदनाम .....छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय  
विनियोगक आवेदन, रायपुर

## मार्गदर्शी दीप :

- (1) कौटलम क्रमांक - 4 : प्रत्येक माह में एकान्तर किये गये शुल्क और उसे विनियोगक आवेदन को नेजने संबंधी विवरण, प्राक्षय - तीन में है। प्राक्षय - 3 में भेजे जाने याते विवरण को संबंधित निर्दि विश्वविद्यालय क्रमांक देता। निर्दि विश्वविद्यालय इसमें वर्तमान तिथियाँ। यह विवरण क्रमांक नथा वर्तमान कोलम में विनियोगक आवेदन के कार्यालय द्वारा ऑफिस तिथ्या जायेगा।

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, रायपुर

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2005

624 (25)

प्रधानमंत्री	केशव द्विवेक
फैसला करने का	को
गठन	को
दिल्ली	दिल्ली

**प्रिय :** छत्तीसगढ़ राज्य की सचिवत निवि. मैं जमा किया गया दंडनाशक घास का विवरण।  
**संदर्भ :** छत्तीसगढ़ निवो विवरणित रूप (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 (क्रमांक 13, 2005) की पात्रा - 12 देखें।

मा. क्र.	विवरिताय का नाम	विवरिताय का नाम का संकल्प शब्द के विस्तृत द्वारा दृढ़तम् व्याज लगाने और इच्छित करने के लिए अधिकृत विधा यथा है	वार्षि यिकांश	विवरित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

- Payee का नाम :** प्रतीतीर्ण यासन, रायपुर

  - (1) वह मर, जिसके अंतर्गत राज की संविधि में जमा की गई है
  - (2) कोषालय का नाम चिकित्सा जमा की गई है
  - (3) Account Payee एक को ब्रानच
  - (4) देक गणी करने का दिनांक
  - (5) देक का नाम जिस पर चेक अद्वितीय रखा गया है
  - (6) विनियोगक आयोग के उस अधिकारी का नाम जो दिनांक दिया गया है
  - (7) विनियोगक आयोग के उस अधिकारी का नाम जो दिनांक दिया गया है

(1) 積極的  
(2) 極端的

चत्तीसगढ़ निजी विरपविचालय  
विनियामक आयोग, साप्तर

रायपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2005.

क्र. एफ 3-62/2005/38.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसारण में, इस विभूग को अधिसूचना क्रमांक एफ 3-62/2005/38 दिनांक 16-12-2005 का अंग्रेजी अनुयाद राज्यपाल के प्राधिकार से एवंदुआरा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जी. डी. गुप्ता, उप-सचिव,

Raipur, the 16th December 2005

NOTIFICATION

No. F 3-62/2005/38.—In exercise of powers conferred by Section 42 of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005), the State Government hereby makes the following Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Rules, 2005.

- 1. Short title and Commencement:-** (a) These rules may be called "Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation), Rules, 2005.
- (b) It extends to the whole State of Chhattisgarh.
- (c) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

- 2. Definitions:-**
- (a) "Act" means Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No.13 of 2005);
  - (b) "Commission" means the Regulatory Commission established under section 36 of the Act;
  - (c) "Higher Education" means the Higher Education Department, State of Chhattisgarh;
  - (d) "Private University" means the Private Universities incorporated under the Act;

- (e) "Regulation" means the regulation made under the provisions of the Act;
- (f) "Sponsoring Body" means the sponsoring body as defined in clause 29 of section 2 of the Act;
- (g) "State" means the State of Chhattisgarh;
- (h) "Visitor" means the visitor of the private universities as defined in clause 38 of Section 2 of the Act.

"Words and Expression" used but not defined in these rules and defined in the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005, as the context requires, have the same meaning as assigned to them in the Act.

**3. Application for Establishment:-** (a) Sponsoring body intending to establish a private university shall submit the application for establishment of the private university in prescribed form shown in Annexure "A" to the Regulatory Commission.

(b) Application shall be signed by the person authorized to authenticate instruments on behalf of the Sponsoring Body.

(c) Application fee of Rs.5000/- (Rs:five thousand only) shall be sent alongwith application through a crossed account payee draft in the name of the "Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission" payable at Raipur.

(d) Application for the establishment of the Private University shall be accompanied by a Project Report.

(e) Application submitted by the sponsoring body shall be duly acknowledged by the Regulatory Commission.

**4. Establishment of Endowment Fund:-** (a) Sponsoring Body intending to establish a Private University shall establish an Endowment Fund after receiving the Letter of intent as provided under sub-section (2) of Section 6 of the Act in accordance with the provision of Section 11 of the Act.

(b) The Endowment fund shall be deposited in the fund of the Regulatory Commission under the signature of Sponsoring Body through crossed account payee draft in the name of the "Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission" payable at Raipur in form shown in Annexure "B" & shall be issued a certificate of receipt by the Commission in form shown in Annexure "C".

**5. Investment of Endowment Fund:-** (a) The Regulatory Commission shall invest the Endowment Fund in the form of Fixed Deposit in some Scheduled Bank, keeping in view of the various parameters for ensuring liquidity, security and profitability of the funds.

(b) Proceeds from the investment shall be utilised by the Commission for performing its function.

**6. Income from Endowment Fund:-** (a) The Regulatory Commission shall pay to the Sponsoring Body interest on the amount of the Endowment Fund at the rate at which the State Bank of India pay the interest, during the period under consideration, on the savings Bank Account.

- (b) Income from the Endowment fund shall be deposited in a Joint Savings Bank Account opened in a Scheduled Commercial Bank. Joint Account will be in the name of the Sponsoring Body and "Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission."
- (c) Income from the Endowment Fund shall not be invested in any business connected directly or indirectly with the Sponsoring Body. This Income shall be used only for the development of the University.

**7. Forfeiture of Endowment Fund :-** (a) If Commission is satisfied that such a situation has arisen that it has to discharge its responsibility according to provisions of Sub- section 2 of Section 11 or/ and Sections 40 or 41 of the Act, it shall issue a showcause notice to the Sponsoring Body of the concerned Private University for forfeiture of a part or whole of the Endowment Fund alongwith the income on this Endowment Fund, if any, for implementing the provisions of sub-section (2) of Section 11 of the Act.

- (b) Sponsoring Body shall reply the showcause notice for forfeiture of the Endowment Fund within 45 days of its receipt.
- (c) After receipt of notice if Sponsoring Body fails to reply within stipulated period, Commission may recommend to the State Government for permission to forfeit the Endowment Fund and after obtaining permission Endowment Fund shall be forfeited and credited in the Government Account under the Head "0202-Education, Sports, Art and Culture (103)- University and Higher Education, (0883).

**8. Refund of Endowment Fund and its Income:-** (a) If the Sponsoring Body proposes to dissolve or de-establish the Private University

**established under the provisions of the Act due to any reasons or circumstances beyond its control, the Sponsoring Body shall have to ensure that no student admitted in the University shall be adversely affected. The Sponsoring Body shall also submit to the Regulatory Commission a complete plan for completion of the courses, conduct of examination and on that basis awarding Degree, Diploma, Certificate, etc. to the students studying in the University. On being fully satisfied that the Sponsoring Body has completed its responsibilities towards the students according to the plans so submitted, the Regulatory Commission shall ask the Sponsoring Body to submit an affidavit stating that the Sponsoring Body does not bear any liabilities due to State Government, Students, and Employees of the University or any other person. On receiving the Affidavit, Regulatory Commission will examine the facts stated therein. After being satisfied that the facts given in the Affidavit are true, Regulatory Commission will return the Endowment Fund and income therefrom, if any, to the Sponsoring Body.**

**(b) Regulatory Commission shall examine the affidavit submitted by the Sponsoring Body and in case of disagreement with the facts shown in the affidavit, Regulatory Commission shall return such a portion of the Endowment Fund and income therefrom, if any, as it considers proper, and it will not return the same till it is fully satisfied that the Sponsoring Body does not bear any due liabilities to the State Government, students and employees of the private university, and that the arrangements have been made for completion of the courses, conduct of examination and on that basis awarding of degree, diploma and certificate, etc., to the students studying in the Private University.**

(c) Provided that where the amount of Endowment Fund has been deposited in the Fund of the Regulatory Commission by a Sponsoring Body with an intention to start a Private University after receiving letter of intent, as per sub-section (2) of Section 6 of the Act, and where the Regulatory Commission is satisfied as per Section 8 of the Act, that the proposal to establish a Private University can not be approved by it for the reasons to be recorded in writing and thus is not in a position to advise the State Government to issue a Notification for establishment of the Private University under sub-section (1) of Section 9 of the Act, the Regulatory Commission shall refund the amount of Endowment Fund and income therefrom, if any, to the Sponsoring Body.

9. **Procedure for fees deposit:-** (a) Every Private University shall deposit the portion of the fees collected from the student due under the provisions of section 12 of the Act through a crossed Account Payee Bank Draft/Runker's cheque in the name of "Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission" payable at Raipur in the prescribed form shown in Annexure-D.
- (b) Regulatory Commission shall credit the amount of fees received from the Private Universities within 15 days in the Treasury under the Head "0202-Education, Sports, Art and Culture, 03-University and Higher Education, 0883-receipt from Private Universities" and information shall be kept in form shown in Annexure-E and a copy of the same be transmitted to Sponsoring Body.
- (c) Information with regard to fees collected from the Private Universities under the provisions of these rules and deposited in Government Treasury, and penal interest, if any, imposed and deposited in the Government Treasury, and other relevant information in this regard for every financial year shall be maintained in the office of the Regulatory Commission. Penal interest information shall be kept in the form shown in Annexure-F

- 10. Establishment of the Regulatory Commission:-** (a) Chhattisgarh Niji Kshetra Vishwavidyalaya Viniyamak Ayog functioning in the State shall be succeeded by Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission and shall function in accordance with the provisions of the Act and Rules made thereunder.
- (b) The Head Office of the Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission shall be at Raipur.
- 11. Functions of the Regulatory Commission:-** (a) The Regulatory Commission shall perform all functions as laid down in Sub-section (8) of Section 36 of the Act as well as such other functions as it may deem fit to achieve the objectives laid down in sub-section (1) of Section 36 of the Act.
- (b) Any other such matter concerning the Private Universities and Private Institutions of Higher Education which may be referred by the State Government.
- 12. Power to make Regulations:-** (a) The Commission shall lay down the procedures for performance of its functions and for administration and management of the Commission in the form of Regulations.
- (b) Till regulations are made as provided in these Rules, the Regulatory Commission may adopt for purpose of administration and management of the Commission, Rules, if any, mutatis mutandis, of Government of Chhattisgarh, or may make such arrangements as it may deem fit.
- 13. General Control of Visitor:-** (a) The Regulatory Commission shall function under the general control of the Visitor.

- (b) The Visitor in performance of his duties of general control of the Regulatory Commission, may call for any paper or information relating to the affairs of the Regulatory Commission for reasons to be recorded and thereon, by an order in writing, give such directions to the Regulatory Commission on that basis.
- (c) The Visitor may before issuing any direction, call comment of the Commission and may also direct for personal presentation on any matter before giving any direction.

**14. Terms and Conditions of Service of Chairman and Members:-**

- (1)- (a) A person appointed as Chairman or Full Time Member or Part Time Member shall hold office for a term of 3 years.
- (b) Person who has held office as Chairman or Member shall be eligible for further appointment for one more term.
- (c) No person shall be eligible for the post of Chairman or Full Time Member or Part Time Member who has held or is holding an office with any of the Private Universities establishes under the Act or Private Universities established outside the State of Chhattisgarh.
- (2) No person shall hold the office after the age of 70 years.
- (3) The Chairman or a Full-Time Member or a Part Time Member may resign his office by writing under his hand addressed to the visitor, and shall forward a copy of that resignation letter to the Higher Education Department.
- (4) If at any time upon representation made or otherwise it appears to the Visitor that the Chairman or Member;

A Member not getting pension shall be entitled for salary of Rs.18,400/- per month with Dearness Allowance and other allowances admissible for Class-I State Government Servants of the State Government.

- (14) The Full Time Member shall be entitled to House Rent Allowance (HRA) admissible as per Government of Chhattisgarh rules regarding House Rent Allowance for the time being in force and applicable to Class-I, State Government Servants, alongwith Telephones with STD facility in office and at his residence.
- (15) The Chairman and Full Time Members shall be entitled to 13 days casual leave and one month's earned leave/medical leave in one calendar year. Leave Record of the Chairman and the Full Time Members shall be kept in the office of the Regulatory Commission.
- (16) During travel for the work of the Regulatory Commission or the Government, Chairman and Full Time Members of the Commission would be entitled to Traveling Allowance and Dearness Allowance at the rates admissible and applicable to Class-I of State Government Servants, and in addition reimbursement of stay in a hotel categorized upto 3 Stars.
- (17). The Chairman and Full Time Members shall be entitled to such medical benefits as may be admissible for Class-I of State Government Servants of of Chhattisgarh or to Medi-claim in lieu thereof, as may be decided by the Education Department.

- (18). The Chairman and the Full Time Members shall not receive any retirement benefits such as pension, gratuity or both from the Regulatory Commission.
- (19). A Part Time Member shall be entitled to sitting fee of Rs.1,000/-per day and Traveling Allowance at the rates applicable at the time to Class-I of State Government Servants, and in addition, for the period spent on duty, reimbursement of stay in a hotel categorized upto 3 Stars.

15. Meeting of the Commission:- (a) The Regulatory Commission shall meet at such time and place as may be decided by the Chairman.
- (b) The Chairman and in his absence, senior most Full-Time Member /Part Time Member of the Commission shall preside over the meetings of the Commission.
- (c) All questions which come up before any meeting of the Commission shall be decided by a majority of the votes of the members present and voting.

If, no Member is appointed then Chairman shall decide the questions by passing Speaking Orders/Resolutions.

If the Chairman and only one Member is present in the meeting then decision shall be taken by Chairman by speaking orders after recording the views of the Member present in the meeting.

- (d) Minutes of every meeting of the Regulatory Commission shall be recorded by one of the Full Time Members of the Commission or by an officer of the Commission authorized for the purposes

by the Chairman. The minutes shall be validated by signature of the Chairman and shall be kept as a permanent record of the Regulatory Commission.

**16. Vacancy etc. not to invalidate the proceedings of the Commission:-**

No act or proceedings of the Commission shall be invalidated merely by reasons of :-

- (a) any vacancy in or any defect in the constitution of the Commission; or
- (b) any defect in the appointment of a person acting as a Member of the Commission; or
- (c) any irregularity in the procedure of the Commission, but not affecting the merits of the case.

**17. Temporary association of persons with the Commission for particular purposes:-**

(a) The Regulatory Commission may associate with itself any person whose assistance or advice it may desire in carrying out any of the provisions of the Act or rules made thereunder.

(b) A person associated with it by the Commission under Sub-section (a) for any purpose may be invited by the Commission to take part in the discussions relevant for the purpose, or in any meeting of the Commission in which the relevant purpose is included as an agenda item of the meeting of the Commission. But such person shall not have a right to vote at a meeting of the Commission and shall not be a member for any other purpose.

(c) A person associated with the Commission for the purpose of this rule 17 shall be paid a sitting fee of Rs. 500/- per day and

**Traveling Allowance at the rates admissible and applicable to  
Class-I Chhattisgarh State Government Servants for the time  
being in force.**

18. **Authentification of Orders and other instruments of the Regulatory Commission**:- All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the signature of the Secretary and till Secretary is appointed by the Chairman or any person authorized by the Chairman in this behalf, and all other instruments issued by the Commission shall be authenticated by a signature of the Secretary and till Secretary is appointed by the Chairman or any other person of the Commission authorized in a like manner in this behalf.
19. **Payment to the Commission**:- The Government of Chhattisgarh may, after due appropriation made by the State Legislative Assembly by law in this behalf, pay to the Regulatory Commission in each financial year such sums as may be considered necessary for the performance of functions of the Commission under the Act.
20. **Fund of the Regulatory Commission**:- (a) The Regulatory Commission shall have its own Fund and all sums which may from time to time be paid by the State Government and all the receipts of the Commission (including Endowment Fund, Additional Fund and any sum which any other authority or person may hand over to the Commission) shall be carried to the Fund, and all payments of the Commission shall be made therefrom.  
  
(b) All the money belonging to the Fund shall be deposited in a Scheduled Bank as defined in the Reserve Bank of India, Act, 1934 (No. 2 of 1934).  
(c) The Commission may spend such sum as it may think fit for performing its functions under the Act, and such sums shall be treated as an expenditure payable out of the Fund of the Regulatory Commission.

21. **Budget:-** The Regulatory Commission shall prepare in such form and at such time each year as may be decided by the Commission, a budget in respect of the financial year next ensuing showing an estimated receipts and expenditures and copies thereof shall be forwarded to the Education Department, with a view to obtain due appropriation by the State Legislative Assembly and payments thereafter of appropriated sums to the Regulatory Commission, as provided under rule 19 above.
22. **Annual Report:** The Regulatory Commission shall prepare once in every financial year, in such form and at such time as may be decided by the Commission, an Annual Report giving true and full account of its activities during the previous year and copies thereof shall be forwarded to the Higher Education Department. The Higher Education Department shall cause the same to be laid before the State Legislative Assembly.
23. **Account & Audit:-** (a) The Regulatory Commission shall cause to maintain such Books of Account and other account in relation to its account in such form and in such manner as may be decided by the Commission.  
(b) The Regulatory Commission shall, as soon as may be after closing its Annual Account, prepare a statement of account in such form and by such date as the Regulatory Commission may determine.  
(c) The accounts of the Regulatory Commission shall be audited by a Chartered Accountant immediately after closing of the financial year.  
(d) The accounts of the Regulatory Commission as certified by the Chartered Accountant together with the Audit Report

thereon shall be forwarded to the Higher Education Department and the Higher Education Department shall cause the same to be laid before the State Legislative Assembly.

**24. Staff, Accommodation and other Facilities of Regulatory Commission:**

- (a) The Regulatory Commission shall appoint on deputation or otherwise such number of officers and other employees as may be necessary for the purpose of enabling it to efficiently discharge its functions under the Act.
- (b) For its officers and employees, the Regulatory Commission shall take decision and accordingly acquire accommodation, equipments and other facilities as it may consider necessary.

**25. Relaxation of Rules:- On such matters which are not covered under these Rules, State Government may take decision on the basis of recommendation of the Regulatory Commission, which is supported by the Principle of Equity.**

**26. Laying of the Rules on the Table of the Legislative Assembly:- These Rules shall be laid on the Table of the Legislative Assembly.**

**27. Repeal and Savings:- The Chhattisgarh Niji Kshetra Vishwavidhyalaya Rules, 2004 and orders, resolutions, if any, in force immediately before the commencement of this Rule, are hereby repealed and rescinded as the case may be.**

Provided that any order made or action taken under these rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
G. D. GUPTA, Deputy Secretary.

ANNEXURE -A

**APPLICATION FORMAT FOR ESTABLISHMENT OF A PRIVATE  
UNIVERSITY IN THE STATE OF CHHATTISGARH**

( UNDER THE PROVISIONS GIVEN IN SECTION 4 OF THE CHHATTISGARH PRIVATE  
UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND OPERATION) ACT, 2005 )

<b>(1) Details of Sponsoring Body</b> (Detailed information given in section ..... of the Project Report.)	
(a)	Name
(b)	Address
(c)	Pin code
(d)	Telephone No. (with STD Code)
(e)	Fax No.
(f)	E-mail
<b>(2) Particulars of registration of the Sponsoring Body and its constitution and bye laws</b> (Detailed information given in section ..... of the Project Report.)	
(a)	the Sponsoring Body is a Registered Society under Chhattisgarh Society's Registrykaran Adhiniyam, 1973 ( No. 44 of 1973); or
(b)	Is a Public Trust; or
(c)	Is a Company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 ( No. 1 of 1956 ).
(d)	Whether the Sponsoring Body is a body which is not registered under any of the arrangements as provided under (a), (b) and (c) but is registered under another Act which is for the time being in force. If yes, give particulars of that Act.

	(e)	Attach certified copies of the Registration	
	(f)	Attach Constitution and Bye-laws	
(3)	Attach certified copies of the audited accounts of the Sponsoring Body for the past 3 years. (Detailed information given in section ..... of the Project Report )		
(4)	Information regarding financial resources of the Sponsoring Body (Detailed information given in section ..... of the Project Report )		
(5)	Name of the proposed University (Detailed information given in section ..... of the Project Report )		
(6)	Full address where the main campus of the proposed University to be established (Detailed information given in section ..... of the Project Report )		
(7)	Objectives of the proposed University: (Detailed information given in section ..... of the Project Report )		
(8)	Whether proposed University would demand minority status under Article 30 of the Constitution?, If yes, give details. (Detailed information given in section ..... of the Project Report )		
(9)	Whether the Main Campus of the University will be located in an area which is not a general area ? (Detailed information given in section ..... of the Project Report )		
	(a)	Whether the main campus of the University proposed to be established will be in a Scheduled Area? If yes, attach proof from the Competent Authority to the effect that the proposed location area is a Scheduled Area.	
	(b)	Whether the main campus of the University proposed to be established will be within the Municipal Corporation Limits of Raipur ? If yes, attach proof from the Competent Authority to the effect that the proposed location is within the Municipal Corporation Limits of Raipur	

(10)	Details about the land for the use of the proposed University. (Detailed information given in section ..... of the Project Report )		
	(a) Details of the land for full use of the University, if available on the date of application.		
	(i) Ownership of land ( with necessary proof)		
	(ii) Area of land		
	(iii) a map of the land		
	(b) Land that will be acquired after receipt of the Letter of Intent		
	(i) Ownership of land ( with necessary proof)		
	(ii) Area of land		
	(iii) a map of the land		
	(iv) Land will be acquired from whom ?		
	(v) Financial arrangement for acquisition of land.		
(11)	Details of campus development before the commencement of functions of the University. (Detailed information given in section ..... of the Project Report )		
	(a) Construction of buildings, development of structural amenities and infrastructural facilities		
	(b) Plan for procurement of equipments		
	(c) Outline of phase-wise programme for the coming 5 years.		

(12)	Details of phased outlays of Capital Expenditure proposed for 5 years and its sources of finance. (Detailed information given in section ..... of the Project Report )	
(13)	<b>Nature of faculties ( Name )</b> (Detailed information given in section ..... of the Project Report )	
(a)	Names of faculties like Science, Arts, Commerce, Technical Education, etc.	
(b)	Courses under each faculty like graduato, post-graduate, etc.	
(c)	Relevance of each course in the context of development of the State.	
(d)	Targeted students strength in each course	
(e)	Proposed phased programmes for courses for next 5 years.	
(f)	For each course, give information whether for starting it, prior approval from Central Regulatory Body or / and State Regulatory Body is necessary. If yes, give details of the same.  If prior approval has not been obtained, give details mentioning the provision under which Central / State Act, prior permission is necessary.	
(14)	Experience and expertise, (if any), in the concerned disciplines at the command of the Sponsoring Body. (Detailed information given in section ..... of the Project Report )	
(15)	Availability of academic facilities required for the courses of study and research. (Detailed information given in section ..... of the Project Report )	
(a)	Teaching Staff	
(b)	Technical and Non-technical Staff	

	(c)	Equipments and Laboratories	
(16)	Details about the expenditure on each of the proposed courses (Detailed information given in section ..... of the Project Report )		
	(a) Estimate of recurring expenditure		
	(b) Sources of finance		
	(c) Estimated expenditure per student		
(17)	Scheme for mobilizing resources (Detailed information given in section ..... of the Project Report )		
	(a) Cost of capital		
	(b) Manner of repayment		
(18)	Scheme for generation of funds internally from various sources (Detailed information given in section ..... of the Project Report )		
	(a) Fee from Students		
	(b) Consultancy Services		
	(c) Other activities relating to the objects of the Private University.		
(19)	Proposed fee structure for different Courses, Concessions, and Scholar-ships (Detailed information given in section ..... of the Project Report )		
	(a) For General Category		
	(b) For economically Weaker Sections		
	(c) For Scheduled Castes and Scheduled Tribes		
(20)	System proposed to be followed for admissions to the courses of study. (Detailed information given in section ..... of the Project Report )		

(21)	System proposed to be followed for appointment of Teachers and other Employees (Detailed information given in section ..... of the Project Report )		
(22)	Mode of imparting education (Detailed information given in section ..... of the Project Report )		
	(a)	Conventional Method	
	(b)	Distance Education Method	
	(c)	Both, as above	
(23)	In case Distance Education is proposed, then names of the proposed Study Centres and their details (Detailed information given in section ..... of the Project Report )		
(24)	Details of programmes related to local needs, nature of the specialized teaching, training and research activities. (Detailed information given in section ..... of the Project Report )		
(25)	Programmes for the benefit of Farmers, Women and Industries especially located in this State. (Detailed Information given in section ..... of the Project Report )		
(26)	Available or/ proposed other facilities :- (Detailed information given in section ..... of the Project Report )		
	(a)	Hostel facility for the students ( Boys / Girls)	
	(b)	Play grounds	
	(c)	National Cadet Corps, Scouts and Guides, National Service Scheme,etc.	
(27)	Details of the proposed Off-campus Centres and Study Centres in the Scheduled areas of the State. (Detailed information given in section ..... of the Project Report )		
(28)	Justification for the necessity of establishing the proposed Private University. (Detailed information given in section ..... of the Project Report )		

(29)	<p>If the Sponsoring Body had established erstwhile University, then full details giving number and date of the Notification regarding establishment and serial number in the Schedule - I of the Earlier Act. Also, mention whether Endowment Fund or / and Additional Fund was deposited or is in deposit ? If yes, then give full particulars with proof.  <small>(Detailed Information given in section ..... of the Project Report.)</small></p>													
(30)	<p><b>Details of application fee ( mention ) :-</b>  <small>(Detailed Information given in section ..... of the Project Report)</small></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; padding: 5px;">(a)</td> <td style="padding: 5px;">Amount in the crossed account payee demand draft</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">(b)</td> <td style="padding: 5px;">Name of the bank which has issued the demand draft.</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">(c)</td> <td style="padding: 5px;">Date and Number of the demand draft</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">(d)</td> <td style="padding: 5px;">Mention the name of the Sponsoring Body and the name of the proposed University on the back of the Demand Draft.</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table>		(a)	Amount in the crossed account payee demand draft		(b)	Name of the bank which has issued the demand draft.		(c)	Date and Number of the demand draft		(d)	Mention the name of the Sponsoring Body and the name of the proposed University on the back of the Demand Draft.	
(a)	Amount in the crossed account payee demand draft													
(b)	Name of the bank which has issued the demand draft.													
(c)	Date and Number of the demand draft													
(d)	Mention the name of the Sponsoring Body and the name of the proposed University on the back of the Demand Draft.													

The above application for establishment of \_\_\_\_\_ (mention name of the proposed University) under the provisions of Chhattisgarh Private Universities ( Establishment and Operation ) Act,2005 ( No. 13 of 2005 ) is submitted hereby on behalf of \_\_\_\_\_ (name of the Sponsoring Body). Detailed particulars of every point of this application is given in the Project Report. Detailed information may be seen in the Sections of the Project Report referred at every point.

I certify that :-

- (a) I am authorized to submit the application on behalf of the Sponsoring Body, \_\_\_\_\_ ( name of the Sponsoring Body ).

- (b) The Sponsoring Body has Resolved to establish a Private University by name of \_\_\_\_\_ and to follow in this connection all provisions made in the Chhattisgarh Private Universities ( Establishment and Operation) Act, 2005 ( No.13 of 2005 ) and such other rules as the State Government may make in this behalf, and has also Resolved to follow the instructions that will be issued by the Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission, from time to time. ( Attach a copy of the Resolution as Annexure )

Signature

Place : Name and Designation

Date : Name of Sponsoring Body  
Signature, name & address of 2 witnesses :-

(1)	Signature	
	Name	
	Address	

(2)	Signature	
	Name	
	Address	

Explanatory note for submitting application for establishment of a Private University

- (1) Before applying for establishment of a University in the State of Chhattisgarh in Private Sector, please read carefully the provisions made in the Chhattisgarh Private Universities ( Establishment and Operation ) Act 2005 ( No. 13 of 2005 ).
- (2) The Act and the Rules can be obtained in person from the Office of the Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission, 29/776, Plot No.5, Block No.3, Opp: Ram Mandir, Shantinagar, Madhu Pillai Chowk, Raipur : 492007 by producing a crossed Account Payee draft for Rs.500/- or by post by sending a crossed Account Payee draft for Rs.550/- in the name of the "Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission" payable in Raipur.
- (3) The Sponsoring Body or its Representative can seek guidance with regard to the establishment of the University from the Regulatory Commission. Guidance session shall be arranged only with prior appointment.

**ANNEXURE - B****APPLICATION FOR ESTABLISHMENT OF ENDOWMENT FUND****To**

**Chairman,**  
**Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission,**  
**RAIPUR, (C.G.)**

<b>(1)</b>	<b>Details of Sponsoring Body</b>	
(a)	Name	
(b)	Address	
(c)	Pin code	
(d)	Telephone No. (with STD Code)	
(e)	Fax No.	
(f)	E-mail	
<b>(2)</b>	<b>Name of the proposed Private University</b>	
<b>(3)</b>	<b>Full address where the main campus of the proposed Private University is to be established</b>	
<b>(4)</b>	<b>Location of Main Campus of the Private University.</b>	

	(a)	Whether the main campus of the University proposed to be established will be in a Scheduled Area ? If yes, attach proof from the Competent Authority to the effect that the proposed location area is a Scheduled Area.	
	(b)	Whether the main campus of the University proposed to be established will be within the Municipal Corporation Limits of Raipur ? If yes, attach proof from the Competent Authority to the effect that the proposed location is within the Municipal Corporation Limits of Raipur	

5.	Details of the Endowment Fund of the erstwhile University (mention) *		
	(a)	Name of the erstwhile University	
	(b)	Name of the Sponsoring Body of the erstwhile University	
	(c)	Notification Number and date under which erstwhile University was established.	
	(d)	Serial Number in Schedule – I of the earlier Act of the erstwhile University	
	(e)	Whether main campus of the erstwhile University was established in the Scheduled Area ?	

\* This information is to be furnished only by those Sponsoring Bodies which had established erstwhile University. Other Sponsoring Bodies may furnish NIL here.

	(f) Amount of Endowment Fund of the erstwhile University which is in deposit with the Regulatory Commission. ( give proof by attaching a photo copy of the Bank Pay-in-Slip).	
	(g) Net amount of the Endowment Fund that the Sponsoring Body proposes to deposit after adjusting the Endowment Fund of the erstwhile University, as provided in proviso to clause (b) of Sub-section (1) of Section 11 of the Act.	

(6)	Details of Endowment Fund (mention)	
	(a) Amount of Endowment Fund	
	(b) Bank Draft Number, full particulars about the name of the Bank including its Branch name, Branch Number and Branch Code which has issued the Bank Draft.	
	(c) Date of issue of Bank Draft	
	(d) Name & designation of the person who has sent the amount of the Endowment Fund on behalf of the Sponsoring Body	
	(e) On the back of the Demand Draft, mention the name of the Sponsoring Body and the name of the proposed University.	
(7)	Proof of opening the Savings Bank Account in the name of Sponsoring Body for depositing income from Endowment Fund	

	(a) Name of the Scheduled Bank and its branch in which the Savings Bank Account has been opened.	
	(b) Amount with which the Savings Bank Account has been opened. Attach photo copy of Deposit Slip issued by the bank as Annexure	
	(c) Name & Designation of the person who will operate the Savings Bank Account on behalf of the Sponsoring Body.	
	(d) Savings Bank Account Number and the date of establishment of this account.	
(8)	<b>Details of Letter of Intent (mention)</b>	
	(a) Number and date of issue	
	(b) Date of receiving by the Sponsoring Body	
	(c) Attach a photo copy of Letter of Intent	
(9)	(9) Any other information that the Sponsoring Body would like to provide or any request that the Sponsoring Body would like to make in the context of the establishment of the Endowment Fund.	

The above application for establishment of Endowment Fund for \_\_\_\_\_ (mention name of the proposed University) under the provisions of Chhattisgarh Private Universities (Establishment & Operation ) Act 2005 ( No. 13 of 2005 ) is submitted hereby on behalf of the \_\_\_\_\_ ( name of the Sponsoring Body) .

I certify that :-

- (a) I am authorized to submit the application for establishment of the Endowment Fund on behalf of the \_\_\_\_\_ ( name of the Sponsoring Body ).
- (b) The Sponsoring Body has Resolved to establish a Private University by name of \_\_\_\_\_ and to deposit Rs. \_\_\_\_\_ (Rupees \_\_\_\_\_ ) as Endowment Fund and to follow in this connection all provisions made in the Chhattisgarh Private Universities ( Establishment and Operation ) Act, 2005 ( No. 13 of 2005 ) and such other rules as the State Government may make in this behalf, and has also Resolved to follow the instructions that will be issued by the Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission, from time to time. ( Attach a copy of the Resolution as Annexure ).

Signature

Place : Name and Designation

Date : Name of Sponsoring Body

Signature, name & address of 2 witnesses :-

(1)	Signature	
	Name	
	Address	

(2)	Signature	
	Name	
	Address	

ANNEXURE - CCHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES REGULATORY COMMISSION . RAIPUR

Phone No.
Fax No.
E-mail
Date

No. Sub:- Certificate for the "Endowment Fund" deposited in the Account of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission, Raipur.

Ref:- See Section 11(1) of the Chhattisgarh Private Universities ( Establishment and Operation) Act, 2005.

Sl. No.	Name of the University	Reference of letter of Intent issued by Higher Education Department, Govt. of Chhattisgarh.	Area of the establishment of proposed Private University ( General / Scheduled Area	Amount	Particulars of Demand Draft deposited
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Place :

Date :

Signature

Name and Designation

Name of the Sponsoring Body ( with seal )



CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES REGULATORY COMMISSION, RAIPUR

**ANNEXURE - E**

ਲੁਚੀਸਾਨਾਹ ਰਾਮਪੜ, ਦਿਨਾਂਕ 16 ਦਿਸੰਬਰ 2005

624 (57)

No.	Sub:-	Statement of fees credited to the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh See Section 12 of the Chhattisgarh Private Universities ( Establishment and Operation) Act, 2005 ( No. 13 of 2005)
Ref:-		
Phone No.		
Fax No.		
E-mail		
Date		

Total of column 5 : (Rs.) \_\_\_\_\_ (In figures) ( Rupees )  
(1) Name of Person \_\_\_\_\_

- (1) Name of Payee : Government of Chhattisgarh , Raipur,  
 (2) Head under which the amount is to be credited in the Consolidated Fund of the State  
 (3) Name of the Treasury in which amount is deposited : \_\_\_\_\_  
 (4) No. of Account Payee Cheque  
 (5) Date of Issue of Cheque  
 (6) Name of the bank on which the Cheque is drawn  
 (7) Name and designation of the Officer of Revenue Commission sanctioning the Cheque

(1) Column No.4

(1) Signature  
Designation  
**Chhattisgarh Private Universities  
Regulatory Commission, Raipur**

Information about the fees collected in each month and sent to the Regulatory Commission is contained in the Form. Information for every month in the Form shall be numbered by the concerned University as Statement Number. Private University shall also mention the year. This statement number and year should be mentioned in this column in the office of the Regulatory Commission.

Name and designation of the Officer of Regulatory Commission signing the Cheque

mission signing the Cheque

**ANNEXURE -F****CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES REGULATORY COMMISSION, RAIPUR**

Sub:- Statement of Penal Interest credited to the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh  
 Ref:- See Section 12 of the Chhattisgarh Private Universities ( Establishment and Operation) Act, 2005 ( No. 13 of 2005).

No	Sl. No.	Name of the University	Resolution Number of the Regulatory Commission ampowering to impose and collect the penal interest	Amount	Remarks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total of column 4 : (Rs.) _____ (in figures) ( Rupees _____ ) (in words)					
(1)	Name of Payee : Government of Chhattisgarh , Raipur.				
(2)	Head under which the amount is to be credited in the Consolidated Fund of the State _____				
(3)	Name of the Treasury in which amount is deposited :				
(4)	No. of Account Payee Cheque				
(5)	Date of issue of Cheque				
(6)	Name of the bank on which the Cheque is drawn				
(7)	Name and designation of the Officer of the Regulatory Commission signing the Cheque				

(1) Signature  
 Designation  
 Chhattisgarh Private Universities  
 Regulatory Commission , Raipur

‘प्रियोनी एस्टेर से असाधारण तृष्णा के  
वह मुख्यतः (विवा वाक दिवं) में वेष्ट  
हैं, जिनमें अमावस्या ३०-१२-२०१४  
मध्य / ११ बि. से. विशेष, विवाह  
३०-१२-२०१४।’

प्रतीक्षा प्रमाण  
“प्रसीदित/पुर्ण/०३/२०१२-२०१५。”



## छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

दिनांक ८३ ]

लखनऊ, उत्तराखण्ड, दिनांक २१ अक्टूबर २०१४— भाग ३०, क्र. १९३६

विधि और विधायी कार्य विभाग  
संचालन, महाकाशी भवन, नया शहर।

लखनऊ, दिनांक २१ अक्टूबर २०१४

उल्लंघन ७२६७ / वी. १३६/११-३६/वार्ष./०. ८/१४ — उल्लंघन विभाग द्वारा की विवरिति अधिकारी विवाह प्रक्रिया १५-०९-२०१४  
की शरणार्थी की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, उल्लंघन विभाग की अनुसूची के लिए अवशिष्ट विवाह जाता है।

उल्लंघन विभाग के शरणार्थी के नाम से तथा अधिकारी,  
सुनाम सरकार, अधिकारी गवर्नर,

ହୃଦୀମାର୍ଗରୁ ଅଧିନିୟମ  
(ପରୀକ୍ଷା ୧୩ ଲ୍ୟାଙ୍କ ୨୦୧୫)

छत्तीसगढ़ निवड़ी विकासनिधालय (स्थापना एवं संचालन) (संकोषित)  
अधिनियम, 2014

कालीगढ़ निवासियों का (प्रधानमन्त्री संचयन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 मर, 2005) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

प्राप्त लक्षणों के देखते ही वर्ष में लग्नीसाइट विकासमाधार द्वारा नियन्त्रित रूप में यह अधिनियमित हो

विविध नाम, विस्तृत ज्ञान ।	(1) पह अभियान उत्तीर्ण निरी विश्वविद्यालय (यांत्रज्ञान एवं संकाय) (संकेत) अभियान, 2014 के द्वारा।
	(2) इसके विस्तृत विवरण एवं विवरण द्वारा दी गई।
	(3) पह अभियान में फैले उत्तरार्थ की तात्पुरता से प्रहृत होता।
पर्याय का संदर्भ:	<p>प्राचीनमात्र निरी विश्वविद्यालय (यांत्रज्ञान एवं संकाय) अभियान, 2015 (पर्याय 1) ने इसमें इसके विवरण एवं अधिकारियों के नाम में निर्दिष्ट है) की पात्र १ की उप-पात्र (2) के विवरण, विवरिति और संबंधित विवरण आये, असौं।-</p> <p>"(2) उप-पात्र (2) में अधिक विविध काम के द्वारा दी गई एवं इस पात्र की उप-पात्र (1) के अंतर्गत विवरित विवरण एवं संकाय द्वारा यात्रा, यात्रा कार्यक, यात्रा विवरण एवं उप-पात्र (1) की विवरण का संलग्न हो।"</p>
अनुसूची का संदर्भ:	पूर्ण अभियान की अनुसूची में, सत्र अनुसंधान ३ के विवरण, विवरिति विवरण तात्पुरता एवं उपर्याय संबंधित विवरण आये, असौं।-

मा. क्र. निरी विवरणात्मक	प्रादौतक विकास	प्रादौतक विकास की वाय	मुख्य विकास	संदर्भिका	विभिन्न संघर्ष	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

<b>६</b> <b>पर्यावरण विभाग</b>	<b>भी फिल्म कलेज</b> <b>इंडिपेंडेन्ट फ़िल्म कलेज</b> <b>फ़ारमार्केट</b>	<b>सोनारगढ़ी पर्यावरण</b> <b>अवैज्ञानिक, १९८०</b> <b>(१९८० का स. २)</b> <b>पर्यावरण, अ. १०-</b> <b>२०६५ तथा १९९६,</b> <b>विशाख १९-१२-१९९६</b>	<b>प्रश्न-उत्तर</b> <b>तापमीठ-विष्णु</b> <b>विला-संपूर्ण</b> <b>कर्मसुख</b>	<b>सारीसंग्रह</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● वर्ण.</li> <li>● विष्ण.</li> <li>● विला,</li> <li>● इतिहासिया,</li> <li>● वैदे-टेक्नोवैदी,</li> <li>● वाक्यालंगाप्रय.</li> <li>● विदी,</li> <li>● इंद्र देवेश्वरी,</li> <li>● विला विष्णविज,</li> <li>विष्ण ते वाक्या, वाक्योत्ता</li> <li>वा उन्होंने वाक्यालंगा,</li> <li>वर, विष्ण, विला, वी. और</li> <li>अन्य अनुभाव वाक्यालंगा।</li> </ul>
-----------------------------------	---	--	--	-------------------	--

छत्तीसगढ़ राज्य, १४०६/२३/२०१४						
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)
७.	श्री. डॉ. विजय किशन एम्प्रेस कृष्णपुरी संस्थानी	एम्प्रेस कृष्णपुरी संस्थानी	चलोलन संस्थानी, परिवहन अधिकारी, १९७३। (उमेर ४४ वर्ष) १९७३) प्रीप्रिय कामल श्री. पूर्ण २१३, लिंगम ४-५-१९९८	श्री. डॉ. विजय कृष्णपुरी संस्थानी, १९७३। (उमेर ४४ वर्ष) १९७३) प्रीप्रिय कामल श्री. पूर्ण २१३, लिंगम ४-५-१९९८	चलोलन संस्थानी कामल पाठी, १९७३। (उमेर ४४ वर्ष) १९७३) प्रीप्रिय कामल श्री. पूर्ण २१३, लिंगम ४-५-१९९८	<ul style="list-style-type: none"> <li>• इमोरियर एवं ट्रेनिंग संकाय,</li> <li>• प्रीप्रिय कृष्णपुरी संकाय,</li> <li>• विजय कृष्णपुरी संकाय,</li> <li>• विजय कृष्णपुरी संकाय,</li> <li>• विजय कृष्णपुरी संकाय,</li> <li>• विजय कृष्णपुरी संकाय</li> </ul>

लखनऊ, दिनांक ११ जून २०१४

५५६

लखनऊ/वी. १३६/११-३८/३०८/०८. ८/१४ — मान से विविध के अनुमोद ३४६ के द्वारा (१) के अनुसार दो छातीसगढ़ विश्वविद्यालय (प्राचीन एवं संस्कृत) (प्रोफेसन) अधिकारी, २०१४ (लखनऊ/१३६८/०८. ८/१४) का अंतिम प्रमुख प्रबन्धन के विविध संकाय  
प्रबन्धन के विविध संकाय के नाम पर नाम बदलावामा,  
कृपया सम्मेलन अधिकारी विविध

CHHATTISGARH ACT  
(No. 13 of 2014)

THE CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND  
OPERATION) (AMENDMENT) ACT, 2014

An Act to further amend the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-fifth Year of the Republic of India, as follows:

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) (Amendment) Act, 2014.  
Short title, extent and commencement.
  - (2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.
  - (3) It shall come into force from the date of its Publication in the Official Gazette.
2. After sub-section (2) of Section 9 of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005) (hereinafter referred to as the Principal Act), the following shall be inserted, namely :—  
Amendment  
Section 9.

"(2A) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), to establish a private university under sub-section (1) of this Section, the State Government may also consider any application submitted before the period of more than two years."

Annexure  
Schedule. of ३. In the Schedule to the Principal Act, after serial number 5, the following serial number and entries relating thereto, shall be added, namely :—

S. No.	Name of the Private University	Name of the Sponsoring body	Procedure of Establishment of Sponsoring body	Main Campus (Head office)	Jurisdiction	Teaching Programmes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
६.	Amity University	Shri Rishabh Baldev International Education Foundation	The society Registration Act, 1860 (No. 21 of 1860) Registration No. S-30655 of 1996, dated 19-12-1996	Village-Masti Tahsil-Tilda District-Raipur Chhattisgarh	Chhattisgarh	Under Graduate, Post Graduate and their integrated courses, M.Phil., Ph.D. and other research courses in— ● Arts, ● Science, ● Commerce, ● Engineering, ● Nano-technology, ● Business Management, ● Law, ● Hotel Management, ● Fashion Designing
७.	O.P. Jindal University	Jindal Education and Welfare Society	The Chhattisgarh Knowledge Society Registration Act, 1973 (No. 44 of 1973), Registration No. B. S. 2171, dated 4-5-1998	O. P. Jindal Knowledge Park,Village- Punipathea, Tehsil- Gharghoda, District- Raigarh Chhattisgarh	Chhattisgarh	● Faculty of Engineering & Technology, ● Faculty of Management Science, ● Faculty of Science, ● Faculty of Education, ● Faculty of Physical Education"

“विजेता योग के अन्तर्गत द्वारा सुनके  
नए मुद्राल (विजेता योग) के द्वेष  
हेतु अनुसन्धान अधीक्षण नं. १२-११-प्राप्तिग्राह्य  
योग / ३६ नि से. मित्रां, विनाक  
३०-४५-१००।”



प्रतिवेदन क्रमांक  
“प्राप्तिग्राह्य/पुर्ण/०९/२०१५-२०१५。”

## छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

प्रकाशन २५४

लारपु, बुकारा, विनाक १५ मार्च २०१५ — विनाक १५, वर्ष १९३७

विधि और विधायी कार्य विभाग  
मंत्रालय, महानगरी भवन, लखनऊ

लारपु, विनाक १४ मार्च २०१५

असाक ४५६१/हें. १५४/२१-३८/प्राप्त./क.न./१५ — उत्तीर्णाय लिखा एवं प्राप्ति विभाग अधिकारियम विनाक विनाक ०१-०५-२०१५ की  
नज़ारात की प्रकृति प्राप्त हो चुकी है, एवं इस नामांकनात की जावाहरी के लिए प्रकाशित विया जाता है।

उत्तीर्णाय के प्राप्तिग्राह्य के बास से लगा आवेदनमुद्दा,  
कुमार मालव, असाधारण विनाक,

उत्तीर्णमध्य अधिनियम  
(क्रमांक २१ ई० २०१५)

**उत्तीर्णमध्य निझी विवाहितालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन)  
अधिनियम, २०१५**

उत्तीर्णमध्य निझी विवाहितालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २०१५ (क्र. १३ मा०, २०१५) को और संशोधन बताने हेतु अधिनियमः

प्रधान नियमको द्वितीयांशे वर्ष में उत्तीर्णमध्य निझी विवाहितालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, २०१५

- |                                 |    |  |
|---------------------------------|----|--|
| संशोधन नाम, विवाह<br>एवं संचालन | १. | (१) यह अधिनियम उत्तीर्णमध्य निझी विवाहितालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, २०१५ का संशोधनः   |
|                                 |    | (२) इसका विवाह रामदूर्ग उत्तीर्णमध्य राज्य पा० हुआ।  |
|                                 |    | (३) यह उत्तीर्णमध्य निझी विवाहितालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २०१५ (क्र. १३ मा०, २०१५) को और संशोधन को इसमें विस्तृत रूप से व्युत्पन्न किया गया है।  |
| प्रधान १ का संशोधनः             | २. | उत्तीर्णमध्य निझी विवाहितालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २०१५ (क्र. १३ मा०, २०१५) (की इसमें इसके प्रधान का अधिनियम के रूप में विविध है) की प्रधान १ की ३०-प्रापा (३) में, जहाँ “२५,०००” के स्थान पर, भेद “१,००,०००” प्रतिशतांश दिया गया। |
| प्रधान १ का संशोधनः             | ३. | (१) मूल अधिनियम की प्रधान १ की उप-प्रापा (१) के प्रधान (५) में, जहाँ “दूसरे कठोड रूपों” के स्थान पर, जहाँ “नीन कठोड रूपों” प्रतिशतांश दिया गया।  |
|                                 |    | (२) मूल अधिनियम की प्रधान १ की उप-प्रापा (१) के प्रधान (७) में, जहाँ “नीन कठोड रूपों” के स्थान पर, जहाँ “नीन कठोड रूपों” प्रतिशतांश दिया गया।  |

रायगढ़, विवाह, १५ मार्च २०१५

क्रमांक ४५६२/वी. १३४/२१-४/२०१५/०३.०३./१५. — आज के विवाहितालय के अनुसंधान ३४८ के घटाव (३) के उत्तरावाह में ३८ विभाग की समांगता, अधिनियम विवाह, १५-०३-२०१५ का अंतीम अनुप्रयत्न संबोधन के विविधांश संलग्नता द्वारा जमा है।

उत्तीर्णमध्य के विवाहितालय के नाम से लक्ष्य आदेशमुग्धा,  
सुनमा रामदूर्ग, अंतीम अनुप्रयत्न संबोधन।

CHHATTISGARH ACT  
(No. 21 of 2015)THE CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES  
(ESTABLISHMENT AND OPERATION) (AMENDMENT) ACT, 2015

An Act further to amend the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows :-

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | (1) This Act may be called the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) (Amendment) Act, 2015.<br><br>(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.<br><br>(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.  | <i>Short title, extent and commencement.</i> |
| 2. | In sub-section (3) of Section 7 of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005), (hereinafter referred to as the Principal Act), for the figure "25,000", the figure "1,00,000" shall be substituted.   | <i>Amendment of Section 7.</i>               |
| 3. | (1) In clause (a) of sub-section (1) of Section 11 of the Principal Act, for the words "One crore rupees", the words "Three crore rupees" shall be substituted.<br><br>(2) In clause (b) of sub-section (1) of Section 11 of the Principal Act, for the words "Three crore rupees", the words "Five crore rupees" shall be substituted. | <i>Amendment of Section 11.</i>              |

“विसरन यात्रा के अन्तर्गत दुष्कृति के काब मुक्ति। विना वाह दिवां के अपरा ही अमृत व्रतम् यो १-२-३-एकीमय दद्दि ३५ वि से विनाह विनाह ३१-३२-३८०।”



पर्याप्त नहीं  
उत्तमीनमात्रा/पृष्ठे/09/2018-19  
अधिकारी का दस्तावेज़ 31/10/2014

23477-  
72110114. - 42167-81244

31-X-11

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)  
धिकार से प्रकाशि

卷四五 49

नवायन लैप्टॉप फिरोज़ाबाद २०१४— अंग्रेजी संस्कृति

## उच्च शिक्षा विभाग

thus leads to figure 2a.

ब्रॉडकॉम १५३-६ / २०१२/३०-८ — इन्डिया रिपोर्टिंग सेवायर (भारत का संसाक्षण) अधिकारीया २०१३ (के १३ जून २०१३) की पात्रा ४२३० प्रत्याग्रहणीय प्राप्ति में लिखा हुआ एक विवरण, जिसमें इन्डिया रिपोर्टिंग सेवायर (भारत का संसाक्षण) के द्वारा २०१२ में उपलब्ध किया गया और विवरणीय होना चाहिए।

五

五  
五

- १ विषय १२ के उत्तर-विषय (११) है। अब, इसे एक विषय हो गया (१०३८)। “के स्थान पर, जल एवं अम्” ६. २१८। प्रश्नपत्रिका विषय आवं  
 २ विषय १२ के उत्तर-विषय (११) है। अब, इसे एक विषय हो गया (१०३८)। “के स्थान पर, जल एवं अम्” ६. २१८। प्रश्नपत्रिका विषय आवं

पंजीयन के दूसरात्र के नाम से जय आदित्यमुख,

卷之三

उमा भट्ट ५-६/२०१२/३८-२ — भट्ट के संविधान के अनुसार ३४८ के मुद्रण (३) के अनुसार से, इस विधायक की अधिकृतता कमाल है। ५-६/२०१२/३८-३, विधायक १८-६८-२०१४ को अपेक्षी प्रजातांत्रिकाके प्रतिवक्ष से उपलब्ध प्रकाशित किया जाता है।

एन्सीसीएसटी के लकड़ावाल के नाम से जाना जाता है।

---

Raipur, the 16th September 2014

**NOTIFICATION**

No. F-5-6/2012/38-2 In exercise of the powers conferred by Section 42 of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005) the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Rules, 2005, namely:-

**AMENDMENT**

In the said rules:-

1. In sub-rule (19) of rule 14, for the word, figure and symbol "Rs. 1000/-", the word and figure "Rs. 2000" shall be substituted.
2. In clause (c) of rule 15, for the word, figure and symbol "Rs. 500/-", the words and figure "Rs. 1000" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
M. L. GUPTA, Deputy Secretary

